



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 22, 1993/ज्येष्ठ 1, 1915

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 22, 1993/JYAISTHA 1, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than
Ministry of the Defence)

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1993

New Delhi, the 24th February, 1993

का.प्रो. 1001.—केंद्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों को फेरबदल) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19-11-92 से श्री वेद प्रकाश भाटिया, सहायक निदेशक के स्थान पर श्री पी. दामोदरन, सहायक निदेशक, तमनुपंगो आसूचना ब्यूरो मुंबई को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है और यह निर्देश देती है कि उक्त अधिकारी, उप-निदेशक तमनुपंगो आसूचना ब्यूरो मुंबई के निमंत्रणाधीन सभी सरकारी वास-सुविधा के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा।

[सं. 1/सी-2/78(जे) जन./एफ.पी. वी-988]

वी. के. पिपरसेनिया, उप सचिव

S.O. 1001.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (eviction of unauthorised occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government, hereby appoints Shri P. Damodaran, Asstt. Director, Subsidiary Intelligence Bureau, Bombay, being a Gazetted Officer of the Government, to be the Estate Officer in place of Shri Ved Prakash Bhatia, Asstt. Director w.e.f. November 19, 1992 for the purposes of the said Act and directs that the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties, imposed on the Estate Officer by or under the said Act, in respect of all Government accommodation under the control of the Deputy Director, SIB Bombay.

[No. 1/C-II/78(J)-Genl/FP. V-988]

V. K. PIPERSENIA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1993

आयकर

का.आ. 1002.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "आर्च डायोसेस ऑफ त्रिवेंद्रम, केरल" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 में 1988-89 तक के लिए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 9211/फा. सं. 197/34/89-आयकर. (नि.1)]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 16th February, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 1002.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Arch Diocese of Trivandrum, Kerala" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1987-88 to 1988-89.

[Notification No. 9211/F. No. 197/34/89-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1993

आयकर

का.आ. 1003.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्री 108 श्री प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट, धाम, पन्ना, मध्य प्रदेश के कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (2) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार प्राप्त लाभ तथा अधिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक

नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9213/फा. सं. 197/36/92-आयकर-नि-1]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 16th February, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 1003.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri 108 Shri Prannath Ji Mandir Trust, Dham, Panna, M.P." for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9213/F. No. 197/36/92-ITA-II]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1993

आयकर

का.आ. 1004.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "मुन्दरम् चेरिटीज, नद्रास" को कर निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (2) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा।

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9238/फा.सं. 197/117/92-आयकर-नि-1]

शरतचन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 1004.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sundaram Charities, Madras" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-94 to 1995-96 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9238/F. No. 197/117/92-ITA-I]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1993

(आयकर)

का.आ. 1005.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्री सिद्धि विनायक गणपति टेंपल ट्रस्ट, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(2) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जैवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

[अधिसूचना सं. 9240/फा. सं. 197/140/92-आयकर-नि-1]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 1005.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shree Siddhi Vinayak Ganapati Temple Trust, Bombay" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1989-90 to 1991-92 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9240/F. No. 197/140/92-ITI-II]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1993

(आयकर)

का.आ. 1006.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "महानिर्वाण मठ, बीरभूम, पश्चिम बंगाल" को कर-निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (1) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए

इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है।

- (2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों की किसी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर, जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा।
- (3) यह अधिसूचना किसी सीए आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि, ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों?

[अधिसूचना सं. 9197/फा.सं. 197/8/93-आयकर नि-1]

शरत चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th February, 1993

(INCOME-TAX)

S.O. 1006.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Mahanirvan Math, Birbhum, West Bengal" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely :

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 9197/F. No. 197/8/93-ITA-1]

SHARAT CHANDRA, Under Secy.

महानिदेशक (आयकर छूट) का कार्यालय

कलकत्ता, 8 मई, 1992

(आयकर)

का.आ. 1007—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35

(पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगी।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने व्यय, प्राप्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

जवाहरलाल नेहरू सेंटर फार अड्वान्स साइंटिफिक रिसर्च, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक कम्पास, बेंगलूर-560012

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 652/फा.सं. डी जी/के टी 30/कल 35/1/II/90
आ.क. (छूट)]

ए.के. विद्याम, उप निदेशक

(Office of the Director General of Income Tax Exemption)
Calcutta, the 8th May, 1992

(INCOME-TAX)

S.O. 1007.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific and Industrial Research for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category Association subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure of the assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Jawaharlal Nehru Centre for Advance Scientific Research,
Indian Institute of Science Campus Bangalore-560 012.

This notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

NOTE :—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 652/F. No. DG/KT-30/Cal. 35(1)(ii)/90.IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 8 मई, 1992

(आयकर)

का.आ. 1008.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 पेंतीस/एक/दो/की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा

निम्नलिखित शर्तों पर संघ प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यक्रमों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने ध्येय आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

रमण रिसर्च इंस्टीट्यूट,
सी. बी. रमण एवेन्यू,
सदाशिवनगर, बेंगलूर-560080

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रार्थियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[ए. 653/का सं. डी. जी. /के. टी. 16/कल. /35 1(ii)/90.
आ. क. (छूट)]

ए. के. विश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 8th May, 1992
(INCOME-TAX)

S.O. 1008.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purpose of clause (ii) of sub-

section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category Association subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each years a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure of the assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Raman Research Institute,
C. V. Raman Avenue
Sadashivanagar,
Bangalore-560080.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

NOTE :—The organisation is advised to apply (in triplicate for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 653/F. No. DG/KT-16/Cal. 35(1)(ii)/90-IT(E)]

A. K. BHASWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 8 मई, 1992

आयकर

का.प्र. 1009.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद् द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैतीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव

वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपने-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान,
विवेकानन्द इंस्टीट्यूट आफ मैडिक साइंसेस
99, शरत बोस रोड,
कलकत्ता-700026

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 654/फा.सं.डी.जी./डब्ल्यू.बी. 6/कल./35/(1)
(ii)/89-आ. कर (छूट)]

ए.के. विश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 8th May, 1992

(INCOME-TAX)

S.O. 1009.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category Institution subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of the audited annual accounts showing its income and expenditure of the assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Rama Krishna Mission Seva Pratishthan Vivekanda Institute of Medical Sciences,
90, Sarat Bose Road,
Calcutta-700026.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1993.

NOTE :—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 654/F. No. DG/WB-6/Cal/35(1)(ii)/89-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 8 मई, 1992

(आयकर)

का.आ. 1010:—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैसीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई, तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-व्यय, भास्तिनों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

किंग एडवार्ड VIII मेमोरियल हास्पिटल एण्ड सेठ जी. एस. मेडिकल कालेज रिसर्च सोसाइटी,
31 के. इ. एम. हास्पिटल,
बम्बई-400012.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी: संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने, के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 655/फा. सं. डी. जी./एम-85 कल./35(1) (ii)
90 आ. कर. (छूट)]

ए. के. विश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 8th May, 1992

(INCOME-TAX)

S.O. 1010.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules 1962, i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category Institution subject to the following conditions :

(i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research.

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure of the assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

King Edgnd VII Memorial Hospital & Seth G. S. Medical College Research Society,
31, K. G. M. Hospital,

Bombay 400012.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1993.

NOTE :—The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 655/F. No. DG/M-85/Cal/35(1)(ii)90-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 8 मई, 1992

(आयकर)

का.आ.1011.—सर्व साधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैटीस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति अपनी-जय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बै आई रिसर्च फाउंडेशन (रजि.)

विजया हस्पिटल,

180, एन. एस. के. सलाई, ववापलानि,

मद्रास-600026,

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 656 (फा. सं. डी. जी./टी. एन. 21/कल./35 (1) (ii)/89 आ. कर. (छूट)]

ए. के. बिश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 8th May, 1992

(INCOME-TAX)

S.O. 1011.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category Association subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year, and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure of the assets and liabilities,

NAME OF THE ORGANISATION

संगठन का नाम

The Eye Research Foundation (Regd.),

Vijaya Hospital

180, N.S.K. Salai Vadapalani,

Madras-600026.

अमला कैंसर रिसर्च सेंटर, त्रिचुर,
अमलानगर-680553, केरल, भारत।

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक
अवधि के लिये प्रभावी है।

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 656/F. No. DG/TN-21/Cal/35(1)(ii)89]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 11 मई, 1993

आयकर

का. आ. 1012.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (पैतीम एक/दो/तीन) की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान/संघ" प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहां अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी है।

[सं. 657 /फा. सं. डी. जी/के-9/कल. 35/(1) (ii)/90-
आ. कर (छूट)]

ए० के० विश्वास, निवेशक

Calcutta, the 11th May, 1992
INCOME-TAX

S.O. 1012.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e., the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category Association subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year, and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure of the assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Amala Cancer Research Centre, Trichur,
Amatanagar-680553, Kerala, India.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1993.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions),

Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 657/F. No. DG/K-9/Cal./35(1)(ii)/90-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 11 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1013.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (पैरिस/एक/दो) की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की सहमति से, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी अर्थात् महानिदेशक (आयकर छूट) द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक, लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति आय-व्यय, आस्तियों एवं देनदारियों के विवरण सहित, (क) महानिदेशक (आयकर छूट); (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेन्ट्रल पावर रिसर्च, इन्स्टिट्यूट,
पोस्ट बाक्स-1242,
बंगलूर-12

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक की अवधि के लिये प्रभावी है।

टिप्पणी : संगठन को अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन की समाप्ति के तीन माह पूर्व आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार

में संगठन में पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करने के लिए सुझाव दिया जाता है। विशेष मामलों में, जहाँ अनुमोदित आदेश उपर्युक्त तीन माह की समाप्ति पर अथवा उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पूर्व प्राप्त हुआ हो, संगठन अनुमोदित आदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करें। अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 658 (फा सं डी. जी./के. टी.-17/कल./35(1)/(ii)/90 आ. कर (छूट)]

ए.के. विश्वास, उप निदेशक

Calcutta, the 11th May, 1992

INCOME-TAX

S.O. 1013.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 i.e. the Director General of Income-tax (Exemptions) in concurrence with the Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty Five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 under the category Institution subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain a separate account of the sums received by it for Scientific Research;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, “Technology Bhawan”, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year, and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 30th June each year a copy of its audited annual accounts showing its income and expenditure of the assets and liabilities.

NAME OF THE ORGANISATION

Central Power Research Institute,
Post Box 1242, Bangalore-12.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1993.

NOTE : The organisation is advised to apply (in triplicate) for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, three months before the expiry of the approval. In exceptional cases where the order granting approval is received after the expiry of the period of three months aforesaid or shortly before the expiry of the said period, the organisation may make an application for extension of approval as soon as possible after the receipt of the order of approval. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 658/F. No. DG/KT-17/Cal/35(1)(ii)/90-IT(E)]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 11 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1014:—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर 'संघ' प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग 'औद्योगिक भवन' न्यू मेहरोली रोड नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रिया-कलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम -

थापर कारपोरेट रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट सेन्टर,
पोस्ट बक्स नं 68 पाटियाला-147001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1, उपर्युक्त शर्त (1) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं० 659(फा० सं० डी० जी०/आ० कर (छूट)/वो०-1/
कल०/35(i)(ii)/90-91]

ए.के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 11th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1014.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and

- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Thaper Corporate Research & Development Centre,
Post Box No. 68,
Patiala-147001,

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-95.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 659 (F. No. DG/IT(E)/P-1/Cal/35(i)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 11 मई 1992

आयकर

का.आ. 1015:—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर 'संघ' प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'औद्योगिक भवन', न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर

महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रियाकलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

मुकुन्द फाउन्डेशन फॉर एग्रिकल्चरल रिसर्च, 8-बी, इज़ पेगसवे, आर. एम. पुरम, कोयम्बटोर

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-90 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 660/फा.सं.डी.जी./आ. कर. (छूट) टी. एन.-16/कल./35(1)(ii)/90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 11th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1015.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Mukund Foundation for Agricultural Research, 8-B, Ease Perlasamy,

R-3, Puram, Coimbatore-2.

This Notification is effective for the period from 1-4-90 to 31-3-93

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 660/F. No. DG/IT(E)/TN-16/Cal/35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 15 मई, 1992

(आयकर)

का.आ. 1016—सर्वसाधारण को सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के लिये, आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संस्थान प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'औद्योगिक भवन' न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रियाकलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

चारुतर आरोग्य मण्डल मेडिकल रिसर्च सोसाइटी, बल्लभ विद्यानगर, 388120, जिला खेडा (गुजरात)।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी 1. उपर्युक्त शर्त (1) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 661/फा.सं.डी.जी.आ.कर (छूट)/जी-13/कल./35(1)
(ii)/90-91]

ए. के. बिश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 15th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1016.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Charutar Arogya Mandal Medical Research Society,
Vallabh Vidyanagar-388120,
District Kheda (Gujarat).

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-93.

Notes:

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 661/F. No. DG/IT(E)/G-13/Cal-35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 15 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1017—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर 'संव' प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष को 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष को 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त, और (ग) आयकर आयुक्त, आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(i) में दी गई रिसर्च क्रिया-कलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

दी सोसाइटी फार रिसर्च ऑन हेमाटोलाजी एण्ड ब्लड ट्रान्सप्लान्त, 75/सी, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता - 700016

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-94 तक की अवधि के लिये प्रभावी है:

टिप्पणी 1 (1) उपर्युक्त (i) 'संव' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आय महानिदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 662/फा.सं.डी.जी.आ.कर(छूट)/डब्ल्यू.डी.13/कल./35(i)
(ii)/90-91]

ए. के. बिश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 15th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1071.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

The Society for Research on Hematology & Blood Transfusion,

75/C, Park Street,

Calcutta-700016,

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-94.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 662/F. No. DG/IT(E)/WB-13/Cal/35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 15 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1018—सर्वसाधारण को सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संस्थान प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक

वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष को 31 अक्तूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रिया-कलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी आन्ट्रप्राइस पार्क, गुरु नानक इंजिनियरिंग कालेज, लूधियाना-141006

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-90 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी 1. उपर्युक्त शर्त (i) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 663/फा. सं. डी जी/आ.कर (छूट) पी-5 कल/35 (i)(ii)/90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 15th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1018.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by

the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Science & Technology Entrepreneurs Park,

Guru Nanak Engineering College,

Ludhiana-141006.

This Notification is effective for the period from 1-4-90 to 31-3-93.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 663/F. No. DG/IT(E)/P-5/Cal/35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 15 मई, 1992

(आयकर)

का. आ. 1019—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, आयकर निगम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संध प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्ति धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष को 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष को 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके-क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च क्रिया-कलाप, सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

कानकेस्ट जैन मेडिकल रिसर्च सोसाइटी, 8/10
निकादवारी, लेन कण्डेवादी, बम्बई 400004

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संध" जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 664/का. सं. डी. जी/आयकर (छूट)/एम 30/
कल/35(1)(ii) 90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 15th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1019.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Conwest Jain Medical Research Society,
8/10, Nikadwari Lane, Kandewadi,
Bombay-400004.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-93.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 664/F. No. DG(IT)(E)/M-30/Cal/35(i)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 15 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1020—सर्वसाधारण की सूचना के लिये
एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्न-
लिखित संसद को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा
35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये
आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित
प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संस्थान प्रवर्ग के
अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन
के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों
का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक
वर्ष को 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक
अनुसंधान विभाग औद्योगिक भवन न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली
110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष को 31 अक्टूबर तक लेखा-
परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक
(छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और
(ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके
क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधि-
नियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रिया-
कलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखापरीक्षित आय-
व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

स्पैस्टिक सोसाइटी आफ इण्डिया, अपर कोलाबा
रोड, अपर कोलाबा चर्क, कोलाबा, बम्बई—400005।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-93
तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा प्रवर्ग के
लागू नहीं होगा।

2. संगठन को मुझाव दिया जाता है कि के अनुमोदन
की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/
आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में
संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक
(छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन

करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध
में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को
प्रस्तुत करना है।

[सं. 665/का. सं. डी. जी. /आ. कर (छूट)/एम

52/कल/35(1)(ii) 90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 15th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1020.—It is hereby notified for general information
that the organisation mentioned below has been approved by
the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax
Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of
section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category
"Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of
accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific
research activities to the Secretary, Department of
Scientific & Industrial Research, 'Technology
Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016
for every financial year by 31st May of each year;
and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-
tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of
Scientific & Industrial Research, and (c) Commis-
sioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exem-
ptions), having jurisdiction over the organisation, by
the 31st October each year, a copy of its audited
Annual Accounts and also a copy of audited Income
and Expenditure Account in respect of its research
activities for which exemption was granted under
sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax
Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Spastics Society of India,
Upper Colaba Road,
Opp. Afghan Church, Colaba,
Bombay-400005.

This Notification is effective for the period from 1-4-92
to 31-3-93.

Notes :

1. Condition (i) above will not apply to organisations
categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate
and well in advance for further extension of the
approval, to the Director General of Income-tax
(Exemptions), Calcutta through the Commissioner
of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions)
having jurisdiction over the organisation. Six copies
of the application for extension of approval should
be sent directly to the Secretary, Department of
Scientific & Industrial Research.

[No. 665/F. No. DG(IT)(E)/M-52/Cal/35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

आयकर, 16 मई, 1992

का. आ. 1021—सर्वसाधारण की सूचना के लिये
एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्न-

लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संव प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(i) में दी गई रिसर्च क्रिया-कलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

भौसाहेब सरदारै मेमोरियल रिसर्च फाउण्डेशन,
पो. अ. तालेगांव जनरल अस्पताल, तालेगांव जिला पूर्ण-
410507.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : उपर्युक्त शर्त (i) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[मं. 666/फा.सं० डी. जी/आ० कर (छूट)/एम 27/
कल/35/(1) (ii)/90-91]

ए. के. विश्वाम, उपनिदेशक

Calcutta, the 15th May, 1992

(INCOME TAX)

S.O. 1021.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Bhauasheb Sardarai Memorial Research Foundation
P. O. Talegaon General Hospital, Talegaon, Dt.
Pune-410507.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-93.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 666]F. No. DG/IT(E)/M-27/Coal/35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता 15 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1022—सर्वसाधारण को सूचना के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संव प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक

अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक, औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त, आयकर महानिदेशक (छूट) जनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रियाकलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखापरीक्षित आय व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

प्रोसेस इंजिनियरी डिजाइन डिवेलपमेंट इन्स्टिट्यूट,
ए डी-161, साल्ट लेक सिटी सेक्टर 1, कलकत्ता 700064

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-91 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पण 1. उपर्युक्त शर्त (i) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/ आयकर निवेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी हैं।

[सं. 667 (फा. सं. डी. जी/ आ. कर (छूट)/ डब्ल्यू बी -36/ कल/35 (i) (ii) 90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 15th May, 1992

(INCOME TAX)

S.O. 1022.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Process Engineering Design Development Institute
AD-161, Salt Lake City, Sector-I, Calcutta-7000634

This Notification is effective for the period from 1-4-91 to 31-3-93.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 667 (F. No. DG/IT(F)/WB-36/Cal/35(1)(ii)90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 15 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1023—पर्वसाधारण को सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संस्थान प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक, औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महा निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रियाकलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

मै बाला मन्दिर रिसर्च फाउण्डेशन, 136, जी.एन चेट्टी रोड टी. नगर, मद्रास-17

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन पत्र को 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 668/फा. सं. डी. जी. /आय कर (छूट) टी
एन/29/कल/35(i) (ii) 90-91]

ए. के. विश्वास उपनिदेशक

INCOME TAX

Calcutta, the 15th May, 1992

S.O. 1023.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

M/s. Bala Mandir Research Foundation, No. 126, C&N, Chetty Road, T. Nagar, Madras-17.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-1995.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 668 F. No. DG/IT(E)/TN-29/Cal/35(1)(ii)90-91

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 15 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1024.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्न-

लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्न-लिखित शर्तों पर संघ प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'औद्योगिक भवन', न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च क्रिया-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सरदार पटेल रिन्यूएबल एर्नर्जि रिसर्च इंस्टिट्यूट, बल्लभ विद्या नगर-388120

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-91 से 31-3-92 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी 1. उपर्युक्त शर्त (1) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त, आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 669/फा. सं. डी. जी./आ. कर (छूट) -35 कल. 35(1)
(ii) 90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

(INCOME TAX)

Calcutta, the 15th May, 1992

S.O. 1024.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of

section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Sardar Patel Renewable Energy Research Institute,
Vallabh Vidya Nagar-388120.

This Notification is effective for the period from 14-91 to 31-3-92.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 669 (F. No. DG/IT(E)/G-35/Cal/35(1)(ii);90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director.

कलकत्ता, 15 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1025.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्न-लिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम के 6 अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्न-लिखित शर्तों पर संस्थान प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'औद्योगिक भवन', न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक

(छूट), (ख), सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च क्रिया-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बन्नारघाटा रोड, बंगलूर-560076।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पण : 1. उपर्युक्त शर्त (1) 'संव' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 670 फा. सं.डी. जी./आ.कर (छूट)/के.टी.-39/कल./35 (1)(ii) 90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 15th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1025.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Institute of Management Bannerghatta Road,
Bangalore-560076.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-93.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 670 (F. No. DG/IT(E)/KT-39/Cal/35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 15 मई, 1992

आयकर

कांशा० 1026.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संस्थान प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यक्रमों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "औद्योगिक भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिस्चर्व किया-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

अरोविला फाउंडेशन,

भारत निवास, अरोविला-605101,

बाया—पांडिचेरी

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1994 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (i) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं० 671/फा. सं. डीजी/आय कर (छूट) कल./टी.एन-53/35/(I)/(ii) (90-91)]

ए. के. बिस्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 15th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1026.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Science and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Auroville Foundation. (Unit : Centre for Scientific Research Bharat Nivas, Auroville-605 101, Via Pondicherry.

This Notification is effective for the period from 1-4-92 to 31-3-94.

Notes : 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 671/F. No. DG/IT(E)/Cal/TN-53/35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 15 मई, 1992

आयकर

कांशा. 1027.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35

की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संस्थान प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एकवार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'औद्योगिक भवन', न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रिया-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इंडियन नेशनल थियेटर, 19/21, अम्बाला दोशी मार्ग, (ह्यूमन स्ट्रीट) बम्बई-400023।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (i) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 672/फा.सं. डी.जी./आ. कर(छूट)/एम. 50/कल.

35(1)(ii)/90-91]

ए. क. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 15th May, 1992

INCOME TAX

S. O. 1027.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian National Theatre, 19/21, Ambala Doshi Marg,
(Human Street) Bombay-400023

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-93.

NOTES :

1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 672/F. No. DG/IT(E)/M-50/Cal/35(1)(ii) 90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 25 मई, 1992

आयकर

का.आ. 1028.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संघ प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (i) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एकवार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'औद्योगिक भवन', न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक

आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिमर्च क्रिया-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाव को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

निम्बकर ऐग्रिकल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट,
फाल्ठन-415523, जिला—सतारा, (महाराष्ट्र)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी 1. उपर्युक्त शर्त (i) 'संघ', जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र का 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 673/फा. सं.डी./जी.आ.कर(छूट)/एम-16 कल./35(1)
(ii) 90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 25th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1028.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Nimbkar Agricultural Research Institute, Phalton-415523, Distt. Satara (Maharashtra).

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1993.

Note—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 674/F. No. DG/IT(E)/M-46/Cal/35(1)(ii) 90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 25 मई, 1992

आयकर

का.आ. 1029.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्न-लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्न-लिखित शर्तों पर संस्थान प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलाप का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'औद्योगिक भवन', न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिमर्च क्रिया-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाव को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेंट्रल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस,
88 2, बजाज नगर, नागपुर-440010

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी 1. उपर्युक्त शर्त (1) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 674/फा. सं.डी.जी./आर कर(छूट)/एम-46/कल./
35] (1)(ii)/90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 25th May, 1992

INCOME-TAX

S.O. 1029.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institute" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Central India Institute of Medical Sciences, 88/2, Bajaj Nagar, Nagpur-440010.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1993.

Note—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 674/F. No. DG/IT(E)/M-46/Cal/35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 26 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1030.—सर्वसाधारण की सूचना लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को,

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संस्थान प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "औद्योगिक भवन", न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षा वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिजर्व क्लॉकबुक संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षा प्रस्तुत हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

दौ कुप्पुस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टिट्यूट,

84, थिरु वी का रोड, मिलापोर,

मद्रास-600004.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 675/फा. सं. डी. जी./आय कर(छूट) टी.एन. 41 कल./
35(1)(ii) 90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 26th May, 1992

INCOME-TAX

S.O. 1030.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of

section 35 of the Income tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities, for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

The Kuppaswami Sastri Research Institute, 84, Thiru VI Ka Road, Mylapore, Madras-600004.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1994.

Note—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 675/F. No. DG/IT(E)/TN-41/Cal/35 (1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 26 मई, 1992

आयकर

कां०आ० 1031—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संस्थान प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'औद्योगिक भवन', न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक

(छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्व क्रियाकलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

ठाकुर हरि प्रसाद इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रीजनिंग-शन फॉर दि मेन्टली हैन्डिकैप्ड चिल्ड्रेन, "शिशुनिकेतन" विवेकानन्द नगर, हैदराबाद-500660,

यह अधिसूचना दिनांक 9-12-91 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1 उपर्युक्त शर्त (1) 'संव' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सूचाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशालय (छूर), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 676 1. सं. डी.जी./आ. कर (छूट)/एपी-14/कल./35 (1)(ii)/90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 26th May, 1992

INCOME-TAX

S.O. 1031.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities, for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Thakur Hari Prasad Institute of Research and Rehabilitation for the Mentally Handicapped Children, "Sishuniketan" Vivekananda Nagar Hyderabad-500660.

Notes—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

Note—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 676/F. No. DG/IT(E)/AP-14/35 (1)(ii)[90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 27 मई, 1992

आयकर

का.आ. 1032.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी की जाती है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर 'कालेज' प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रियाकलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

भारतीय वैद्यक समन्वय समिति,

(ऑल इंडिया आयुर्वेद रिसर्च इंस्टिट्यूट)

श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, हसन नगर,

नागपुर-440009.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1 उपर्युक्त शर्त (1) 'संव' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 677 फा.सं.डी/जी आय कर (छूट)/एम-48/कन.
35(1)(ii) 90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 27th May, 1992

INCOME-TAX

S.O. 1032.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "College" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Returns of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Bhartiya Vaidyak Samanvaya Samity, (All India Ayurveda Research Institute) Sri Ayurved Mahavidyalaya, Human Nagar, Nagpur-440009.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1993.

Note—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 677/F. No. DG/IT(E)/M-48/Cal/35(1)(ii)[90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 27 मई, 1992

Calcutta, the 27th May, 1992

INCOME-TAX

आयकर

का.आ. 1033.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की धारा (1) के खंड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर 'संघ' प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "औद्योगिक भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।
- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रियाकलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

टी रिसर्च एसोसिएशन,
113, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700016.

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी 1. उपर्युक्त शर्त (1) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध के लिए आवेदनपत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 678/फा. सं. डी. जी. आ.कर (छूट)/डब्ल्यू. बी.-17/कल./
35 (1)(ii)/90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

S.O. 1033.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Tea Research Association 113, Park St., Calcutta-700016.
This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

Notes—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 678/F. No. DG/IT(E)/WB-17/Cal/35 (1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 27 मई, 1992

आयकर

का.आ. 1034.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्द्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर एसोसिएशन प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "औद्योगिक भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा।

- (3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रियाकलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

बम्बई नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी,
हार्नबील हाउस, अप. लायन गेट,
भगत सिंह रोड के पीछे, बम्बई-400023

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-90 से 31-5-92 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी 1. उपर्युक्त शर्त (1) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 679/फा. सं. डी. जी. आ. कर(छूट)/एम-55 कल/35(1)(ii)/90-91]
ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 27th May, 1992

INCOME-TAX

S.O. 1034.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Bombay Natural History Society,
Hornbill House, Opp. Lion Gate Behind
Bhagat Singh Road, Bombay-400023.

This Notification is effective for the period from 1-4-1990 to 31-3-1992.

Notes—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 679/F. No. DG/IT(E)/M-55/Cal.35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 29 मई, 1992

आयकर

का.आ. 1035.—सर्वसाधारण को सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्न-लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्न-लिखित शर्तों पर 'संस्थान' प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिए अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक, सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग 'औद्योगिक भवन' न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली 110 016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर, तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रियाकलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

टाटा मेमोरियल सेंटर,
डॉ. एमेस्ट बोरजेस मार्ग परेल,
बम्बई-400 012

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी 1. उपर्युक्त शर्त (1) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 680(फा.सं. डी.जी./आ.कर (छूट)/एम-36/कल./
35(1)(ii)/90-91]
ए.के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 29th May, 1992

INCOME-TAX

S.O. 1035.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Tata Memorial Centre,
Dr. Emost Borges Marg, Parel,
Bombay-400012.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995

Notes—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisations. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 680/F. No. DG/IT(E)/M-36/Cal.35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 29 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1036.—सर्वसाधारण की सूचना के लिये
एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्न-

लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, आयकर नियम 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संघ प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान, संबंधी कार्यकलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिसके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दो गई रिसर्च क्रिया-कलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इण्डियन अकादमी ऑफ पीडिएटरिक्स,
कैलाश दर्शन, केन्नेडी ब्रीज,
बम्बई 400007

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपयुक्त शर्त (1) संघ जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

- संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रति सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 681/फा. सं. डी. जी. / आ. कर (छूट)/
एम-94/कल/35 (1)(ii)/90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 29th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1036.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax

Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Indian Academy of Pediatrics,
Kailas Darshan, Kennedy, Bridge,
Bombay-400007.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1993.

Notes—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisations. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 681/F, No. DG/IT(E)/M-94/Cal/35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 29 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1037—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संघ प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक सेवा परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक

(छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(1) में दो गई रिसर्च क्रिया-कलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

एसकार्ट हार्ट इनस्टिट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर, ओखला रोड, नई दिल्ली —110025

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-92 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं 682/का. सं. डी. जी. / आ. कर (छूट) / एन.

डी-5/कल/35 (1) (ii) /90-91]

ए. के. विद्यास, उपनिदेशक

Calcutta, the 29th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1037.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Escort Heart Institute and Research Centre,
Okhla Road, New Delhi-110025.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

Notes—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisations. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 682/F. No. DG/IT(E)/ND-5/Cal/35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

कलकत्ता, 29 मई, 1992

आयकर

का. आ. 1038—सर्वसाधारण की सूचना के लिये एतद्वारा यह अधिसूचना जारी किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम 1961 को धारा 35 को उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिये, आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर संघ प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्राप्त धन के लिये एक अलग लेखा रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, प्रत्येक वर्ष की 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, औद्योगिक भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा।

(3) यह प्रत्येक वर्ष की 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक आयुक्त और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रिया-कलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

नैयर गोल्डेन जुबिली रिसर्च फाउन्डेशन डा. ए. एल. नैयर रोड, बम्बई—400008।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-91 से 31-3-92 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) 'संघ' जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार

में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट) कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में किए आवेदन पत्र को 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 683/फा. सं. डी जी/आ. कर (छूट)/एम-126/कल/35/(1) (ii)/90-91]

ए. के. विश्वास, उपनिदेशक

Calcutta, the 29th May, 1992

INCOME TAX

S.O. 1038.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Nair Golden Jubilee Research Foundation.
Dr. A. L. Nair Road, Bombay-400008.

This Notification is effective for the period from 1-4-1991 to 31-3-1992.

Notes—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisations. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 683/F. No. DG/IT(E)/M-126/Cal/35(1)(ii)/90-91]

A. K. BISWAS, Dy. Director

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

का.आ.1039:—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 3 के साथ पठित, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963

(1963 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना सं. 3/90/85-ई. आई. एण्ड ई. पी. तारीख 21 जनवरी, 1993 में रूपान्तर करते हुए श्री वाई बी. रेड्डी, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय के डा. जी. सुन्दरम के स्थान पर नियत निरीक्षण परिषद् का एतद्वारा तुरन्त अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फाइल संख्या 3/90/85-ई.आई.एण्ड ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1039.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with Rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government, in modification of Notification No. 3/90/85-EI&EP dated 21st January, 1993, hereby appoints Shri Y. V. Reddy, Additional Secretary, Ministry of Commerce, as Chairman of the Export Inspection Council with immediate effect, vice Dr. G. Sundaram

[File No. 3/90/85-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

का.आ.1040:—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि मैसर्स पैस्ट कंट्रोल कम्पनी बंगलोर को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3608 तारीख 16 नवम्बर, 1965 द्वारा दी गयी मान्यता वापिस ली जाए और उस अभिकरण को इस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए उचित अवसर देने के पश्चात् उक्त मान्यता को लोकहित में वापिस लेती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फाइल सं. 5/8/92-ई आई एण्ड ई पी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1040.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, being of the opinion that the recognition granted to M/s. Pest Control Company, Bangalore vide Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 3608, dated 16th November, 1965 may be withdrawn and after giving a reasonable opportunity to that agency to make representation in the matter, hereby withdraws the recognition in the public interest.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 5/8/92-EI&FP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

का.आ.1041:—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की

धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि कलकत्ता स्थित मैसर्स कार्गो इंस्पेक्टर्स एण्ड सुपरिटेण्डेंस (प्रा.) लिमिटेड को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की क्रमशः अधिसूचना सं. का.आ. 3152 तारीख 30 सितम्बर, 1965 का.आ. 3150, तारीख 30 सितम्बर, 1965, का.आ. 1773, तारीख 7 जून, 1966 और का.आ. 1006 तारीख 23 मार्च, 1967 द्वारा दी गयी मान्यता वापिस ली जाए और उस अभिकरण को इस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए उचित अवसर देने के पश्चात् उक्त मान्यता को लोकहित में वापिस लेती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फाइल सं. 5/8/92-ईआईएण्ड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1041.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, being of the opinion that the recognition granted to M/s. Cargo Inspectors and Superintendence Co. (Pvt.) Ltd., at Calcutta vide Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. S.O. 3152 dated 30th September, 1965, S.O. 3150 dated 30th September, 1965, S.O. 1773 dated 7th June, 1966 and S.O. 1006, dated 23rd March, 1967 respectively may be withdrawn and after giving a reasonable opportunity to that agency to make representation in the matter, hereby withdraws the said recognition in the public interest.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 5/8/92-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

का.आ.1042:—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि अल्टामाउंट रोड, मुम्बई स्थित मैसर्स डा. रमण सी. अमीन को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 2443, तारीख 2 अगस्त, 1975 द्वारा दी गयी मान्यता वापिस ली जाए और उस अभिकरण को इस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए उचित अवसर देने के पश्चात् उक्त मान्यता को लोकहित में वापिस लेती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फाइल सं. 5/8/92-ईआईएण्ड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1042.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, being of the opinion that the recognition granted to M/s. Dr. Raman C. Amin at Altamount Road, Bombay vide notifica-

fication of the Government of India in the Ministry of Commerce, S.O. No. 2443, dated 2nd August, 1975 may be withdrawn and after giving a reasonable opportunity to that agency to make representation in the matter, hereby withdraws the said recognition in the public interest.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 5/8/92-EI&EP]
KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

का.आ. 1043:—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि मुम्बई स्थित मैसर्स कार्गो इन्स्पेक्टर्स एंड सुपरिटेण्डेंस कं. (प्रा.) लिमिटेड को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की क्रमशः अधिसूचना का.आ. 3407, तारीख 28 अक्टूबर, 1965, का.आ. 2155, तारीख 19 जुलाई, 1966, का.आ. 480, तारीख 9 फरवरी 1966 का.आ. 1272, तारीख 25 मार्च, 1966, का.आ. 2677, तारीख 1 मिनम्बर, 1966, का.आ. 1006, तारीख 23 मार्च, 1967, का.आ. 1688, तारीख 3 जून, 1966, का.आ. 4456, तारीख 14 दिसम्बर, 1967, का.आ. 4576, तारीख 19 दिसम्बर, 1967 और का.आ. 480, तारीख 12 फरवरी, 1977 द्वारा दी गयी मान्यता वापिस ली जाए और उस अभिकरण को इस मामले में अध्याववेदन करने के

लिए उचित अवसर देने के पश्चात् उक्त मान्यता को लोकाहित में वापिस लेती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फाईल सं. 5/8/92-ईआई एण्ड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1043.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government being of the opinion that the recognition granted to M/s. Cargo Inspectors and Superintendence Co. (Pvt.) Ltd., at Bombay vide Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. 3407 dated 28th October, 1965, S.O. 2155 dated 19th July, 1966, S.O. 480 dated 9th February, 1966, S.O. 1272 dated 25th March, 1966, S.O. 2677 dated 1st September, 1966, S.O. 1006 dated 23rd March, 1967, S.O. 1688 dated 3rd June, 1966, S.O. 4456, dated 14th December, 1967, S.O. 4576 dated 19th December, 1967 and S.O. 480 dated 12th February, 1977 respectively may be withdrawn and after giving a reasonable opportunity to that agency to make representation in the matter, hereby withdraws the said recognition in the public interest.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 5/8/92-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

परमाणु ऊर्जा विभाग

आदेश

बम्बई, 3 मई, 1993

का.आ. 1044:—राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) की धारा (ब) तथा नियम 24 के उप-नियम (i) के अनुमरण में, तथा भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के विनॉक 7 जुलाई, 1979 के आदेश सा.आ. 2537 का अधिकरण करने हुए, निम्नलिखित कार्यों के जो एसे अधिकरण से पहले किए जा चुके हैं अथवा जिनका किए जाने हेतु, कोष किया गया, एतद्वारा निदेश देते हैं कि इस आदेश की अनुसूची के भाग-I, भाग-II और भाग-III के काण्ड 2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट सामान्य केन्द्रीय सेवाएं वर्ग 'ख', सामान्य केन्द्रीय सेवाएं वर्ग 'ग' और सामान्य केन्द्रीय सेवाएं वर्ग 'घ' के पदों के संबंध में कालम 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होंगे और इसी कालम में 5 में विनिर्दिष्ट दंडों के संबंध में कालम 4 तथा 6 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी क्रमशः अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीली प्राधिकारी होंगे।

अनुसूची

भाग-I सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ख'

क्र.सं.	पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	दंड देने के लिए सक्षम प्राधिकारी और दंड जो वे दें सकते हैं (नियम 11 में दी गयी संख्याओं के संबंध में)	असली प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			प्राधिकारी	दंड
				(6)
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग			
1.	विभाग के सचिवालय में पद	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	सभी सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
2.	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में पद (भा. प. अनु. के.)			
(क)	शैक्षणिक और तकनीकी पद	नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	सभी निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ख) प्रशासनिक और सहायक पद	निर्देशक, भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	निर्देशक, भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	सभी		
3. परमाणु खनिज प्रभाग (ए.एम.डी.) में पद	निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग	निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग	सभी		निदेशक, भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
4. भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय) और भारी पानी परियोजना/संयंत्रों के प्रधान पद	मुख्य कार्यपालक, भारी पानी बोर्ड	मुख्य कार्यपालक, भारी पानी बोर्ड	सभी		
5. संवदा प्रबंध निदेशालय (डीईएम) में पद	अपर सचिव/संयुक्त सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग	अपर सचिव/संयुक्त सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग	सभी		
6. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीएआर) में पद	निदेशक, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र	निदेशक, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र	सभी		सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
7. अणु एवं अंतरा निदेशालय (डीवीएम) में पद	निदेशक, अणु एवं अंतरा निदेशालय	निदेशक, अणु एवं अंतरा निदेशालय	सभी		
8. नाभिकीय ईंधन समिथि (एनएफसी) में पद	मुख्य कार्यपालक/उप मुख्य कार्यपालक (प्रशासन) नाभिकीय ईंधन समिथि	मुख्य कार्यपालक/उप मुख्य कार्यपालक (प्रशासन) नाभिकीय ईंधन समिथि	सभी		
9. निर्माण एवं सेवा वर्ग में पद	निदेशक, निर्माण एवं सेवा वर्ग	निदेशक, निर्माण एवं सेवा वर्ग	सभी		
10. सामान्य सेवा संगठन, कल्पावकम में पद	अपर सचिव/संयुक्त सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	सभी		
11. प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र (प्र. प्रौ. के.) में पद	निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र	निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र	सभी		
12. विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (प्रिट) में पद	मुख्य कार्यपालक, विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	मुख्य कार्यपालक, विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (प्रिट)	सभी		सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
13. परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड में पद	अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड	अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड	सभी		
14. परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र में पद	निदेशक, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र	निदेशक, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र	सभी		
15. ऊपर विनिर्दिष्ट पदों के प्रतिरिक्त अन्य पद	अपर सचिव/संयुक्त सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग	अपर सचिव/संयुक्त सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग	सभी		

भाग-II सामान्य केन्द्रीय सेवाएं वर्ग 'ग'

परमाणु ऊर्जा विभाग

1. विभाग के सचिवालय में पद	निदेशक/उप सचिव	निदेशक/उप सचिव	सभी	अपर सचिव/संयुक्त सचिव
2. भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (भा.प.अ.के.) में पद	अध्यक्ष कार्यालय प्रभाग भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (भा.प.अ.के.)	अध्यक्ष कार्यालय प्रभाग भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	सभी	निदेशक, भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
3. परमाणु खनिज प्रभाग (ए.एम.डी.) में पद	मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी परमाणु खनिज प्रभाग (ए.एम.डी.)	मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी परमाणु खनिज प्रभाग	सभी	निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग
4. भारी पानी बोर्ड तथा उसके अधीन परियोजनाओं/संयंत्रों में पद	(अ) भारी पानी बोर्ड के केन्द्रीय कार्यालय में पदों के मामले में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (ब) भारी पानी परियोजनाओं या संयंत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके अपने-अपने नियंत्रणाधीन पदों के मामले में महा-प्रबंधक	भारी पानी बोर्ड के केन्द्रीय कार्यालय में पदों के मामले में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भारी पानी परियोजनाओं या संयंत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके अपने-अपने नियंत्रणाधीन पदों के मामले में महा-प्रबंधक	सभी	निदेशक, भारी पानी बोर्ड
5. संवदा प्रबंध निदेशालय (डीईएम) में पद	निदेशक, संवदा प्रबंध निदेशालय	निदेशक, संवदा प्रबंध निदेशालय	सभी	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
6. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र में पद	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी इंदिरा, गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र	सभी	निदेशक, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. क्रय एवं भंडार निदेशालय (रीपोरिंग) में पद	निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय	निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय	सभी	अवर सचिव/संयुक्त सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग	
8. नाभिकीय ईंधन समिधि (एनएफसी) में पद	उप मुख्य कार्यपालक (प्रशासन) नाभिकीय ईंधन समिधि	उप मुख्य कार्यपालक (प्रशासन) नाभिकीय ईंधन समिधि	सभी	मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन समिधि	
9. निर्माण एवं सेवा वर्ग में पद	निदेशक, निर्माण एवं सेवा वर्ग	निदेशक, निर्माण एवं सेवा वर्ग	सभी	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	
10. सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ) कल्याणक में पद	मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी सामान्य सेवा संगठन कल्याणक	मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी सामान्य सेवा संगठन कल्याणक	सभी	अवर सचिव/संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	
11. प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र में पद	मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र	मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र	सभी	निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र	
12. विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड में पद	मुख्य कार्यपालक, विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	मुख्य कार्यपालक, विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	सभी	निदेशक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र	
13. परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड में पद	अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड	अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड	सभी	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	
14. परियोजना ऊर्जा साइकलोट्रॉन केन्द्र (प.ऊ.सा.के.) में पद	निदेशक, परियोजना ऊर्जा साइकलोट्रॉन केन्द्र	निदेशक परियोजना ऊर्जा साइकलोट्रॉन केन्द्र	सभी	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	
15. ऊपर त्रिनाइट्ट पदों के अभाव में अन्य पद	निदेशक/उप सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग	निदेशक/उप सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग	सभी	अवर सचिव/संयुक्त सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग	

भाग III—सामान्य केन्द्रीय सेवाएं वर्ग 'घ'

परमाणु ऊर्जा विभाग

1. विभाग के सचिवालय में पद	अवर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	सभी	निदेशक/उपसचिव,
2. भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (भा.प.अ.के.) में पद			
(क) उस कर्मचारियों (वर्ग घ) के बारे में पद जो 11 अक्टूबर, 1990 को सेवा में थे	अध्यक्ष, कार्मिक प्रभाग भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	अध्यक्ष, कार्मिक प्रभाग भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	सभी निर्देशक, भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(ख) 11 अक्टूबर 1990 के बाद वर्ग 'घ' कर्मचारियों के लिए पद	उप स्थापना अधिकारी भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	उप स्थापना अधिकारी भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	सभी अध्यक्ष कार्मिक प्रभाग भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
3. परमाणु खनिज प्रभाग (प.ख.प्र.) में पद	मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी परमाणु खनिज प्रभाग	मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी परमाणु खनिज प्रभाग	सभी निदेशक, परमाणु खनिज प्रभाग
4. भारी पानी बोर्ड, परियोजनाओं एवं गद्यनों में पद	(क) भारी पानी बोर्ड के केन्द्रीय कार्यालय में पदों के संबंध में प्रशासनिक अधिकारी-III (ख) भारी पानी परियोजनाओं में प्रयोज्य संयंत्रों के कार्यालयों में उनके अपने-अपने नियंत्रणधीन पदों के संबंध में उनका अपना प्रशासनिक अधिकारी-III अथवा प्रशासनिक अधिकारी-III	भारी पानी बोर्ड के केन्द्रीय कार्यालय में पदों के संबंध में प्रशासनिक अधिकारी-III भारी पानी परियोजनाओं में प्रयोज्य संयंत्रों के कार्यालयों में उनके अपने-अपने नियंत्रणधीन पदों के संबंध में उनका अपना प्रशासनिक अधिकारी-III अथवा प्रशासनिक अधिकारी-III	सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारी पानी बोर्ड भारी पानी परियोजनाओं में प्रयोज्य संयंत्रों के कार्यालयों में उनके अपने-अपने नियंत्रणधीन पदों के संबंध में उनके अपने-अपने महा-प्रबंधक
5. विश्व प्रबंध निदेशालय में पद	प्रशासनिक अधिकारी-III संपदा प्रबंध निदेशालय	प्रशासनिक अधिकारी-III, संपदा प्रबंध निदेशालय	सभी निदेशक, संपदा प्रबंध निदेशालय
6. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीएमएआर) में पद	प्रशासनिक अधिकारी-III इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र	प्रशासनिक अधिकारी-III इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र	सभी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र
7. क्रय एवं भंडार निदेशालय (रीपोरिंग) में पद	प्रशासनिक अधिकारी-III क्रय एवं भंडार निदेशालय	प्रशासनिक अधिकारी-III क्रय एवं भंडार निदेशालय	सभी निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय
8. नाभिकीय ईंधन समिधि (एनएफसी) में पद	प्रशासनिक अधिकारी-III नाभिकीय ईंधन समिधि	प्रशासनिक अधिकारी-III नाभिकीय ईंधन समिधि	सभी उप मुख्य कार्यपालक, (प्रशासन)

9. निर्माण एवं सेवा वर्ग (सी एंड एन) में पद	प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण एवं सेवा वर्ग	प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण एवं सेवा वर्ग	सभी	निदेशक, निर्माण एवं सेवा वर्ग
10. सामान्य सेवा संगठन (जीएसओ) कल-पाक्कम में पद	प्रशासनिक अधिकारी-III सामान्य सेवा संगठन, कलपाक्कम	प्रशासनिक अधिकारी-III सामान्य सेवा संगठन, कलपाक्कम	सभी	मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी सामान्य सेवा संगठन, कलपाक्कम
11. प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीएटी) इंदौर में पद	प्रशासनिक अधिकारी III, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र इंदौर	प्रशासनिक अधिकारी III प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र इंदौर	सभी	मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर
12. विकिरण एवं ब्राह्मसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) बम्बई में पद				
(क) उन कर्मचारियों (वर्ग घ) के बारे में पद जो 15-1-91 को सेवा में थे।	मुख्य कार्यपालक, विकिरण एवं ब्राह्मसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट), बम्बई	मुख्य कार्यपालक, विकिरण एवं ब्राह्मसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट) बम्बई	सभी	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग
(ख) उन कर्मचारियों (वर्ग घ) के बारे में पद जो 16-1-91 को भयवत्ता उसके बाद सेवा में आये।	प्रशासनिक अधिकारी-III विकिरण एवं ब्राह्मसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट), बम्बई	प्रशासनिक अधिकारी-III विकिरण एवं ब्राह्मसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट), बम्बई	सभी	मुख्य कार्यपालक विकिरण एवं ब्राह्मसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट), बम्बई
13. परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (एईआर बी) में पद	प्रशासनिक अधिकारी-III परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड	प्रशासनिक अधिकारी-III परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड	सभी	अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
14. परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र (बीईसीसी) में पद	प्रशासनिक अधिकारी-III परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, कलकत्ता	प्रशासनिक अधिकारी-III परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, कलकत्ता	सभी	निदेशक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र कलकत्ता
15. ऊपर विनिर्दिष्ट पदों के अलावा अन्य पद	अवर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	अवर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	सभी	निदेशक/उप-सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग

[फाइल नं. 1/6(1)/91-प्रतर्कता]

श्रीमती टी. एफ. शेक्केकरा, निदेशक

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

ORDER

Bombay the May 3, 1993

S.O. 1044 :- In pursuance of sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and in supersession of the Government of India in the Department of Atomic Energy Order No. S.O. 2537 dated 7th July, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby directs that in respect of posts in the General Central Service, Group 'B', the General Central Service Group 'C' and the General Central Service Group 'D', specified respectively in column 2 of Part I, Part II and Part III of the Schedule to this Order, the authority specified in column 3 shall be the Appointing Authority and the authority specified in columns 4 and 6 shall be the Disciplinary Authority and the Appellate Authority respectively in regard to the penalties specified in column 5 thereof.

SCHEDULE

Part I—General Central Service, Group 'B'

Serial No.	Description of Post	Appointing Authority	Authority Competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in Rule 11)	Appellate Authority
			Authority	Penalties
1	2	3	4	5
6				
Department of Atomic Energy				
1.	Posts in the Secretariat of the Department	Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Atomic Energy.	Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Atomic Energy	All Secretary, Department of Atomic Energy

1	2	3	4	5	6
2.	Posts in Bhabha Atomic Research Centre (BARC).				
(a)	Scientific and Technical Posts.	Controller, Bhabha Atomic Research Centre.	Controller, Bhabha Atomic Research Centre	All	} Director, Bhabha Atomic Research Centre.
(b)	Administrative and Auxiliary posts.	Controller, Bhabha Atomic Research Centre.	Controller, Bhabha Atomic Research Centre	All	
3.	Posts in the Atomic Minerals Division (AMD).	Director, Atomic Minerals Division.	Director, Atomic Minerals Division.	All	} Secretary, Department of Atomic Energy.
4.	Posts in Heavy Water Board (Central Office) and Heavy Water Projects/Plants thereunder.	Chief Executive, Heavy Water Board.	Chief Executive, Heavy Water Board.	All	
5.	Posts in the Directorate of Estate Management (DEM).	Additional Secretary/Joint Secretary Department of Atomic Energy.	Additional Secretary/Joint Secretary. Department of Atomic Energy.	All	
6.	Posts in Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR).	Director, Indira Gandhi Centre for Atomic Research.	Director, Indira Gandhi Centre for Atomic Research.	All	} Secretary, Department of Atomic Energy.
7.	Posts in Directorate of Purchase and Stores (DPS).	Director, Directorate of Purchase and Stores.	Director, Directorate of Purchase and Stores.	All	
8.	Posts in the Nuclear Fuel Complex (NFC).	Chief Executive/Deputy Chief Executive (Admn.) Nuclear Fuel Complex.	Chief Executive/Deputy Chief Executive (Admn.), Nuclear Fuel Complex.	All	
9.	Posts in the Construction and Services Group.	Director, Construction and Services Group.	Director, Construction and Services Group.	All	
10.	Posts in the General Services Organisation Kalpakkam.	Addl. Secretary/Joint Secretary, Department of Atomic Energy.	Addl. Secretary/Joint Secretary, Department of Atomic Energy.	All	
11.	Posts in the Centre for Advanced Technology (CAT).	Director, Centre for Advanced Technology.	Director, Centre for Advanced Technology.	All	
12.	Posts in the Board of Radiation and Isotope Technology (BRIT).	Chief Executive, Board of Radiation and Isotope Technology.	Chief Executive, Board of Radiation and Isotope Technology.	All	
13.	Posts in the Atomic Energy Regulatory Board.	Chairman, Atomic Energy Regulatory Board.	Chairman, Atomic Energy Regulatory Board.	All	
14.	Posts in the Variable Energy Cyclotron Centre.	Director, Variable Energy Cyclotron Centre.	Director, Variable Energy Cyclotron Centre.	All	
15.	Posts other than those specified above.	Addl. Secretary/Joint Secretary, Department of Atomic Energy.	Addl. Secretary/Joint Secretary, Department of Atomic Energy.	All	

Part II— General Central Service, Group 'C'

Department of Atomic Energy.

1. Posts in the Secretariat of the Department.	Director/Deputy Secretary	Director/Deputy Secretary	All	Additional Secretary/Joint Secretary.
2. Posts in the Bhabha Atomic Research Centre (BARC).	Head, Personnel Division, Bhabha Atomic Research Centre (BARC).	Head, Personnel Division, Bhabha Atomic Research Centre.	All	Controller, Bhabha Atomic Research Centre.
3. Posts in the Atomic Minerals Division (AMD).	Chief Administrative and Accounts Officer, Atomic Minerals Division (AMO).	Chief Administrative and Accounts Officer, Atomic Minerals Division.	All	Director, Atomic Minerals Division.

1	2	3	4	5	6
4. Posts in the Heavy Water Board and Projects/ Plants thereunder.	(a) Chief Administrative Officer in respect of posts in the Central Office of Heavy Water Board.	Chief Administrative Officer in respect of posts in the Central Office, Heavy Water Board.	All	Chief Executive, Heavy Water Board.	
	(b) General Managers in respect of posts under their respective control in field offices of Heavy Water Projects or Plants.	General Managers in respect of posts under their respective control in field offices of Heavy Water Projects or Plants.	All	Chief Executive, Heavy Water Board.	
5. Posts in the Directorate of Estate Management (DEM).	Director, Directorate of Estate Management.	Director, Directorate of Estate Management	All	Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Atomic Energy.	
6. Posts in the Indira Gandhi Centre for Atomic Research.	Chief Administrative Officer, Indira Gandhi Centre for Atomic Research.	Chief Administrative Officer, Indira Gandhi Centre for Atomic Research.	All	Director, Indira Gandhi Centre for Atomic Research.	
7. Posts in the Directorate of Purchase and Stores (DPS).	Director, Directorate of Purchase and Stores.	Director, Directorate of Purchase and Stores.	All	Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Atomic Energy.	
8. Posts in the Nuclear Fuel Complex (NFC).	Deputy Chief Executive (Admn.) Nuclear Fuel Complex.	Deputy Chief Executive (Admn.) Nuclear Fuel Complex.	All	Chief Executive, Nuclear Fuel Complex.	
9. Posts in the Construction and Services Group	Director, Construction and Services Group.	Director, Construction and Services Group..	All	Secretary, Department of Atomic Energy.	
10. Posts in the General Services Organisation (GSO) Kalpakkam.	Chief Administrative and Accounts Officer, General Services Organisation, Kalpakkam.	Chief Administrative and Accounts Officer, General Services Organisation, Kalpakkam	All	Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Atomic Energy	
11. Posts in the Centre for Advanced Technology.	Chief Administrative and Accounts Officer, Centre for Advanced Technology.	Chief Administrative and Accounts Officer, Centre for Advanced Technology.	All	Director, Centre for Advanced Technology.	
12. Posts in the Board of Radiation and Isotope Technology.	Chief Executive, Board of Radiation and Isotope Technology.	Chief Executive, Board of Radiation and Isotope Technology.	All	Secretary, Department of Atomic Energy.	
13. Posts in Atomic Energy Regulatory Board.	Chairman, Atomic Energy Regulatory Board.	Chairman, Atomic Energy Regulatory Board.	All	Secretary, Department of Atomic Energy.	
14. Posts in Variable Energy Cyclotron Centre (VECC).	Director, Variable Energy Cyclotron Centre.	Director, Variable Energy Cyclotron Centre.	All	Secretary, Department of Atomic Energy.	
15. Posts other than those specified above.	Director/Deputy Secretary Department of Atomic Energy.	Director/Deputy Secretary, Department of Atomic Energy.	All	Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Atomic Energy.	

Part III General Central Services Group 'D'

Department of Atomic Energy

1. Posts in the Secretariat of the Department.	Under Secretary, Department of Atomic Energy.	Under Secretary, Department of Atomic Energy.	All	Director/Deputy Secretary, Department of Atomic Energy.
2. Posts in Bhabha Atomic Research Centre (BARC)				
(a) Posts in respect of employees (Group 'D') in service as on 11th October 1990.	Head, Personnel Division, Bhabha Atomic Research Centre.	Head, Personnel Division, Bhabha Atomic Research Centre.	All	Controller, Bhabha Atomic Research Centre.
(b) Posts in respect of Group 'D' employees appointed after the 11th October 1990.	Deputy Establishment Officer, Bhabha Atomic Research Centre.	Deputy Establishment Officer, Bhabha Atomic Research Centre.	All	Head, Personnel Division, Bhabha Atomic Research Centre.

1	2	3	4	5	6
3. Posts in the Atomic [Minerals Division (AMD).	Chief Administrative and Accounts Officer, Atomic Minerals Division.	Chief Administrative and Accounts Officer, Atomic Minerals Division.	All	Director, Atomic Minerals Division.	
4. Posts in the Heavy [Water Board, Projects and Plants.	(a) Administrative Officer-III in respect of posts in the Central Office of Heavy Water Board. (b) The Administrative Officer-III, in respect of posts under their respective control in offices of Heavy Water Projects or Plants.	Administrative Officer-III, in respect of posts in the Central Office of Heavy Water Board. The respective Administrative Officer-III, in respect of posts under thier respective control in offices of Heavy Water Projects or Plants.	All All	Chief Administrative Officer Heavy Water Board. The respective General Managers in respect of posts under their respective control in offices of Heavy Water Projects or Plants.	
5. Posts in the Directorate of Estate Management (DEM).	Administrative Officer-III, Directorate of Estate Management.	Administrative Officer-III, [Directorate of Estate Management.	All	Director, Directorate of Estate Management.	
6. Posts in the Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR).	Administrative Officer-III, Indira Gandhi Centre for Atomic Research.	Administrative Officer-III, Indira Gandhi Centre for Atomic Research	All	Chief Administrative Officer, Indira Gandhi Centre for Atomic Research.	
7. Posts in the Directorate of Purchase and Stores (DPS).	Administrative Officer-III, Directorate of Purchase and Stores.	Administrative Officer-III, Directorate of Purchase and Stores.	All	Director, Directorate of Purchase and Stores.	
8. Posts in the Nuclear Fuel Complex (NFC).	Administrative Officer-III, Nuclear Fuel Complex.	Administrative Officer-III, Nuclear Fuel Complex.	All	Deputy Chief Executive (Admn.) Nuclear Fuel Complex.	
9. Posts in the Construction and Services Group (C&SG).	Administrative Officer, Construction and Services Group.	Administrative officer, Construction and Services Group.	All	Director, Construction and Services Group.	
10. Posts in the General Services Organisation (GSO), Kalpakkam.	Administrative Officer-III General Services Organisation, Kalpakkam.	Administrative Officer-III, General Services Organisation, Kalpakkam.	All	Chief Administrative and Accounts Officer, General Services Organisation Kalpakkam	
11. Posts in the Centre for Advanced Technology (CAT), Indore.	Administrative Officer-III, Centre for Advanced Technology, Indore.	Administrative Officer-III, Centre for Advanced Technology, Indore.	All	Chief Administrative and Accounts Officer, Centre for Advanced Technology, Indore.	
12. Posts in Board of Radiation and Isotope Technology (BRIT) Bombay.					
(a) Post in respect of employees (Group 'D') in service as on 15-1-91.	Chief Executive, Board of Radiation and Isotope Technology, Bombay (BRIT).	Chief Executive Board of Radiation and Isotope Technology (BRIT) Bombay.	All	Secretary, Department of Atomic Energy.	
(b) Post in respect of employees (Group 'D') in service on or after 16-1-91.	Administrative Officer-III, Board of Radiation and Isotope Technology (BRIT), Bombay.	Administrative Officer-III, Board of Radiation and Isotope Technology (BRIT), Bombay.	All	Chief Executive, Board of Radiation and Isotop Technology (BIRT), Bombay.	
13. Posts in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB).	Administrative Officer-III, Atomic Energy Regulatory Board.	Administrative Officer-III, Atomic Energy Regulatory Board.	All	Chairman, Atomic Energy Regulatory Board.	
14. Posts in Variable Energy Cyclotron Centre (VECC).	Administrative Officer-III, Variable Energy Cyclotron Centre, Calcutta.	Administrative Officer-III, Variable Energy Cyclotron Centre, Calcutta.	All	Director, Variable Energy Cyclotron Centre Calcutta.	
15. Posts other than those specified above.	Under Secretary, Department of Atomic Energy.	Under Secretary, Department of Atomic Energy.	All	Director/Deputy Secretary, Department of Atomic Energy.	

[No. F. 1/6 (1)/91-Vig]
SMT. T.F. THEKKEKARA, Director.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का. आ. 1045—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. घा. सं. 3848 तारीख 14-10-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

अनुसूची

पावरा - 9 से पादरा ई पी एम तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : वडोदरा तालुका : पावरा

गांव	ब्लॉक सं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
पादरा	1210	0	00	28
	1209	0	20	80
कार्ट ट्रैक		0	01	69
	1213	0	03	16
	1214	0	09	94
	1216	0	03	01
	1215	0	19	96
	1217	0	02	25
कार्ट ट्रैक		0	20	60
	1188	0	05	85
	1187	0	11	70
	1184	0	09	23
	1183	0	00	78
	1181	0	11	14
	1178	0	02	99
	1179	0	18	01
	1109	0	16	03
	1111	0	00	70
	1112/1	0	10	00
	1113/4	0	10	00
	1108	0	05	83
	1113/पी	0	09	07
	1055	0	17	16

1	2	3	4	5
	कार्ट ट्रैक	0	01	95
	1035/2	0	12	54
	1036	0	00	75
	1037	0	15	84
	1043	0	09	12
	1041	0	17	16

[सं. ओ - 12016/87/92 - ओ एन जी डी - 4]

एम. मर्दिन, हेड अधिकारी

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 21st April, 1993

NOTIFICATION

S.O. 1045.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2848 dated 14-10-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub section (1) of the section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering, the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section(1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Padara-9 to Padra EPS

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Padra	1210	0	00	28
	1209	0	20	80
	Cart track	0	01	69
	1213	0	03	16
	1214	0	09	94
	1216	0	03	01
	1215	0	19	96
	1217	0	02	25
	Cart track	0	02	60
	1188	0	05	85
	1187	0	11	70
	1184	0	09	23
	1183	0	00	78
	1181	0	11	14
	1178	0	02	99

New Delhi, the 21st April, 1993

NOTIFICATION

S.O. 1046.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2846 dated 14-10-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And further whereas the Central Government has, after (i) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section(1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Padra-9 to EPS Padra

State : Gujarat

Taluka & District : Vadodara

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centi-are
Raipura	165	0	10	53
	164/2	0	03	06
	161	0	08	25
	Cart track	0	01	95
	160/2	0	08	71

[No. O-12016/85/92-ONGD-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का. प्रा. 1047.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 2845 तारीख 14-10-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारों ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

1	2	3	4	5
पादरा (नारी)	1179	0	18	01
	1109	0	16	03
	1111	0	00	70
	1112/1	0	10	00
	1112/4	0	10	00
	1108	0	05	88
	1113/P	0	09	07
	1055	0	17	16
	Cart track	0	01	95
	1035/2	0	12	54
	1036	0	00	75
	1037	0	15	84
	1043	0	09	12
	1041	0	17	16

[No.O-12016/87/92/ONGD/IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का. प्रा. 1046.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 2846 तारीख 14-10-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारों ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार से निहित होने को बशाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निश्चित होगा।

अनुसूची

पादरा - 9 से ईपीएस पादरा तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : वडोदरा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टर	आर.	सेन्टियर
1	2	3	4	5
रायपुरा	165	0	10	53
	164/2	0	03	66
	161	0	08	25
	कार्ट ट्रैक	0	01	95
	160/2	0	08	71

[स. प्रा. - 12016/85/92 - ओ एन जी डी - IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी. जी. एम. 5 से जी. जी. एम. कलोल तथा पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तहसील : कलोल

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टर	आर	सेटीयर
इसंड	805	0	27	00
	772	0	21	00
	773	0	10	40
	769	0	32	70

[सं. ओ - 12016/84/92 - ओ एन जी सी - IV]

एम मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 1993

S.O. 1047.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2845, dated 14-10-1992 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section(1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from GGS-5 to GGS Kalol
State : Gujarat District : Mehsana Tal : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Isand	805	0	27	00
	772	0	21	00
	773	0	10	40
	769	0	32	70

[No. O-12016/84/92-ONGD-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का. घा. 1048.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संज्ञात्मक अधिसूचना का. घा. सं. 2039 तारीख 1-8-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गावा - 1 से जी एन ए क्यू तक पाइप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - नाहब तालुका - जंबुसर

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेटीआर
1	2	3	4	5 -
जामसरमा	328	0	01	30
	329	0	01	00
	330	0	01	10
	331	0	02	00
	338	0	01	24
	339	0	03	70
	340	0	00	77
	341	0	00	50
	348	0	01	26
	353	0	00	10
	351	0	00	22
	350/ए/बी	0	05	70
	416	0	03	19
	415	0	05	25
	414	0	01	25
	413	0	01	27
	420	0	05	20
	411	0	00	09
	410	0	00	04
	409	0	03	60
कार्टट्रेक		0	01	60
	498	0	01	91
	525	0	00	12

1	2	3	4	5
	554	0	00	06
	490	0	02	78
	523	0	00	80
	518	0	01	18
	517	0	00	85
	511	0	04	20
	512	0	00	35
	510	0	01	00
	512	0	01	00
	493	0	01	90
	496	0	05	40
	497	0	07	27
	कार्ट ट्रैक	0	01	39
	562	0	05	58
	563	0	00	27
	561	0	04	30
	566	0	04	30
	कार्ट ट्रैक	0	02	61
	724	0	05	95
	726	1	27	20
	509	0	01	19
	498	0	02	00
	560	0	00	50

[सं. ओ - 12016/70/92 - ओ एन जी डी - 4]

एस मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 1993

S.O. 1048.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2039, dated 1-8-1992 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section(1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Nada-1 to Gnaq

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Cent- tiare
1	2	3	4	5
Aasarsa	328	0	01	30
	329	0	01	00
	330	0	01	10
	331	0	02	00
	338	0	01	24
	339	0	03	70
	340	0	00	77
	341	0	00	50
	348	0	01	26
	353	0	00	10
	351	0	00	22
	350/A/B	0	05	70
	416	0	03	19
	415	0	05	25
	414	0	01	25
	413	0	01	87
	420	0	05	20
	411	0	00	09
	410	0	00	04
	409	0	03	60
	Cart track	0	01	60
	489	0	01	91
	525	0	00	12
	524	0	00	06
	490	0	02	78
	523	0	00	80
	518	0	01	18
	517	0	00	85
	511	0	04	20
	513	0	00	35
	510	0	01	00
	512	0	01	00
	493	0	01	90
	496	0	05	40
	497	0	07	27
	Cart track	0	01	39
	562	0	05	58
	563	0	00	27
	561	0	04	30
	566	0	04	30
	Cart track	0	02	61
	724	0	05	95
	726	1	27	20
	509	0	01	19
	498	0	02	00
	560	0	00	50

[No. O-12016/70/92-O.N.G.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का. भा. 1049.—यह : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 2037 तारीख 1-8-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों की बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, योजना के प्रकाशन की इस तारीख की लिहित होगी।

अनुसूची

नाडा - 1 से जी एन ए क्यू तक पाइप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - भरुच तालुका - जंबुसर

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	घार.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
नाडा	956	0	05	45
	968	0	04	50
	967	0	02	35
	966	0	01	00
	965	0	00	90
	948/पी	0	0	75
	948/पी	0	01	30
	1029	0	01	60
	1030	0	01	70
	1103	0	04	45
	1104	0	01	05
	1105	0	00	75
	1106	0	01	70
	1107	0	00	83
	1108	0	06	50
	1115	0	01	38
	1117	0	04	45
	1173	0	02	15
	1174	0	01	67
	1175	0	02	35
	1640	0	02	22
	1210	0	08	52
	1223	0	12	73
	1222	0	00	20
	1225	0	07	00
	1230	0	04	40
	1229	0	04	40
	1464	0	06	55
	1517	0	00	70
	1518	0	05	90

New Delhi, the 21st April, 1993

S.O. 1049.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 2037, dated 1-8-1992 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition, of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Nada-1 to Gnaq

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Nada	956	0	05	45
	968	0	04	50
	967	0	02	35
	966	0	01	00
	965	0	00	90
	948/P	0	03	75
	948/P	0	01	30
	1029	0	01	60
	1030	0	01	70
	1103	0	04	45
	1104	0	01	05
	1105	0	00	75
	1106	0	01	70
	1107	0	00	83
	1108	0	06	50
	1115	0	01	28
	1117	0	04	45
	1173	0	02	15
	1174	0	01	67
	1175	0	02	25
	1640	0	02	22
	1220	0	08	52
	1223	0	12	73
	1222	0	00	20
	1225	0	07	00
	1230	0	04	00
	1229	0	04	40
	1464	0	06	55
	1517	0	00	70
	1518	0	05	90

[सं. ओ - 12016/65/92 - ओ एन जी डी - 4]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

[No. O-12076/68/92-ONGD-IV]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1992

का. प्रा. 1050.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का.प्रा.सं. 1350 तारीख 13-5-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ए.बी.जी.एल.टी. बिन्दु से गुजरात गारडीयन तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भारुच तालुका : कालिया

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
कोन्ध	1233	0	30	40
	1234	0	31	10

1	2	3	4	5
	1225	0	55	30
	1240	0	49	10
	1244	0	39	20
	1246	0	13	85
	1247	0	12	90

[सं. ओ-12016/21/92-ओ.एन.जी.डी.-4]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 1993

S.O. 1050.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. No. 1350, dated 13-5-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Comptent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Abgl 'T' Point to Gujarat Guardian

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Valia

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centi-tiare
Kondh	1233	0	30	40
	1234	0	31	10
	1225	0	55	30
	1240	0	49	10
	1244	0	39	20
	1246	0	13	85
	1247	0	12	90

[No. O-12016/21/92/ONGD-IV]

M. MARTIN, Desk Officer.

का.भा. सं. 1051.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.भा.सं. 1440 तारीख 24-4-92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप-लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

टी पाइन्ट से कलोल जी जी एस-2 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला और तालुका महेसाणा

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेंटीयर
गमानपुरा	654		05	40
	655	0	10	60
	656	0	14	40
	657	0	08	80
	667	0	21	40
	668	0	12	80
	669	0	06	00
	672	0	14	80
	671	0	07	80

1	2	3	4	5
	673	0	05	20
	707	0	20	20
	706 पी	0	11	80
	706 पी	0	13	90
	कार्ट ट्रैक	0	01	40
	725	0	04	18
	724	0	05	39
	726	0	08	52
	727 पी	0	10	00
	727 पी	0	10	40
	कार्ट ट्रैक	0	08	60
	731	0	12	00
	739	0	09	20
	740	0	07	20
	742	0	02	00
	747	0	12	60
	746 पी	0	20	82
	751	0	13	08
	कार्ट ट्रैक	0	07	40
	248	0	24	00

[सं. ए ओ-12016/184/91-ओ एन जी सी-4]

एम. माटिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 1993

S.O. 1051.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 1440, dated 24-4-92 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section(1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE
Pipeline from T. Point to Balol GGS-II

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Centi- tiare
1	2	3	4	5
Gamanpura	654	0	05	40
	655	0	10	60
	656	0	14	40
	657	0	08	80
	667	0	21	40
	668	0	12	80
	669	0	06	00
	672	0	14	80
	671	0	07	80
	673	0	05	20
	707	0	20	20
	706/P	0	11	80
	706/P	0	13	90
	Cart track	0	01	40
	725	0	04	18
	724	0	05	39
	726	0	08	52
	727/P	0	10	00
	727/P	0	10	40
	Cart track	0	08	60
	731	0	12	00
	739	0	09	20
	740	0	07	20
	742	0	02	00
	747	0	12	60
	746/P	0	20	82
	751	0	13	08
	Cart track	0	07	40
	248	0	24	00

[No. O-12016/184/91/O.N.GD-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का.प्रा. 1052 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 432 तारीख 9-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार

पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ई पी एस से अंकलेश्वर सी टी एफ तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
खोजबल	261	0	45	20
	263	0	22	35
	264	0	09	56
गाडावाट		0	12	60
265		0	13	26
गाडावाट		0	05	00
242		0	12	30
239		0	42	80
238		0	37	96
286		0	38	40
237		0	13	44
236		0	12	40
235		0	26	95
234		0	21	50
297		0	22	00
298		0	13	20
299		0	30	10
329		0	12	80
328		0	11	15
327		0	17	00
326		0	10	52
332		0	00	30
331		0	24	96
338		0	09	85
420	1	44	80	
419	0	14	00	
418	0	15	20	
417	0	09	90	
3	0	03	60	
24	0	13	79	
25	0	16	00	

1	2	3	4	5
	23	0	15	80
	27	0	22	21
	28	0	00	30
	31	0	15	75

[सं. ओ-11027/208/90/ओ एन जी डी-3]

एम. मार्टिन, डेस्क ऑफिसर

New Delhi, the 21 April 1993

S.O. 1052.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O. No. 432, dated 9-2-1991 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the Schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from E.P.S. to Ankleshwar CTF

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Bloc No.	Hectre	Are	Centre
1	2	3	4	5
Khojbat	261	0	45	20
	263	0	22	35
	264	0	09	56
	Cart track	0	12	60
	265	0	13	26
	Cart track	0	05	00
	242	0	12	30
	239	0	42	80
	238	0	37	96
	286	0	38	40
	237	0	13	34
	236	0	12	40
	235	0	26	95
	234	0	21	50
	297	0	22	00
	298	0	13	20
	299	0	30	10
	329	0	12	80
	328	0	11	15

1	2	3	4	5
	327	0	17	00
	326	0	10	52
	332	0	00	30
	331	0	24	96
	338	0	09	85
	420	1	44	80
	419	0	14	00
	418	0	15	20
	417	0	09	90
	3	0	03	60
	24	0	13	79
	25	0	16	00
	23	0	15	80
	27	0	22	21
	28	0	00	30
	31	0	15	75

[No. O-11027/208/90/O.N.G.D-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का. भा. 1053.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.भा.सं. 431 तारीख 9-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ई पी एस से अंकलेश्वर सी टी एफ तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात

जिला व तालुका : भरुच

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	अर.	सेटयर
1	2	3	4	5
भाडभुट	277	0	07	80
	278	0	23	55
	279	0	05	00
	280	0	07	30
	286	0	18	00
	285	0	11	45
	284	0	14	30
	283	0	05	80
	266	0	19	45
	267	0	19	45
	261	0	09	00
	260	0	10	25
	259	0	09	71
	258	0	15	70
	302	0	00	14
	303	0	22	20
गाडावाट	0	07	20	
304	0	31	00	
306	0	08	90	
305	0	08	55	
310	0	30	05	
322	0	04	45	
321	0	50	40	
333	0	08	40	
317	0	04	30	
334	0	21	55	
335	0	12	28	
336	0	03	40	
338	0	00	48	
337	0	50	25	
375	0	47	05	
376	0	04	50	
369	0	33	20	
370	0	11	80	
गाडावाट	0	04	20	
438	0	22	30	
439	0	15	20	
320	0	13	10	

[सं. ओ-11027/207/90-ओ एन जी डी-3]

एम माटिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 1993

S.O. 1053.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 431 dated 9-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from F.P.S. to Ankleshwar CTF

State : Gujarat

District & Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Bhadbhut	277	0	07	80
	278	0	23	55
	279	0	05	00
	280	0	07	30
	286	0	18	00
	285	0	11	45
	284	0	14	30
	283	0	05	80
	266	0	19	45
	267	0	19	45
	261	0	09	00
	260	0	10	25
	259	0	09	71
	258	0	15	70
	302	0	00	14
	303	0	22	20
	Cart track	0	07	20
	304	0	31	00
	306	0	08	90
	305	0	08	55
	310	0	30	05
	322	0	04	45
	321	0	50	40
	333	0	08	40
	317	0	04	30
	334	0	21	55
	335	0	12	28
	336	0	03	40
	338	0	00	48
	337	0	50	25
	375	0	47	05
	376	0	04	50
	369	0	33	20
	370	0	11	80

1	2	3	4	5
	Cart track	0	04	20
	438	0	22	30
	439	0	15	20
	320	0	13	10

[No. O-11027/207/90/O.N.G.D.-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का आ. 1034.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 430 तारीख 9-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इन तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ई पी एस में अंकलेश्वर सी टी एफ तक पाइप लाइनों को बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात		जिला व तालुका : भरुच		
गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
एकसाल	2	0	77	53
	3	0	17	70
	27	0	51	92

1	2	3	4	5
	26	0	19	00
	67	0	31	45
गाडावाट		0	03	00
131		0	06	00
132		0	06	50
132		0	07	00
129		0	04	50
137		0	07	11
138		0	02	90
136		0	00	09
139		0	14	51
142		0	05	40
140		0	11	10
114/ए/बो		0	09	90
113		0	20	90
110		0	00	50
111		0	28	31
गाडावाट		0	04	20
252		0	02	75
250		0	17	85
251		0	09	45
249		0	28	50
248		0	24	60
247		0	00	05
243		0	06	51
242		0	00	52
317		0	04	20
320		0	00	05
319		0	07	45
318		0	09	20
325		0	25	80
326		0	17	30
327		0	04	30

[सं. ओ-11027/206/90/ओ एन जी डी-3]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 1993

S.O. 1054.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 430 dated 9-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from F.P.S. to Ankleshwar CTF

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
1	2	3	4	5
Ekshal	2	0	77	53
	3	0	17	70
	27	0	51	92
	20	0	19	00
	67	0	31	45
	Cart track	0	03	00
	131	0	06	00
	132	0	06	50
	135	0	07	00
	129	0	04	50
	137	0	07	11
	138	0	02	90
	136	0	00	09
	139	0	14	51
	142	0	05	40
	140	0	11	10
	114/A/B	0	09	90
	113	0	20	90
	110	0	00	50
	111	0	28	31
	Cart track	0	04	20
	252	0	02	75
	250	0	17	85
	251	0	09	45
	249	0	28	50
	248	0	24	60
	247	0	00	05
	243	0	06	51
	242	0	00	52
	317	0	04	20
	320	0	00	05
	319	0	07	45
	318	0	09	20
	325	0	25	80
	326	0	17	30
	327	0	04	30

[No. O-11027/206/90/O.N.G.D.-III]

M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का.ग्रा. 1055.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.ग्रा.सं. 491 तारीख 16-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने

के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

और अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

चोकारी टी बिन्दु से जिनको तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : बड़ोदा तालुका : बड़ोदा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेंटीयर
हिंगलोड	107	0	03	19
	104	0	22	00
	कार्ट ट्रैक	0	03	65
	92/के/बी	0	52	00
	कार्ट ट्रैक	0	02	27
	88	0	22	38
	87	0	30	49
	86	0	06	00
	76	0	19	60

[सं. ओ-11027/205/90/ओ ए. जी. डी.-III]

एस. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 1993

S.O. 1055.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 491 dated 16-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Chokari T. Point to Gipco (Revised)
State : Gujarat District & Taluka : Vadodara

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Hinglot	107	0	03	19
	104	0	22	00
	Cart track	0	03	65
	92/K/B	0	52	00
	Cart track	0	02	27
	88	0	22	38
	87	0	30	49
	86	0	06	00
	76	0	19	60

[No.O-11027/205/90/O.N.G.D.-III]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का.आ. 1056.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 493 तारीख 16-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न

अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभा बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

प्रदेश से जिफको तक पाईप लाईन बिछाने के लिए
(सुधारने के बाद)

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : बड़ोदा

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सेंटीयर
1	2	3	4	5
कोयली	गाडावाट	0	01	60
	450/1	0	00	30
	450/2	0	04	13
	451	0	02	78
	452	0	10	66
	453	0	02	77
	454	0	07	47
	455	0	12	46
	474/4	0	22	64
	474/2	0	06	00
	474/1	0	01	50
	483	0	23	01
	488	0	02	79
	489/1	0	05	00
	489/2	0	08	00
	गाडावाट	0	02	55
	500	0	12	46
	502	0	16	71
	504	0	16	71
	505	0	05	85
	गाडावाट	0	02	70
	549	0	02	70
	549	0	20	36
	562	0	30	33
	572	0	04	70
	573	0	21	72
	583	0	01	18
	581	0	24	11
	585	0	13	76
	गाडावाट	0	01	40

1	2	3	4	5
	587	0	08	00
	गाडावाट	0	03	80
	840	0	14	46
	गाडावाट	0	03	40
	773	0	11	40
	775	0	11	60
	गाडावाट	0	01	00
	776	0	13	06
	776/1	0	19	72
	777/2/ए	0	07	05
	गाडावाट	0	01	20
	821	0	11	14
	822	0	02	83
	820/1	0	08	90
	819	0	08	30
	818	0	08	15
	817	0	02	00
	गाडावाट	0	05	50
	814	0	15	20
	गाडावाट	0	01	40
	938/1	0	14	16
	938/2	0	01	24
	गाडावाट	0	02	70
	940/1	0	14	56
	934	0	04	80
	987/2	0	07	20
	986	0	29	26
	गाडावाट	0	01	20
	1050/3	0	05	00
	1050/2	0	00	34
	1048	0	05	19
	1047	0	07	60
	1042	0	28	28
	1043	0	14	20
	1087/1	0	13	10
	1081	0	20	15
	1088	0	25	56
	1080	0	04	88

[सं. ओ-11027/203/90/ओ एन जी डी-III]

एम. माटिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 1993

S.O. 1056.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 493 dated 16-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user

in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Undera to Gipco R(evised)

State : Gujarat

District & Taluka : Vadodara

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Koyli	Cart track	0	01	60
	450/1	0	00	30
	450/2	0	04	13
	451	0	02	78
	452	0	10	66
	453	0	02	77
	454	0	07	47
	455	0	12	46
	474/4	0	22	64
	474/2	0	06	00
	474/1	0	01	50
	483	0	23	01
	488	0	02	79
	489/1	0	05	00
	489/2	0	08	00
	Cart track	0	02	55
	500	0	12	46
	502	0	16	71
	504	0	16	71
	505	0	05	85
	Cart track	0	02	70
	549	0	02	70
	549	0	20	36
	562	0	30	33
	572	0	04	70
	573	0	21	72
	583	0	01	18
	581	0	24	11
	585	0	13	76
	Cart track	0	01	40
	587	0	08	00
	Cart track	0	03	80
	840	0	14	46
	Cart track	0	03	40
	773	0	11	40
	775	0	11	60
	Cart track	0	01	00
	776	0	13	06
	777/1	0	19	72
	777/2/A	0	07	05
	Cart track	0	01	20
	821	0	11	14

2	3	4	5
822	0	02	83
820/1	0	08	90
819	0	08	30
818	0	08	15
817	0	02	00
Cart track	0	05	50
814	0	15	20
Cart track	0	01	40
938/1	0	14	16
938/2	0	01	24
Cart track	0	02	70
940/1	0	14	56
934	0	04	80
987/2	0	07	20
986	0	29	26
Cart track	0	01	20
1050/3	0	05	00
1050/2	0	00	34
1048	0	05	19
1047	0	07	60
1042	0	28	28
1043	0	14	20
1081/1	0	14	10
1081	0	20	15
1088	0	25	56
1080	0	04	88

[No. O-11027/203/90-ONGD-III]

M. MARTIN, Desk officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का.आ. 1057 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 492 तारीख 16-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में

सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

उदर से जिप्को तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला और तालुक : बड़ौदा

गांव	से.न.	है.	आर.	सेण्टी
धनोरा	118	0	19	20

[सं. ओ-11027/204/90/ओ. एन. जी. डी.-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 1993

S.O. 1057.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 492 datd 16-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from Undera to Gipco (Revised)

STATE : GUJARAT DISTRICT & TALUKA :
VADODARA

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Dhanora	118	0	19	20

[No. O-11027/204/90/O.N.G.D.-III]

M. MARTIN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का.आ.1058:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 429 तारीख 4-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

चोकारी टी बिन्दु से जिपको तक पाईप लाईन बिछाने लिए (तथा)

राज्य : गुजरात जिला : वाडोदा त : पादरा

गांव	सर्वे नं.	हे.	आर.	सेन्टी
1	2	3	4	5
डन्का	243	0	10	80
	240	0	18	64
	239	0	12	60
	232	0	06	80
	231	0	20	00
कार्ड ट्रैक		0	02	00
	225	0	15	60
	226	0	16	00
कार्ड ट्रैक		0	03	60
	194	0	01	25
	183	0	13	75
	184	0	13	00
	185	0	20	75
	179	0	15	25
कार्ड ट्रैक		0	02	20
	172	0	01	20
	173	0	20	00
	171	0	06	00
	170	0	27	00
	166	0	15	60
	165	0	02	50
	422	0	15	40
	423	0	03	00

1	2	3	4	5
	421	0	01	26
	424	0	12	36
	425	0	13	87
कार्ड ट्रैक		0	03	00
	405	0	05	21
कार्ड ट्रैक		0	03	87
	404	0	09	75
	431	0	00	50
	403	0	22	20
	399	0	04	00
	398	0	00	25
	400	0	09	00
	393	0	16	00
	445	0	06	00

[सं. ओ-11027/202/90 ओ. एन. जी. डी-III]

- एम मार्टिन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 1993

S. O. 1058.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 429 dated 9-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Chokari 'T' Point to Undera

State : Gujarat	District : Vadodara	Taluka : Padra		
Village	Block No.	Hec-tare	Are	Cent-tiare
1	2	3	4	5
Dabka	243	0	10	80
	240	0	18	64
	239	0	12	60
	232	0	06	80
	231	0	20	00
	Cart track	0	02	00
	225	0	15	60
	226	0	16	00

1	2	3	4
Debka (Contd.)	Cart track	0	03 60
	194	0	01 25
	183	0	13 75
	184	0	13 00
	185	0	20 75
	179	0	15 25
	Cart track	0	02 20
	172	0	01 20
	173	0	20 00
	171	0	06 00
	170	0	27 00
	166	0	15 60
	165	0	02 50
	422	0	15 40
	423	0	03 00
	421	0	01 26
	424	0	12 36
	425	0	13 87
	Cart track	0	03 00
	405	0	05 21
	Cart track	0	03 87
	404	0	09 75
	431	0	00 50
	403	0	22 20
	399	0	04 00
	398	0	00 25
	400	0	09 00
	393	0	16 00
	445	0	06 00

[No. O-11027/202/90/O.N.G.D.-III]

M. Marti, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का.आ. 1059:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 490 तारीख 16-2-91 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

चोकारी टी बिन्दु से जिप्को तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : बड़ोदा	ता. पादरा
गांव	सर्वे न.	है. भार० सेंटी०
नरसीपुरा	187	0 14 05
	236	0 08 60
	237	0 23 65
	231	0 05 25
	230	0 05 85
	249	0 14 55
	250	0 16 30
	259	0 01 00
	कार्ट ट्रैक	0 00 60
	260	0 05 40
	261	0 07 58
	262	0 09 70
	265	0 09 60
	264	0 10 40

[सं.-O-11027/201/90/ओ एन.जी.डी.-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 1993

S.O. 1059.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 490 dated 16-2-91 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Chokari 'T' Point to Undera Gipco (Revised)

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padara

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Centi- tiare
Narsipura	187	0	14	05
	236	0	08	60
	237	0	23	65
	231	0	05	25
	230	0	05	85
	249	0	14	55
	250	0	16	30
	259	0	01	00
	Cart track	0	00	60
	260	0	05	40
	261	0	07	58
	262	0	09	70
	265	0	09	60
	264	0	10	40

[No. O-11027/201/90/ONGDIH]
M. MARTIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1993

का.आ.1060:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 3147 तारीख 24-11-90 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट द दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार ने निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

ई. पी. एस. से अंकलेश्वर सी.टी.एफ. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भारुच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
पिलोदरा	198	0	36	20
	196	0	07	25

[सं. ओ-11027/124/90-ओ. एन. जी. डी.-III]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st April, 1993

S.O. 1060.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 3147 dated 24-11-90 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from E.P.S. to Ankleshwar CTF

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Centi- tiare
Pilodara	198	0	36	20
	196	0	07	25

[No. O-11027/124/90/ONGDIH]

M. MARTIN, Desk Officer

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1993

का. आ. 1061 :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श

करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती, अर्थात् :—

1. उक्त अनुसूची में :—

- (i) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संबंधित प्रविष्टियों में “डाक्टर आफ मेडिसिन (सामुदायिक आयुर्विज्ञान) एम. डी. (सा. वि.)” प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “मास्टर आफ सर्जरी, (शरीर रचना विज्ञान) एम. एम. (श. र. वि.)
- मास्टर आफ सर्जरी
(नेत्र विज्ञान) एम. एम. (नेत्र वि.)
- मास्टर आफ मेडिसिन
(सूक्ष्म जीव विज्ञान) एम. डी.
(सू. जी. वि.)
- डाक्टर आफ मेडिसिन
(प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)
एम. डी. (प्र. वि. और स्त्री रोग वि.)
- डिप्लोमा इन गायनाकोलाजी एंड आबमेट्रिक्स
..... डी. जी. ओ.
- (ii) आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में संबंधित प्रविष्टियों में “डिप्लोमा इन न्याय आयुर्विज्ञान डी. एफ. एम.” प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथालॉजी
डी. सी. पी.
- डाक्टर आफ मेडिसिन (डर्माटोलोजी)
एम. डी. (डर्मा.)
- डिप्लोमा इन डर्माटोलोजी डी. डी.
- (iii) कलकत्ता विश्वविद्यालय में संबंधित प्रविष्टियों में, “मास्टर आफ सर्जरी (प्लास्टिक शल्य विज्ञान) एम. एम. (प्ला. श. वि.)” प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “डाक्टर आफ मेडिसिन (फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन) एम. डी. (फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन)
- डाक्टर आफ मेडिसिन [ट्रोपिकल मेडिसिन]
एम. डी. (ट्रोपिकल मेडिसिन)
- (iv) कालीकट विश्वविद्यालय में संबंधित प्रविष्टि में “डाक्टर आफ मेडिसिन अनेस्थेसियोलोजी एम. डी. (अनेस्थ.)” प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“डाक्टर आफ मेडिसिन
(विकृति विज्ञान) एम. डी. (वि. वि.)

मास्टर आफ सर्जरी
(जनन मृत्र शल्य विज्ञान) एम. सी. एन.
(जनन मृ. श. वि.)

मास्टर आफ सर्जरी
(बाल शल्य विज्ञान) एम. सी. एन. (बा. श. वि.)

मास्टर आफ सर्जरी
(प्लास्टिक शल्य विज्ञान) एम. सी. एन.
(प्ला. श. वि.)

मास्टर आफ सर्जरी
(वक्ष शल्य विज्ञान) एम. सी. एन.
(वक्ष श. वि.)

- (v) गुजरात विश्वविद्यालय में संबंधित प्रविष्टियों में मास्टर आफ सर्जरी (शरीर रचना विज्ञान) एम. एम. (श. र. वि.)

प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“डाक्टर आफ मेडिसिन (डर्माटोलोजी) एम. डी. (डर्मा.)

- (vi) गुलबर्ग विश्वविद्यालय में संबंधित प्रविष्टियों में “डिप्लोमा इन अनेस्थेसिया डी. ए.” प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान) एम. डी. (बा. चि. वि.) डिप्लोमा इन चार्टर्ड हेल्थ डी. सी. एन.”

- (vii) महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में संबंधित प्रविष्टियों में “डाक्टर आफ मेडिसिन (शरीर क्रिया विज्ञान) एम. डी. (श. क्रि. वि.)” प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“डाक्टर आफ मेडिसिन एम. डी.
(वि. वि.) विकृति विज्ञान

डाक्टर आफ मेडिसिन

(बाल चिकित्सा विज्ञान) एम. डी.
(बा. चि. वि.)

डिप्लोमा इन चार्टर्ड हेल्थ डी. सी. एन.

- (viii) गोवा विश्वविद्यालय में संबंधित प्रविष्टियों में (डाक्टर आफ मेडिसिन/बाल चिकित्सा विज्ञान) एम. डी. (बा. चि. वि.)” प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

“डाक्टर आफ मेडिसिन (गर्भमा और वक्ष रोग विज्ञान) एम. डी. (ग. और व. रोग वि.)

डाक्टर आफ मेडिसिन
(प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान)
... एम. डी. (प्र. वि. और स्त्री रोग वि.)
डाक्टर आफ मेडिसिन
(शरीर क्रिया विज्ञान) ... एम. डी. (श. क्रि. वि.)"

(ix) देवी ग्रहिल्या विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में
"डाक्टर आफ मेडिसिन (अनेस्थेसियोलॉजी) ...
एम. डी. (अनेस्थे.)", प्रविष्टि के पश्चात् निम्न-
लिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
"डिप्लोमा इन गायनाकोलॉजी एंड ग्राइमेट्रिकल
... डी. जी. आ."

(x) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से
संबंधित प्रविष्टियों में, "डिप्लोमा इन आर्थोपेडिकल
... डी. आर्थो."

प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित
की जाएगी, अर्थात् "डिप्लोमा इन गायनाकोलॉजी
एंड ग्राइमेट्रिकल ... डी. जी. ओ."

(xi) केरल विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में
"डाक्टर आफ मेडिसिन (तंत्रिका विज्ञान) ...
... डी. एम. (न. वि.)"

प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः
स्थापित की जाएंगी, अर्थात् "मास्टर आफ सर्जरी
... एम. सी. एच."

प्लास्टिक शल्य विज्ञान (प्ला. श. वि.)

डाक्टर आफ मेडिसिन ... एम. डी.

(रेडियो डायग्नोसिस) (रेडि. डाय.)

डिप्लोमा इन मेडिकल

रेडियो डायग्नोसिस ... डी. एम. ए. आर. डी.

(xii) कर्नाटक विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में
"डिप्लोमा इन आफथोलमायोलॉजी ... डी. ओ."
प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः
स्थापित की जाएंगी, अर्थात् "मास्टर आफ सर्जरी
... एम. एस."

शरीर रचना विज्ञान (श. र. वि.)

डाक्टर आफ मेडिसिन ...

(अनेस्थेसियोलॉजी ... एम. डी. अनेस्थे.)

डिप्लोमा इन अनेस्थेसियोलॉजी ... डी. ए. (अनेस्थे.)"

(xiii) लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में
"डाक्टर आफ मेडिसिन (सामान्य आयुर्विज्ञान)
एम. डी. (स. आ.)" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित
प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् "डाक्टर
आफ मेडिसिन

(हृदय रोग विज्ञान) ... डी. एस

(... वि.)"

(XIV) मंगलौर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में
"डिप्लोमा इन चार्ड्ड हेल्थ ... डी. सी. एच."
प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः
स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"डाक्टर आफ मेडिसिन ... डी. एम. (हृ. रोग वि.)
(हृदय रोग विज्ञान)"

(XV) नागपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में
"मास्टर आफ सर्जरी ... (कर्ण, नासा, और कंठ
विज्ञान) एम. एस. (क. ना. कं. वि.)"
प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः
स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"डाक्टर आफ मेडिसिन ... एम. डी.
(न्या. आ. वि.) (न्याय आयुर्विज्ञान)"

(XVI) उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में
"मास्टर आफ सर्जरी विकलांग विज्ञान ...
एम. एस. (वि. वि.)"
प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतः
स्थापित की जाएंगी, अर्थात्
"डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथालॉजी ...
डी. सी. पी."

"डाक्टर आफ मेडिसिन (डर्मटोलॉजी) ...
एम. डी. (डर्मा)

डिप्लोमा इन डर्मटोलॉजी ... डी. डी."

(XVII) पांडिचेरी विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में
"डाक्टर आफ मेडिसिन (बाल चिकित्सा विज्ञान
एम. डी. (बा. वि. वि.)" प्रविष्टि के पश्चात्
निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी
अर्थात् :—

"डाक्टर आफ मेडिसिन ... एम. डी. (सा. आ.)
(सामुदायिक आयुर्विज्ञान)

(XVIII) राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में
"मास्टर आफ सर्जरी (तंत्र शल्य विज्ञान) ...
एम. सी. एच. (त. श. वि.)" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित
की जाएगी, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (बाल शल्य विज्ञान)
(एम. सी. एच. (बा. श. वि.)"

(XIX) रांची विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में
"डिप्लोमा इन अनेस्थेसियोलॉजी ... डी. ए."
प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः
स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"डाक्टर आफ मेडिसिन (मनोरोग विज्ञान)
... एम. डी. (म. वि.)"

(XX) रवि शंकर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विज्ञान) . . . एम. एस. (वि. वि.)

प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"डिप्लोमा इन चार्ड्ड हेल्थ, डी. सी. एच."

(XXI) सोराष्ट्र विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विज्ञान) . . . एम. एस. (वि. वि.)

प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टिया अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"मास्टर आफ सर्जरी (नेत्र विज्ञान) . . . एम. एस. (ने. वि.)

मास्टर आफ सर्जरी (विकलांग विज्ञान) . . . म. एस. (वि. वि.)

(XXII) दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में (डिप्लोमा इन आफ्योलमालोजी डी. ओ. (ने. वि.)

प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टिया अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् : "डाक्टर ऑफ मेडिसिन (अनेस्थेसियोलॉजी) . . . एम. डी. (अनेसन) डिप्लोमा इन अनेस्थेसियोलॉजी डी. ए."

(XXIII) उत्कल विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों में "डाक्टर आफ मेडिसिन (अनेस्थेसियोलॉजी) एम. डी. अनेस्थे)"

प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"डाक्टर ऑफ मेडिसिन" प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान एम. डी. (प्र. वि. और स्त्री. रोग. वि.)

2(1) उक्त अनुसूची में, अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टियों अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"अमरावती विश्वविद्यालय :

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी एम. बी. बी. एस.

(2) अन्नामलाई विश्वविद्यालय :

बैचलर आफ मेडिसिन एण्ड बैचलर आफ सर्जरी एम. बी. बी. एस.

[फा. सं. बी. 11015 /56 /92 /एम ई (यु.जी.)]
आर. विजयकुमारी, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 29th April, 1993

S.O. 1061.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Indian Medical Council Act,

1956 (102 of 1956), the Central Government after consulting the Medical Council of India hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :

1. In the said Schedule :

(i) In the entries relating to Aligarh Muslim University, after the entry "Doctor of Medicine (Community Medicine—M. D. (Community Medicine))" the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Anatomy)—M. S. (Anatomy)
Master of Surgery (Ophthalmology)—M. S. (Ophthalmology)

Doctor of Medicine (Microbiology)—M. D. (Microbiology)

Doctor of Medicine (Obstetrics and Gynaecology—M. D. (Obst. and Gynae.)

Diploma in Gynaecology and Obstetrics—M. G.O.

(ii) In the entries relating to Andhra Pradesh University of Health Sciences after the entry "Diploma in Forensic Medicine—DFM, the following entries shall be inserted namely :—

"Diploma in Clinical Pathology—D.C.P.

Doctor of Medicine (Dermatology)—M. D. (Derm.)

Diploma in Dermatology—D.D.

(iii) in the entries relating to the University of Calcutta after the entry "Master of Surgery (Plastic-Surgery)—M. Ch. (Plastic-Surgery)" the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Physical Medicine & Rehabilitation)—M. D. (Physical Medicine & Rehabilitation).

Doctor of Medicine (Tropical Medicine)—M. D. (Tropical Medicine)"

(iv) in the entries relating to Calcutta University after the entry "Doctor of Medicine (Anaesthesiology)—M. D. (Anaes)" the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Pathology)—M.D. (Pathology)

Master of Surgery (Genito-Urinary-Surgery)—M. Ch. (Genito-Urinary-Surgery).

Master of Surgery (Paediatric Surgery)—M. Ch. (Paediatric Surgery).

Master of Surgery (Plastic Surgery)—M. Ch. (Plastic Surgery).

Master of Surgery (Thoracic Surgery)—M. Ch. (Thoracic Surgery)"

(v) in the entries relating to the University of Gujarat after the entry "Master of Surgery (Anatomy)—M. S. (Anatomy)", the following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Dermatology)—M.D. (Derm)"

(vi) in the entries relating to Gulbarga University, after the entry "Diploma in Anesthesia—D.A.", the following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Paediatrics)—M.D. (Paed.)

Diploma in Child Health—M.C.H."

(vii) in the entries relating to Mahatma Gandhi University after the entry "Doctor of Medicine (Physiology)—M. D. (Physiology) the following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Pathology)—M.D. (Pathology)

Doctor of Medicine (Paediatrics)—M.D. (Paed.)

Diploma in Child Health—D.C.H.

(viii) in the entries relating to Goa University, after the entry "Doctor of Medicine (Paediatrics)—M.D. (Paed.)" the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Tuberculosis & Chest Diseases)—M.D. (Tuberculosis & Chest Diseases).

Doctor of Medicine (Obstetrics & Gynaecology) M. D. (Obst. & Gynaec.)

Doctor of Medicine (Physiology)—M.D. (Physiology)"

(ix) in the entries relating to Devi Ahilya Vishwavidyalaya after the entry "Doctor of Medicine (Anaesthesiology)—M. D. (Anaes.)" the following entry shall be inserted, namely :—

"Diploma in Gynaecology and Obstetrics—D.G.O."

(x) in the entries relating to Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur, after the entry "Diploma in Orthopaedics—D. (Ortho)", the following entry shall be inserted, namely :—

"Diploma in Gynaecology and Obstetrics—D.G.O."

(xi) in the entries relating to University of Kerala after the entry "Doctor of Medicine (Neurology)—D.M. (Neurology)" the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Plastic Surgery)—M. Ch. (Plastic Surgery)

Doctor of Medicine (Radio-Diagnosis)—M. D. (Radio-Diag.)

Diploma in Medical Radiology Diagnosis—D.M.R.D."

(xii) in the entries relating to University of Karnataka after the entry "Diploma in Ophthalmology—D.O." the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Anatomy)—M. S. (Anatomy)—

Doctor of Medicine (Anaesthesiology)—M. D. (Anaes.)

Diploma in Anaesthesiology—D.A.(Anaes)"

(xiii) in the entries relating to University of Lucknow after the entry "Doctor of Medicine (General Medicine)—M.D. (Gen. Med)" the following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicines (Cardiology)—D.M. (Cardiology)"

(xiv) in the entries relating to Mangalore University after the entries "Diploma in Child Health—D.C.H." the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Cardiology)—D.M.(Cardiology)"

(xv) in the entries relating to University of Nagpur after the entry "Master of Surgery (Orthopaedics)—M.S. (Ortho.)" following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Forensic Medicine)—M.D. (Forensic Medicine)"

(xvi) in the entries relating to University of Osmania after the entry "Master of Surgery (Orthopaedics)—M.S. (Ortho.)" the following entries shall be inserted, namely :—

"Diploma in Clinical Pathology—D.C.P.

Doctor of Medicine (Dermatology)—M.D.(Derm.)

Diploma in Dermatology...D.D."

(xvii) in the entries relating to Pondicherry University after the entry "Doctor of Medicine (Paediatrics)—M.D. (Paed.)" the following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine—M.D. Community Medicine (Community Medicine)".

(xviii) in the entries relating to University of Rajasthan after the entry "Master of Surgery (Neuro Surgery)—M.Ch. (Neuro-Surgery)" the following entry shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Paediatric Surgery)—M.Ch. (Paediatric Surgery)

(xix) in the entries relating to Ranchi University after the entry "Diploma in Anaesthesiology—D.A.", the following entry shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Psychiatry)—M.D. (Psychiatry)"

(xx) in the entries relating to Ravishankar University after the entry "Master of Surgery (Orthopaedics)—M.S. (Ortho)" the following entry shall be inserted, namely :—

"Diploma Child Health—D.C.H."

(xxi) in the entries relating to Saurashtra University after the entry "Master of Surgery (Orthopaedics)—M.S. (Ortho.)" the following entries shall be inserted, namely :—

"Master of Surgery (Ophthalmology)—M.S. (Ophth.)

"Master of Surgery (Orthopaedics)—M. S. (Ortho)

(xxii) in the entries relating to South Gujarat University after the entry "Diploma in Ophthalmology—D.O.", the following entries shall be inserted, namely :—

"Doctor of Medicine (Anaesthesiology)—M.D. (Anaes.)

(xxiii) In the entries relating to University of Utkal after the entry "Doctor of Medicine (Anaesthesiology)—M.D. (Anaes)" the following entry shall be inserted, namely :—

Doctor of Medicine (Obstetrics & Gynaecology)—M.D. (Obst. & Gynaec.)"

2. In the said Schedule, the following entries shall be inserted at the end, namely :—

(i) "AMRAVATI UNIVERSITY :—

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery—M.B.B.S."

(ii) "ANNAMALAI UNIVERSITY :

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery—M.B.B.S."

R. VIJAYAKUMARI, Desk Officer

[No. V. 11015/56/92-ME(UG)]

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 मई, 1993

का.श्रा. 1062 :—यनः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार अध्यावर्णित क्षेत्रों के बारे में दिल्ली वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 02-02-93 के नोटिस संख्या एक. 16 (7)/90 एम.पी. द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-क में अपेक्षित आपत्तियों/सुझाव, उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे।

और यनः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की उक्त वृहद योजना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन :— "जोन डी-1 कनाट प्लेस एवं इसके विस्तार में पड़ने वाले तथा उत्तर में ईस्टर्न कोर्ट बिल्डिंग से, दक्षिण तथा पूर्व में आवासीय

क्षेत्र और एच.सी. माथुर लेन से तथा पश्चिम में 45 मीटर मार्गाधिकार जनपथ से घिरे लगभग 0.92 हेक्टेयर (2.777 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाओं से 'सरकारी कार्यालयों' में बदलने का प्रस्ताव है।

- (2) प्रस्ताव है कि केन्द्र के शहरी रूप को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय व्यवसाय जिला (महानगर केन्द्र अर्थात् कनाट प्लेस एवं इसके विस्तार) में भवन की अधिकतम ऊँचाई 50 मीटर तक रखने की अनुमति दी जाए।"

[सं. के-13011/7/92-डी डी-1-वी]

एस.सी. सागर, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

New Delhi, the 4th May, 1993

S.O. 1062.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder were published with Notice No. F. 16(7)/90-MP dated 2-2-93 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) of section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said Notice.

And whereas no objections/suggestions have been received with regard to the said proposed modification;

And whereas the Central Govt. have decided to modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11A of the said Act, the Central Govt. hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi w.e.f. the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION :

"The land use of an area, measuring 0.92 ha. (2.277 acres) in the Zone D-I (Connaught Place and its extension) and bounded by Eastern Court building in the North, residential area and H. C. Mathur Lane in the South and East, 45 mtr. r/w Janpath in the West is proposed to be changed from 'public and semi-public facilities' to 'Govt. officers'.

2. It is proposed that the maximum height of the building in the Central Business District (Metropolitan City Centre, i.e., Connaught Place and its Extension) could be permitted upto 50 mtrs., keeping in view the urban form of the Centre."

[No. K-13011/7/92-DDIB]

S. C. SAGAR, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 93

का.आ. 1063:—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एनडूडार मैमर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., बिशाखापट्टनम की स्वीकृति छूट तत्काल रद्द करते हैं जिसे भारत सरकार (श्रम व रोजगार विभाग)

(श्रम मंत्रालय, रोजगार व पुनर्वास की अधिगृहणा सं. एम.ओ. 3676 दिनांक 24 अक्टूबर, 1970 से श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और भारत के राजपत्र के भाग II धारा 3, उपधारा (ii) में दिनांक 14-11-70 को प्रकाशित किया गया।

[सं. एम-35017/1/91-एम एम-II]

जे.पी. शुक्ला, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 29th April, 1993

S.O. 1063.—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (4) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby cancels with immediate effect the exemption granted to M/s. Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam, vide Notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour & Employment) No. S.O. 3676, dated the 24th October, 1970 published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 14th November, 1970.

[No. S-35017(1)/91-SS-III]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1993

का.आ. 1064:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुमरण में, केन्द्रीय सरकार, मै. भारत कोलिंग कोल लि. की कुसुण्डा कोलियरी के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 2), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-4-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/136/87-डी-3 (ए) प्राईआर (काल-I)]

एच.सी. गोड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 30th April, 1993

S.O. 1064.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. II), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Kusunda Colliery of M/s. B.C.C.I. and their workmen which was received by the Central Government on 29-4-93.

[No. L-20012/136/87 DII(A)/IR(C.I)]

HARISH GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESIDENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

REFERENCE No. 107 OF 1991

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kusunda Area of M/s. B.C.C.L. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri J. P. Singh, Advocate.

On behalf of the employers : Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 15th April, 1993

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(136)/87-D.III (A)/IR(C-I), dated, the Nil.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Gondudih Colliery of Area No. VI (Kusunda Area) of M/s. B.C.C.L. in discontinuing from service Shri Yamuna Yadav and 25 other Badli Miner/Loaders on the ground that they were not genuine dependants of female delisted/enlisted casual wagon loaders is justified ? If not, to what relief the concerned persons are entitled ?"

2. All the concerned workmen 26 in Nos. are demanding their reinstatement with full back wages, plus other consequential benefits. Admittedly all were enrolled as badli miner/loader on the basis of applications submitted by female delisted casual wagon loaders who also claimed to have put in 75 days attendance during the year 1973 to 1976. The concerned workmen were declared as dependants of such female delisted casual wagon loaders.

3. It has been stated through the W.S. of the union that those applications were thoroughly scrutinised and examined by the management of BCCCL at various level and their identifications were established they were also medically examined and found fit for employment as miner/loader. It was submitted that the concerned workmen were employed as badli miner/loader which amounts to unfair labour practice under item No. x of the 5th schedule of the Industrial Disputes Act which reads as follows :—

"10. To employ workmen as "Badlis", casuals or temporaries and to continue them as such for years, with the object of depriving them of the status and privileges of permanent workmen."

4. It was contended that since after their appointment on 4-12-80 as badli miners/they have already completed 240 days attendance during the year 1981 and 1982 but they were not regularised and denied benefits admissible to the regular workmen.

5. The union stated further that initially all the concerned workmen were employed in Gondudih Colliery but 9 of the named below were transferred to Pootki Balihari colliery vide office order dt. 24-11-81 issued by the Deputy Personnel Manager (M.P.), BCCI, Karmik Bhawan, Saraidhalla, Dhanbad.

S No Name of the worker

1. Sri Lakhan Mahato.
2. Sri Jogesar Bhuian.
3. Sri Kedar Mistry.
4. Sri Bhakwan Sao.
5. Sri Ramendra Thakur.
6. Sri Babulal Yadav.
7. Sri Subhash Mistry.
8. Sri Darogi Mahato.
9. Sri Ramswarup Rajiv.

6. The aforesaid 9 workmen were again transferred from Pootki Balihari Project to Kusunda vide office order dt. 29-1-93 by Dy. C.M.U./Project Officer, Pootki Balihari project. They after their release on 5-2-83 reported for duty to the

Personnel Manager, Kusunda Area but they were again directed to report for duty at Gondudih Colliery. Naturally the concerned workmen reported for duty on the same day i.e. on 5-2-93 itself to the Manager, Gondudih colliery. They were directed to come on the following day and so the concerned workmen again reported for duty on 6-2-83 but the Manager refused to provide them any work and told that they have been permanently stopped from their work. The union stated in the W.S. that no reasons was assigned before stopping the work nor any chargesheet was issued against them. It was submitted that stoppage of the said concerned workmen by the management was illegal and they should be declared to be continuing in the employment of M/s. BCCI with all consequential benefits.

7. The union further added that 13 concerned workmen out of remaining 17 were discontinued from their work by the Agent, Gondudih colliery on 8-1-83 without assigning any reason. That remaining 4 concerned workmen were discontinued vide office order dt. 10-1-83 issued by the Dy. Chief Mining Engineer, Dhanbar of Kusunda Area. Since the stoppage was illegal, the union claimed that all the concerned workmen should be held to be continuing in the employment of BCCI. The union represented the case of the concerned workmen before the management several but without any effect. The conciliation proceeding also failed giving rise to the present reference.

8. The management filed separate W.S. and stated during the year 1973 to 1976 the supply of wagons on the railway siding was very erratic so much so that on some days wagons used to be supplied and on some days more than normal number of wagons were supplied for loading purpose. In order to meet the situation a casual pool was maintained. Apart from permanent loaders some casual loaders were engaged. In spite of all these things sometimes it was very impracticable to accomplish the work of loading due to excess supply of Wagons and in such a situation anyone available was used to be engaged on wagon loading job and they were treated as unutilised/delisted casual wagon loaders. Such delisted casual wagon loaders were engaged when permanent and casual wagon loaders were not found sufficient to do wagon loading job on a particular day.

9. The management stated that in the year 1976 mechanised system of loading was introduced and delisted casual wagon loaders become surplus. However, in the year 1980 the management took a policy decision to give preference to the delisted casual wagon loaders in their employment as badli miner/loaders and a formula was devised whereunder a delisted casual wagon loader who have completed 75 days attendance during 1973 to 1976 will be given job of badli miner/loaders according to the requirement. In this way several delisted casual wagon loaders were enrolled as badli miner/loader. As the female could not have been engaged under the mine. It was decided that their male dependants will be given job of badli miner/loaders. In this way the concerned workmen were enrolled as badli miner/loaders on the basis of the applications submitted by some female workers asserting that they were genuine delisted casual wagon loaders and have put in more than 75 days attendance during the year 1973 to 1976. The concerned workmen were thus declared dependants of such female casual wagon loaders. The management however, stated that the concerned workmen could not prove their genuinity for year together and they themselves stopped coming because they were not being provided with any job for a number of days.

10. While giving parawise reply it was contended by the management that the engagement of the concerned workmen as badli miner/loader was provisional subject to proper verification of the documents to be produced by them. They could not submit proper identification certificate for their enrolment as badli miner/loader. It was also submitted that engagement of badli miners becomes necessary only in case of absenteeism on mass scale specially during Pooja, festival time and cultivation period. Thus they are provided job during leave and sick vacancies only. It was denied that the concerned workmen completed 340 days attendance during 1980 and 1981 and they were not regularised on account of any unfair labour practice.

11. In the circumstances of the case the point for consideration is as to whether the concerned workmen are entitled for reinstatement with full back wages or not.

12. Admittedly, 26 concerned workmen were employed as badli miner loaders as the dependants of delisted female casual wagon loaders vide office order dt. 4-12-80 issued by the General Manager, Kusunda Area. The management had to say that their engagement as badli miner/loaders were provisional subject to proper verification of the identification certificate to be produced by them. The management stated that the concerned workmen did not file any identification certificate. MW-1 Shri A. K. Prasad Sr. P. O. BCL has stated in his evidence that a letter was received in the office from the higher authorities that the concerned workmen were not genuine persons and after that they were stopped from their work. In this connection first of all reference may be made to letter dt. 4-12-80 (Ext. W-3) whereby they were appointed as badli miner/loader. They were directed to report for duty by 10-12-80. The letter does not whisper even a word like provisional or temporary. On the other hand the spirit of the letter shows that all sorts of verification had been done by the authorities and so much as the photographs of the concerned workmen duly attested by B.D.O's and Mukhiya had been sent to the respective collieries for official record. Para-7 of the W. S. also recites that the concerned workmen were declared as dependants of such female delisted casual wagon loaders. The word 'declared' is very significant in itself. The question of declaration does not arise without proper verification. W.W.-1 and W.W.-2 have stated that all sorts of verification has already been done by the management before they were appointed as badli miner. They also stated that the enquiry from the B.D.O. and Mukhiya and from the Police had already been made.

13. The letter dt. 25-12-82 appears to be most important document whereby the concerned workmen were stopped from their work. It was issued by Shri K. C. Nandkeyolyar, Dy. Chief Personnel Manager to the General Manager Kusunda Area. It will be important to note that this letter was issued after complete two years of the appointment. The operative portion of the letter reads as follows :—

"In view of the facts that objection has been received from different workmen on the photographs displayed in the colliery, it has been decided that the following badli miner/loaders, who have been employed as dependants of the delisted casual wagon loaders of Industry colliery should be immediately discontinued. They should also be asked to prove their bonafide as well as of those women in whose places they have been offered employment."

14. From the letter it is crystal clear that some complaints had been received from different women on display of the photographs in the colliery. Those complaint petitions have been marked Ext. M-2 to M-2/15 and all were received in October, 1982 i.e. after about 2 years of the appointment of the concerned workmen. The question is that the photographs of the concerned workmen were expected to have been displayed before or immediately after their appointment as badli miner. Normally the objections are invited before any appointment. The main objection would have been as to whether the concerned workmen were the real dependants of delisted casual wagon loaders or not. If the objections were invited immediately after appointment than these complaint petitions would have been filed shortly thereafter. But there can be hardly any sense in filling those complaint after about 2 years. This will give rise to an inference that these complaints were mere futile exercise as if changing after wind in the wilderness. Now let us have a look on these complaint petitions. They are all carbon copies seemed to have been written in one sitting and in one pen. The language of the complaint petition is also one and the same. Only the I.T.I of the Kamins have been obtained on each complaint. No doubt the complaints disclosed that in the month of January, 1981 some information had been given by the delisted female casual wagon loaders but we have no paper to substantiate this fact. As the record reveals one Darogi Mahato is said to be the dependant of Kunti Kamin. She has been examined as MW-3. She stated that Darogi Mahato was not her dependant. She herself claims to be Bhuini by caste. She was stopped from the work in 1976. Her husband was also working in the Industry colliery from before her appointment. The question is that she was stopped in 1976 and she should have represented before the management as to why she was stopped if she had no dependant. I think she was not alone. Her husband was also alive and working in the same colliery.

Normally she should have anxiety to know as to why her bread was snatched away by the management. It is very important to note that snatching of livelihood was not an ordinary incident which could have been ignored or laughed away without any consequence but the silence on the part of the lady smacks something very unnatural and very indifferent. A certificate of the Mukhiya of the Gram panchayat has been filed on behalf of the concerned workman certifying that he was the son-in-law of Kunti Kamin. There can be no rule of the society that a Mahato cannot be the son-in-law of Kamin. No other complainant has been examined to show that the concerned workmen are not their dependants. I think mere filing of the complaint cannot be called sufficient. Rarogi Mahato has filed an affidavit duly sworn in by him that Kunti Kamin was his mother-in-law. Few other concerned workman have also filed affidavits stating the names of Kamins their relationship with them. MW-2 Raj Kumar Bhuia has come to say that Bedamin Kamin, Gurji Kamin, Chhota Sumri Kamin had never applied for engagement of their any dependant. The witness stated that they were stopped in the year 1976. Again the same question will arise as to why they kept scum after their stoppage and why they did not ask the management reasons for their illegal stoppage.

15. The evidence of A. K. Singh, MW-4 will be of much important. He has been working as Senior Personnel Officer in Kusunda Area. He stated that 15 complaints were received by Shri Divakar Mukherjee and one by Shri B. M. Chouhan. M-2 to M-2/15. The witness stated that on the basis of those complaints petitions an enquiry was held by the management and after due enquiry the concerned workmen were stopped. I find no enquiry report has been filed nor the officer who conducted the enquiry has been examined. The question is as to how that enquiry was conducted. Whether the concerned workmen were given any opportunity to explain or it was an ex parte affair? We have nothing before us to know the mode and manner of enquiry conducted by the management. The persons or the authority who received the complaint have also not been examined.

16. It was the case of the management that the concerned workmen were enrolled as badli miner/loader and provided job as and when required during leave and sick vacancies of permanent miner/loaders. In this way the management wanted to say that the concerned workmen had no regular and continuous work. The learned counsel for the workmen urged that though they were deployed as badli miner/loader but they worked continuously. He submitted in his continued argument that as a matter of fact the system of badli miner/loader by the management of BCCI amounts to unfair labour practice.

17. It was contended that these concerned workmen even though working as badli miner/loader have completed more than 240 days attendance during the year 1981, 1982. In order to prove this fact the union has filed and got proved few pay slips issued by the management and it has been marked Ext. W-2 series. This will show that the concerned workmen had been allotted their C.M.P.F. No. as well. For example Deorgi Mahato had C.M.P.F. No. D/42/371(W.2/11) Subhas Mistry was allotted C.M.P.F. No. D/42/356 (Ext. W-2/18). The pay slips will also disclose the number of days employed by the particular workman in particular month. We can take up the example of Subhash Mistry one of the concerned workman. He has been described as underground miner/loader as noted on the right hand side of Ext. W-2/13. On the right hand side below of each pay slip the month and year has been noted. The attendance of Subhash Mistry as miner right from April 1982 to December, 1982 barring September, 1982 will be as follows :—The pay slip for September, 1982 is not available with the record.

Name and designation	Month/Year	days employed
Subhas Mistry	April '82	26 days
	May '82	32 days
	June '82	30 days
	July '82	28 days
	August '82	24 days
	Oct '82	25 days
	Nov. '82	24 days
	Dec. '82	27 days
		216 days

18. Similarly Ram Swarnp Rajiv one of the concerned workmen having C.M.P.F. No. D/42/364 worked for 232 days as underground miner in the year 1982. The break up is as follows :—

Name and designation	Month/Year	days employed
Ram Swarnp Rajiv	April' 82	26
	May' 82	26
	June' 82	22
	July' 82	27
	Aug' 82	26
	Sept.' 82	27
	Oct.' 82	25
	Nov.' 82	26
	Dec.' 82	27
		232

The concerned workmen were also provided with Bonus card, Ext. W-1 series. This means that they were also paid yearly bonus. Atleast the pay slips showing the days of work done by the concerned workman disproves the contention of the management that they were given job as and when required during leave and sick vacancies, of permanent miner/loader. As again that Ext. W-2 series clearly demonstrate that these concerned workmen have been working continuously like permanent miner in the whole of the year. The complete papers of the pay slips must show that they have been working regularly and have completed 190 days attendance as miner/loader in a calendar year. According to the para-25 of the W. S. of the management if a workman is provided job for 190 days attendance in a year in underground mine or 240 days attendance on surface, he cannot be regularised as permanent miner/loader. In the instant case the management knowingly or unknowingly acted contrary to the statutory provisions and the concerned workmen were not regularised although they worked there required days as underground miners. Since they were in continuous service the provision of Section 25 of the I. D. Act will necessarily come into play. Admittedly there has been no compliance of the provision of Section 25F of the I.D. Act.

19. Ext. W-4 is the office order dt. 24-11-81 whereby the nine concerned workmen out of 20 were transferred from Gondudih colliery to Putki Balihari Project. Normally a badli miner is not required to be transferred from one colliery to another colliery. This further proves that they were working as fulfilled underground miner/loaders. Ext. W-6 and W-7 are the office order dt. 8-1-83 and 10-1-83 whereby 17 concerned workmen were stopped from their work.

20. The union has examined some witnesses and they have proved the claims of the concerned workmen. WW-1 has stated that he himself and other concerned workmen were real dependants of delisted female casual wagon loaders. He also claims to have been working continuously since after his appointment in the year 1980. Other concerned workmen have also working continuously. The witness further stated that they were all appointed after due enquiry by the management. This fact finds support from the evidence of WW-2 also who is the Secretary of Koyala Ispat Mazdoor Panchayat. He had stated that all the concerned workmen are the members of the C.M.P.F. WW-3 is the Secretary of the Coalfields Labour Union. He had himself approached the Mukhiya and B.D.O. for the grant of the certificates in favour of the concerned workmen. He also stated that the concerned workmen are the genuine persons. WW-4 Jamuna Yadav is also one of the concerned workmen. He claims to have been appointed as dependant of his wife Sohla Kamin. He stated to have worked continuously but he was stopped without any notice or chargesheet. WW-5 is Shri Rajendra Thakur who is the dependant of his mother Basanti Kamin. He has stated his claims.

21. I have examined various aspect of the matter. Even supposing for the sake of argument that the concerned workmen are not genuine dependants of delisted female casual wagon loaders still I find that they since their appointment as badli miner/loaders have discharged continuous service in a year and are entitled to be regularised as underground miner/loaders. For the reasons already explained I am to hold that the stoppage of the concerned workmen by the

management was not justified. The management is thus directed to reinstate all the concerned workmen as Miner/loaders with payment of fifty percent of back wages from the date of stoppage to the date of reinstatement with all consequential benefits within 2 months from the date of publication of the Award.

This is my Award.

B. RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

का.आ. 1065 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै. भारत कोकिंग कोल लि. की कनकनी कोलियरी के प्रबन्धतंत्र के संयुक्त नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 2), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/101/86-डी-3(ए)/आई आर (कोल-I)
एच.सी. गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1065.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. II) Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kankanee Colliery of B.C.C.L. and their workman, which was received by the Central Government on 3-5-1993.

[No. L-20012/101/86-D.III (A)/IR (C-I)]

HARISH GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Ram, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

Reference No. 258 of 1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kankanee Colliery of Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workman—Shri B. Bose, Secretary, R.C.M.S. Union.

On behalf of the employers—Shri G. Prasad, Advocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 26th April, 1993

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/101/86-D.III (A), dated, the 24th July, 1986.

SCHEDULE

"Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor

Sangh that the management of Kankanee Colliery of Bharat Coking Coal Limited should give their workmen, S/Shri Ashok Kumar Roy and Swapan Kumar Banerjee the designation of store clerk and office clerk, respectively, and clerical grade-II scale of pay from 1-1-81 is justified? If so, to what relief are these workmen entitled?"

2. In this case both the parties appeared and filed their respective W.S. documents. Subsequently at the stage of oral evidence, both the parties appeared before me and filed a petition of compromise under their signature. I heard both the parties on the said petition of compromise and do find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both of them. Accordingly, I accept the said petition of compromise and pass an Award in terms thereof which forms part of the Award as Annexure.

B. RAM, Presiding Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II,
DANBAD

Reference case No. 258 of 1986

Employers in relation to the management of Kankanee
Colliery of Sijua Area of M/s. B.C.C.L.

AND

Their Workmen.

The humble petition of compromise on behalf of the parties most respectfully sheweth :—

1. That, the Central Government by a notification has referred the instant industrial dispute for an adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947) to this Hon'ble Tribunal. The schedule of the reference is reproduced below :—

SCHEDULE

"Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh That the management of Kankanee Colliery of Bharat Coking Coal Limited, should give their workmen S/Shri Ashok Kumar Roy and Swapan Kumar Banerjee the designation of Store Clerk and Office clerk, respectively and clerical Grade-II scale of pay from 1-1-81 is justified? If so, to what relief are these workmen entitled?"

2. That, the parties discussed the dispute outside the Court and have settled the said dispute on the following terms and condition.

Terms of settlement

1. That Shri Ashok Kumar Roy and Shri Swapan Kumar Banerjee will be placed in clerical grade-II w.e.f. 1-1-1989.
2. That, they are notionally placed in clerical Grade-II w.e.f. 1-1-1989 and they will not be entitled for any arrear wages etc. However pay fixation benefit will be given from 1-1-1989.
3. That, it was agreed that both the parties will approach, the Hon'ble C.G.I.T. No. II to record the aforesaid compromise and pass an award in terms of settlement.
4. That, this settlement resolves all the dispute fully and finally between the parties and the workmen concerned S/Shri Ashok Kumar Roy and Swapan Kumar Banerjee shall have no claim whatsoever.

It is, therefore, prayed that your Honour may graciously be pleased to accept the above compromise and pass an award in terms of settlement.

Representing Union :

- (1) (G. D. Pandey)
Joint General Secretary R.C.M.S.
- (2) (Ashok Kumar Roy)
Workmen.

- (3) (Swapan Kumar Banerjee)
Workmen.

Representing Management :

- (1) General Manager, Sijua Area
- (2) Dy. C.P.M. Sijua Area
- (3) P.M. (IR), Sijua Area

Witness :

- (1)
- (2)

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1993

का.ग्रा 1066 :—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तारीख 16 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या का.ग्रा. 172 द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण संख्या 1, बम्बई के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक पद रिक्त हुआ है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री आर.जी. सिंघाकर को 19 अप्रैल, 1993 से उक्त अधिकरण में पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा.सं. ए-11016/1/91-सी.एल.एस-II]

गोपाल सिंह, अवसर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1993

S.O. 1066.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal No. 1 Bombay, constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Employment Notification No. S.O. 172 dated the 16th January, 1960.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri R. G. Sindhakar as the Presiding Officer of the said Tribunal with effect from 19th April, 1993.

[F. No. A-11016/1/91-CLS. II]

GOPAL SINGH, Under Secy

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1993

का.ग्रा 1067 :—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तारीख 22 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या का.ग्रा. 1698 द्वारा गठित श्रम न्यायालय संख्या 1, बम्बई के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक पद रिक्त हुआ है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री आर.जी. सिंघाकर को 19 अप्रैल, 1993 से उक्त श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा.सं. ए-11016/1/91-सी.एल.एस-II]

गोपाल सिंह, अवसर सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1993

S.O. 1067.—Whereas a vacancy has occurred in the Office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal No. 1 Bombay, constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour and Employment Notification No. S.O. 1698 dated the 22nd May, 1965 ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri R. G. Sindhakar as the Presiding Officer of the said Labour Court with effect from 19th April, 1993.

[F. No. A-11016/1/91-CLS. II]

GOPAL SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 मई, 1993

का.आ.1068:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धसूत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, व श्रम न्यायालय, चण्डीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-12012/369/87-डी-II (ए)]

एस.के. जैन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd May, 1993

S.O. 1068—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 3-5-1993.

[No. L-12012/369/87-D.II (A)]

S. K. JAIN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I. D. 8/88

V. K. Chawla

Vs.

State Bank of India.

For the workman—Shri C. L. Bhardwaj.

For the management—Shri Ajay Kohli.

AWARD

Central Government vide Gazette Notification No. L-12012/369/87-D.II (A) dated 10th February, 1988 issued U/S 10 (1)(d) of the I. D. Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the State Bank of India, Haryana Region, Chandigarh in terminating the services of Shri V. K. Chawla, clerk-cum-cashier at Nilokheri branch w.e.f. 20-7-1986 is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

2. It has alleged in the statement of claim that the petitioner was appointed w.e.f. 14-5-1973 against an independent permanent sanctioned vacancy. His services were terminated w.e.f. 20-7-1974. Industrial Disputes No. 68 of 1979 was raised which was decided on 18-1-1984 declaring the termination as void ab initio and ordered to be reinstated in

service with full back wages and continuity of service. However it was also observed that it shall open to the State Bank of India to terminate his service by complying with Section 25-F of the I. D. Act 1947. It is further alleged that the said award was not implemented and the respdt. management had gone to the High Court against the said order. Upon dismissal of the said writ petition, the petitioner was advised through letter to report for duty at branch office Nilokheri for which he reported on 5-5-1986. It was further alleged that instead of reinstating him the petitioner was advised that he had been appointed as a temporary clerk-cum-cashier subject to deposit of Rs. 1,000 as cash security. It is further alleged that the petitioner was again appointed as temporary clerk for a period of one month from 14-6-1986 with the condition that appointment will automatically come to an end on the expiry of the said period on 13-7-1986 and this appointment was against the directive of the Hon'ble Tribunal in the said award and the management has been harassing the petitioner. It is further alleged that the services of the petitioner again terminated w.e.f. 19-7-1986 for not having passed the requisite test for the permanent absorption in the bank after giving an amount of Rs. 2690.10 on account of one month pay in lieu of notice and Rs. 7218 on account of retrenchment compensation in terms of Section 25-F of the I. D. Act 1947 for the period 14-5-1973 till the date of termination i.e. 19-7-1986. It is further alleged that the said termination is utter violation of provisions of I. D. Act 1947 read with the provisions of the modified bank awards up to date without assigning any cogent reasons and in violation of provisions of Sastri Award/Desai Award and Bipartite Settlement. It is further alleged that during the pendency of earlier dispute the respdt. management had imposed a condition upon the petitioner to forgo back wages if he had passed the test which was to be held on 3-10-1982 for permanent absorption in the bank but the said condition was not acceptable to the petitioner and he declined to appear in the written test and now the management cannot take the stand that the petitioner is not fit for the post as he had not qualified the test. It is also alleged that this action of the management was prejudiced with him. It is further alleged that during the conciliation proceedings Asstt. Labour Commissioner Rohtak directed the management to produce the names of temporary employees who were working after 14-5-1973 and were called for written test held on 3-10-1982 together with the names of those who had qualified the written test of 3-10-1982 but the management did not produce the same. It is further prayed that the termination of the petitioner is violation of Industrial Disputes Act, 1947 and prayed for reinstatement with back wages.

3. Respdt. management filed written statement. The plea has been taken that in pursuance of the earlier award the petitioner was reinstated with full back wages and continuity of service. It was open to the Respdt. bank to terminate the services of the petitioner after complying the provisions of Section 25-F of the I.D. Act 1947. The termination of the petitioner was effected after complying with the provisions of Section 25-F of the I. D. Act and thus there is no illegality. It is further pleaded that the said award was challenged in Delhi High Court by way of writ petition and it was dismissed. The petitioner was advised on 29-4-1986 to report for duty at Nilokheri Branch on 5th of May 1986. He was further asked to deposit cash security of Rs. 1,000 and there is no illegality in it and perfectly in accordance with law. It is further pleaded that intimation letter dated 29-4-1986 and 14-6-1986 in which there was stipulation that the appointment of the petitioner would automatically come to an end, but this condition was withdrawn and as such para two of letter dated 14-6-1986 was deemed to be withdrawn. It is further pleaded that termination date 19-7-1986 is in accordance with the provisions of Section 25-F of the I. D. Act 1947, pay in lieu of notice amounting to Rs. 2690.10 and retrenchment compensation for the entire period from 14-9-73 till termination amounting to Rs. 7218.72 P. was paid to him. It is further pleaded that the petitioner was asked to appear in the test which was scheduled to be held in October 1982 however he did not appear in the test. It is further pleaded that there is no merit in the allegation of the petitioner that the stigma has been imposed upon him while terminating his services on 19-7-1986. It is further pleaded that in the earlier award also observation has been made that the petitioner also alleged though wrongly that he passed in the test. The workman did not challenge this part of the award before any authority. It is further pleaded that citation cited by the petitioner has no relevance to the facts of this case and prayed for the dismissal of the present reference.

4. Replication was also filed reasserting the facts made in the claim statement.

5. In support of his case the petitioner examined himself as WW-1 and filed his affidavit Ex. W-1 in evidence and also relied on the documents Ex. W-2 the award, Ex. W-3 order of Hon'ble High Court Ex. W-4 order of reinstatement dated 29-4-1986, Ex. W-5 is the calculation filed by the petitioner for the entitlement of the back wages up to reinstatement, Ex. W-6 letter dated 13-6-1986 asking the petitioner to deposit Rs. 1,000 as security, Ex. W-7 is the appointment letter of the petitioner for one month. Ex. W-7A is the correspondence asking the petitioner to submit application, Ex. W-8 letter written by the petitioner, Ex. W-9 letter dated 25-6-1986 conveying to the petitioner calculation, Ex. W-10 letter written by the petitioner, Ex. W-11 letter dated 25-6-1986 by the management asking the petitioner not to deposit Rs. 1,000 as security, Ex. W-12 letter written by the management, Ex. W-13 letter written by the workman, Ex. W-14 letter written by the management conveying the petitioner with regard to the deletion of para two in the letter dated 14-6-1986, Ex. W-15 is the termination dated 19-7-1986, Ex. W-16 the correspondence, Ex. W-17 letter written by the petitioner Ex. W-18 is again correspondence, Ex. W-19 is the letter written by the petitioner Ex. W-20 is letter written by the petitioner Ex. W-21 letter written by the management Ex. W-22 letter written by the management asking the petitioner to appear in the test Ex. W-23 letter written by the management Ex. W-24 letter written by the petitioner, Ex. W-25 telegram sent by the management, Ex. W-26 telegram sent on behalf of the petitioner, Ex. W-27 letter written by the petitioner, Ex. W-28 demand notice before the A.L.C., Ex. W-29 reply filed by the management before the A.L.C., Ex. W-30 replication before the A.L.C., Ex. W-31 letter written by the authorised representative of the petitioner to A.L.C., Ex. W-32 letter by the management to A.L.C., Ex. W-33 observation of A.L.C. and W-34 the failure report.

The management produced Mr. G. D. Goel MW-1 who filed his affidavit Ex. M-1 in evidence and produced himself as MW-1 and also relied on document Ex. M-2 the termination letter duly annexed calculation of retrenchment compensation from 14-5-1973 to 13-5-1986.

6. I have heard both the parties. Both the parties have filed written arguments which I have gone through and perused the record and evidence.

7. Representative appearing on behalf of the workmen has argued that by virtue of the earlier award which is Ex. W-2 the petitioner was given reinstatement but respdt. management vide Ex. W-7 appointment made as fresh hand for one month only and after the expiry of the said period his services was again terminated which is illegal and against law. Thus his subsequent termination is void abinitio and he is to be reinstatement with full back wages. There is no merit in this argument. No doubt that in para two of Ex. W-7 there is mention that the petitioner is appointed as temporary clerk for one month and his appointment will automatically come to an end on the expiry there of i.e. 13-7-1986 and at the same time in Ex. W-6 dated 13-6-1986 the petitioner was required to deposit cash security of Rs. 1,000 but at the same time condition contained in para two of Ex. W-7 was treated to be cancelled in the subsequent communication dated 10-7-1987 which is Ex. W-14 and the demand of Rs. 1,000 as security deposit was also withdrawn vide letter dated 25th June 1986 which is Ex. W-11. Thus the position stands that on account of withdrawal of the condition and the security deposit, there was clan reinstatement of the petitioner and he was paid all the arrears of the back wages right from the date of his retrenchment i.e. 1974 till his reinstatement i.e. 4-5-86. Otherwise consequence of his subsequent termination had the management considered his appointment for the period of one month the management was not required to pay the petitioner the retrenchment compensation right from the period 14-5-1973 till his date of termination i.e. 1986 by virtue of the amendment in Section 2(o) and the introduction of clause bb), termination of the services for the non renewal of contract has been specifically excluded from the definition of 'retrenchment' in that situation provision of Section 25-F would not have applied. But the management had paid entire retrenchment compensation right from 14-5-1973 to 19-7-1986 indicating that the petitioner was given a clear reinstatement in pursuance of the earlier award Ex. W-2.

Next contention raised by the rep. of the petitioner is that subsequent termination of the petitioner has been effected

for not having passed the requisite test prescribed for permanent absorption and have not been found suitable and in this connection he has argued that prior to his earlier termination he had passed the test and subsequently he was not allowed to sit in the test which was scheduled to be held on 3-10-1982 as the management had put the condition that he will be allowed only if he will forgo his back wages and thus the management is reasonable for not allowing the petitioner to qualify the said test and termination on this score is bad in the eyes of law. This contention can not be accepted for many reasons. Firstly earlier award had been passed on 18-1-1984. The contention of the petitioner with regard to the fact that he was not allowed to appear in the test which was held on 3-10-1982 and that test stood prior to the earlier award and the same should have been agitated in the earlier proceedings and the same could be adjudicated upon in the earlier award which was passed much later to the date of the test. But the same has not been done. Secondly the petitioner might have alleged in the earlier proceedings that he had passed the test because upon the perusal of the award there is an averment with regard to the test and that is why it gave an occasion to the Court to observe in the second para of the said award :

"that the petitioner had alleged though wrongly that he had passed the test"

Thirdly however the test which was held on 3-10-1982, the respdt. management themselves had offered the petitioner on 3-9-1982 vide Ex. W-22 to appear in the test which was scheduled to be held on 3rd October 1982 and the venue was also indicated and in this connection the management had not laid any condition that the petitioner shall be allowed to appear in the test only if he forgo the back wages. No doubt in subsequent communication vide Ex. W-23 the petitioner was asked to give an undertaking in connection with the forgoing of the back wages but at the same time it was not the condition precedent for appearing in the test. The petitioner could appear in the said test even without agreeing to the condition laid down by the respdt. management. But on the contrary he remained absent on the date of the test as apparent from the telegram sent by his father to the respdt. management which is Ex. W-26 indicating that the petitioner is out of station. Thus conclusion can easily be drawn that the petitioner himself knowingly did not appear in the said test and can not claim any contravention at this stage at the hands of the respdt. management.

Thus for the sake of repetition the petitioner was duly reinstated and was paid all the wages in pursuance of the earlier award. Subsequent termination w.e.f. 19-7-1986 has been effected after duly complying the provisions laid down U/S 25-F of the I.D. Act 1947 the management had said retrenchment compensation from 14-5-1973 till date the petitioner was retrenched.

Next contention has been raised by the representative of the petitioner that the retrenchment compensation offered to the petitioner at the time of subsequent termination falls short the amount to which the petitioner was entitled and thus there is contravention of clause 'B' of Section 25-F of the I.D. Act and on this score alone the petitioner is entitled for reinstatement. There is no force in this contention. The legislature had in mind to make this clause obligatory and making it as a condition precedent so to partially redress the hardship caused to the workmen upon his retrenchment. In other way it implies that the offer should be genuine which is sufficient. There may be difference of calculation and only on account of certain miscalculation the offer does not become non-genuine. As apparent from Ex. M-2 termination letter and the calculation of retrenchment compensation annexed out-come was offered for payment at the time of retrenchment. If there is some variation in calculation it is open to the petitioner to claim the same from the management. But when offer is genuine and there are miscalculations in retrenchment compensation that certainly does not warrant reinstatement.

In view of the discussion made in the earlier paras. there is no merit in this reference and same is dismissed. However, it is open to the petitioner to claim difference of retrenchment compensation, if there is any, from the management otherwise through the intervention of the Court U/S 33-C (2) of the I.D. Act 1947.

Chandigarh,

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 मई, 1993

का.आ. 1069 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ इन्दौर, के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोक्ताओं और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, व श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/165/89-आई आर (बी-3)]

एम.के. जैन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th May, 1993

S.O. 1069.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Indore and their workmen, which was received by the Central Government on the 3-5-93.

[No L-12012/165/89-IR (B-3)]
S. K. JAIN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
CUM LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 25 of 1989

In the matter of dispute between :—

Sri Suresh Shukla, C/o Sri V. N. Sekhari, 26/104 Birhana Road, Kanpur.

AND

Manager, State Bank of Indore, Hospital Road Agra.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification no. L-12012/165/89-I.R. (B-3) dated 6-10-89 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

“Whether the management of State Bank of Indore, Agra, was justified in terminating the services of Sri Suresh Kumar Shukla w.e.f. 2-3-83, in violation of sec. 25G & H of the I. D. Act, 1947 ? If not to what relief the workman entitled to ?”

2. On 16-3-93, the case was fixed for the cross examination of the workman. Sri V. Singh, appeared for the workman with an application that despite writing of letter by him to the workman, the workman did not turn up and as such notice be issued to the workman. The said application was rejected vide order passed on the application on 16-3-93, on the ground that previously the workman was represented by Sri D. D. Mehta, and since 25-9-93 time is being given for the cross-examination of the workman.

3. Since the workman is absent, it appears that he is not interested in the case any more. As such a no claim award is given against him.

4. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV Presiding Officer

Dated : 16-5-93

नई दिल्ली, 4 मई, 1993

का.आ. 1070 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय

सरकार साऊथ इण्डियन बैंक लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोक्ताओं और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय, एरनाकुलम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/105/91-आई आर (बी-III)]

एम.के. जैन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th May, 1993

S.O. 1070.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Labour Court, Ernakulam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of South Indian Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd May, 1993.

[No. L-12012/105/91-IR (B.III)]

S. K. JAIN, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR COURT,
ERNAKULAM

(Labour Court, Ernakulam)

(Friday, the 16th day of April, 1993)

PRESENT :

Shri M. V. Viswanathan, B.Sc, LL.B., Presiding Officer.

Industrial Dispute No. 2 of 1991 (C)

BETWEEN

The Chairman, The South Indian Bank Ltd., Central Office, Trichur, Kerala-680001.

AND

The President, South Indian Bank Employees Association, Central Office, Post Office Road, P.B. No. 131, Trichur, Kerala-680001.

(2) The General Secretary, South Indian Bank Employees Congress (INTUC), Central Office, INTUC Bhavan, Kuruppam Road, Trichur-680001.

REPRESENTATIONS :

Sri. B. S. Krishnan, Advocate, Ernakulam—For Management.

Sri. P. Balakrishnan, Advocate, Trichur-3—For Union No. 2.

AWARD

This industrial dispute was referred to this Court by the Central Government as per the Order No. L-12012/105/91-IR. D.III dated 9th May, 1991. The dispute is between the management of South Indian Bank Limited and their workmen. The issue referred for consideration is “Whether the action of the management of South Indian Bank Limited, Trichur is justified in not regularising the services of the 98 workmen viz. Shri P. A. Francis and 97 others from the date of their initial entry into the services ? If not, to what relief the concerned workmen are entitled to ?”

2. The workmen involved in this dispute are represented by the President, South Indian Bank Employees Association, Central Office, Trichur and the General Secretary, South Indian Bank Employees Congress (INTUC), Central Office, Trichur.

3. In pursuance to the notice of reference served on the Management and the Unions, both the Unions and the Management entered appearance. The Unions 1 & 2 filed separate claim statements. The management filed a counter statement.

The second union viz. the South Indian Bank Employees Congress filed a rejoinder to the counter statement filed by the management.

4. The first union viz. the South Indian Bank Employees Association filed a claim statement alleging mainly as follows:—

The South Indian Bank Limited and its workmen are covered and governed by the Industrial Disputes Act. The Bipartite settlements have provided that the so called temporary workmen who have worked for more than three months in regular and permanent vacancies should be deemed to be permanent workmen. The subsisting contracts and the conditions of service governing the management and the workmen also provide that when a temporary vacancy exists for three months, such vacancy shall be deemed to be a permanent vacancy. Under section 25(B) of the I.D. Act, provides that a workman who has put in 240 days of service within a period of 12 consecutive calendar months shall be deemed to have put in one year's continuous service. The 98 workers involved in this dispute became eligible to be treated as permanent and confirmed employees of the Bank. They have entitled regularisation of their services with retrospective effect from the date of their initial entry into their service together with all other attendant benefits. The management has denied the workmen their right to get wage scales and allowances. Many of these workmen have been in continuous employment from the year 1985 onwards. The management has adopted unfair labour practice in relation to the service conditions, rights and entitlements of the workmen. Hence, the first union prayed for the regularisation of the workmen from the date of their initial entry into services with full back wages and all other benefits.

5. The second Union has also put forward claim for the regularisation of the workmen from the date of their entry into services with back wages and other benefits.

6. The management filed the counter statement contending mainly as follows:

The management used to engage locally available persons in case of any emergency. They were paid remuneration depending on the days of work. Such engagement is purely intermittent and casual in nature. They are not entitled to regularisation as per the Industrial Law. The number of persons so engaged is only 97, but by mistake, in the reference their number is shown as 98. Out of 97, one person viz. D. John died after the reference of the dispute. The daily rated and casually engaged workers have no right for regularisation. However, the management adopted a compassionate approach to them and offered regular appointment. 95 of them have accepted the offer and entered the regular service of the bank from the date of their joining duty. They have given an undertaking in writing that they do not wish to further pursue the present dispute. The undertaking given by one worker is produced for ready reference to this court. The remaining one worker is not interested in joining the subordinate service as he is already working as Daily Deposit Canvassing Agent. Thus the subject matter of the dispute is resolved as above and the further adjudication is not required in the matter. The allegations in the claim statement of the Unions are not correct. The workers involved in this dispute will not get the protection under the Bipartite Settlement. They were engaged on casual basis because the vacancies are also casual in nature. The management has not adopted any unfair labour practice as alleged by the union. Hence, the management prayed for passing an award according to the contentions raised by them.

7. The South Indian Bank Employees Congress in their rejoinder refuted the contentions raised by the management in the counter statement. The union further contended that the offer made to the workers is not acceptable to the Union. The offer of appointment was only from July, 1992 onwards. The workers will lose more than 10 years benefits. The man-

agement had concocted certain documents using the blank signed papers forcefully obtained from the workers during their first appointment. Such documents are unenforceable and illegal. The subject matter of the dispute has not been resolved. The dispute is still pending. Hence, they reiterated their claim as put forward in their claim statement.

8. The issue referred for consideration is "Whether the action of the management of South Indian Bank Ltd., Trichur, is justified in not regularising the services of the 98 workmen viz. Shri P. A. Francis and 97 others from the date of their initial entry into the services? If not, to what relief the concerned workmen are entitled to?" According to the reference the number of workers involved in this dispute would come to 98. But the management in their counter statement categorically contended that actually there are only 97 workers involved in this dispute. This fact has not been disputed by the concerned workmen of the unions. On the other hand, the second union viz. South Indian Bank Employees Congress in their rejoinder admitted the fact that there are only 97 workmen involved in this dispute.

9. The management has submitted that out of 97, one person viz. D. John died after the reference of the dispute. This fact is not disputed by the Unions or the concerned workmen. The management further contended that out of the remaining 96 workmen, one person is not interested in joining the subordinate service of the management bank as he is already working as a Daily Deposit Canvassing Agent. This fact has also not been disputed by the other side. Thus the dispute is only in respect of 95 workmen. The definite case of the management is that the said 95 workmen have been given regularisation in service. The management in para 3 of the written statement has contended that the management offered the said 95 workers regular appointment and they accepted the same and entered the regular service of the Bank from the date of their joining duty. It is further stated that the said 95 workmen have given the undertaking to the effect that they do not wish to further pursue the present dispute. The management has also produced a copy of an application given by one of the workmen viz. R. Murala-dharan involved in this dispute. A perusal of this application submitted by the workman R. Murala-dharan would show that he is satisfied with the regular appointment given by the management and that he is not interested in pursuing the present dispute, I.D. 2/91. So this circumstance would give an indication that at present there is no subsisting industrial dispute between the management and the workmen involved in this reference case.

10. The first union viz. The South Indian Bank Employees Association has not filed any rejoinder to the counter statement filed by the management. This would give an inference that the 1st union has no dispute in the matter of the regularisation of the workmen involved in this case. It is further to be noted that there was no representation from the side of the first union from 22nd November, 1992 onwards. Only the second union viz. the South Indian Bank Employees Congress filed a rejoinder to the counter statement of the management. But in the said counter statement, the second union has also admitted the fact that the management has given regular appointment to the workmen involved in this dispute. But the case of the second union is that the management has concocted some documents by using the blank signed papers forcefully obtained from the workers. But the second union has not adduced any evidence to support the said contentions of concoction of documents. The second union could not produce any of the workmen involved in this case to depose before this Court regarding the alleged fabrication or concoction of documents. On the other hand, the application submitted by one of the workmen produced from the side of the management would show that at present there is no subsisting industrial dispute between the concerned workmen and the management regarding their regularisation in service. Moreover, the dispute referred to this Court is only in respect of the regularisation of the workmen involved in this case. But, it is an admitted fact that the concerned workmen have been given regularisation in their service. The workmen involved in this case have no subsisting dispute in the matter of regularisation. The unions have not succeeded in establishing the fact that there is a subsisting dispute regarding regularisation of the workmen involved in this case. On the other hand, the facts and circumstance of this case would show that there is no subsisting industrial dispute between the management and the workmen involved herein. Hence, I have

no hesitation to hold that there is no subsisting industrial dispute available for adjudication by this Court.

11. In the result, an Award is passed holding that there is no subsisting industrial dispute for adjudication by this Court.

Ernakulam,
16-4-1993.

M. V. VISWANATHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

का.प्रा. 1071 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, तमिलनाडु, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्याएन-12012/804/87-डी-II (ए)]
एस. के. जन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1071.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Tamil Nadu, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 5-5-93.

[No. I-12012/804/87 D.II(A)]
S. K. JAIN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Friday, the 26th day of February, 1993

PRESENT :

THIRU M. GOPALASWAMY, B.Sc.(B.L.),
INDUSTRIAL TRIBUNAL

Industrial Dispute No. 22 of 1989

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of State Bank of India, Madras).

BETWEEN :

Smt. T. Elavarasi,
T. S. 958, North 3rd Street,
Pudukottai-622001.

AND

The Regional Manager,
State Bank of India, Madurai.
Reference :

Order No. L-12012/804/87-D.II(A) dated, 14-7-88, of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Monday, the 11th day of January, 1993 upon perusing the reference claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru N.G.R. Prasad for Tvl. Row and Reddy & S. Vaidyanathan, Advocates

appearing for the worker and of Tvl. T. S. Gopalan, P. Ibrahim Kalifulla & S. Ravindran Advocates appearing for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :

AWARD

1. This dispute between the workman and the management of State Bank of India, Madurai, arises out a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, by the Government of India in its order No. L-12012/804/87-D.II(A) dt. 14-7-88 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue :—

"Whether the action of the management of State Bank of India in discharging from service Smt. T. Elavarasi is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The petitioner states as follows :—

She was working as a clerk cum-cashier in Pudukottai Branch of the Respondent Bank. While so, she was served with a letter dt. 28-9-83 stating 3 charges against her. She received a charge sheet dt. 31-10-83 adding one more charge. The last charge sheet dt. 27-2-84 was issued to her containing 4 charges.

1. 1st charge is in respect of negotiation and purchase of a cheque for Rs. 1000 favouring Suppaya and crediting the said amount on 15-7-83 into the petitioner's S.B. A/c and later refunding the amount to the Bank on 26-7-83.

2. The 2nd and 3rd and 4th charges relate to crediting of the amount of Rs. 600 into the S.B. A/c. of Narayanan, by realising a crossed draft in her favour issued by Madurai Branch and retaining the amount by the petitioner till the next day and further causing substitution of a voucher in that connection and further overdrawing a sum of Rs. 500 from petitioner's A/c. through Teller.

3. At the domestic enquiry she was not assisted by Defence representative. She was not asked whether she would have any defence representative. Regarding the procedure of conducting the enquiry she was not given any information. Without putting her on notice about the actual punishment to be awarded to her, she was asked to admit the charges with an assurance given by the Branch Manager that she would be let-off with a minor punishment. As a helpless lady she meekly admitted the charges, hoping that the consequences would not be severe and trusting the words of the Branch Manager.

4. But contrary to the assurance given and the belief entertained by the petitioner she was given 2nd show cause notice dt. 24-1-85 intimating the proposal to dismiss her from service on the basis of the findings. She appeared at the personal hearing on 9-2-85 and explaining her position. She pleaded that she did not commit mis-appropriation. She received an order dt. 14-2-85 stating that she was dismissed from service. Petitioner's past good record of service was not considered by the Disciplinary Authority who imposed the punishment. She filed an appeal dt. 19-3-85 to the Chief Regional Manager, narrating the entire facts. The Appellate Authority also gave the personal hearing at which petitioner made written submissions on 19-3-85. The appellate authority without weighing the petitioners submissions modified the punishment into discharge without notice. Then this Industrial Dispute has been raised.

One Suppaya, known to the petitioner presented a bearer cheque for Rs. 1000 payable by South Indian Bank, Othapalam. The said Suppaya was indebted to her already in a sum of Rs. 1000 taken as hand loan. Hence he delivered the bearer cheque to the petitioner towards the loan of Rs. 1000. The said cheque was discounted by the petitioner

and it was purchased by the Pudukottai Branch with the sanction of the Banks Officer. Therefore 1000 Rs. was credited into the petitioners account. The cheque however, when sent for encashment was dishonoured by the Othapalam Branch of South Indian Bank. Discounting of the cheque and converting it into a draft and then crediting the amount into petitioners S.B. A/c. were all approved by the Officers of the Pudukottai Branch and hence there is no illegality about it. After the dishonouring of the cheque, petitioner immediately refunded the amount already credited into her account with penalty to the Bank. There was no complaint from Suppaya or anybody else. The same cheque in favour of Suppaya was later handed over by him to one Muthulugu, who again presented it to the Petitioner at the counter of the Bank and it was again sent for collection.

5. As regards the other charges, Narayanan presented an outstation crossed draft for Rs. 600 in his favour and wanted immediate encashment on 9-8-83. As he was a known customer having an S.B. A/c. in Pudukottai Branch, she approached the Bank's Officers on behalf of Narayanan and hence the Officer concerned cancelled the crossing of the draft. Immediately she (petitioner) encashed the draft and held the sum of Rs. 600 with her without remitting it into the S.B. A/c. of Narayanan for the purpose of handing over the same to Narayanan who was expected to come back in the evening of the same day. As he did not turn up, she remitted the amount into Mr. Narayanan's Account on 10-8-83 by using Narayanan's remittance voucher. Soon after such remittance Narayanan turned up on 10-8-83 and started to withdraw the money immediately. As the withdrawal would take sometime he wanted the petitioner to prepare another credit voucher in petitioner's name for putting the amount into her account by cancelling the earlier credit voucher signed by Narayanan. The bank did not allow the petitioner to make the credit remittance of Rs. 600 in petitioner's account. The petitioner at the same time has presented the withdrawal slip for Rs. 500 to be paid out of her S.B. A/c. The bank prevented the remittance of Rs. 600 only for the purpose of charging her with unauthorised O.D. of Rs. 500. The petitioner did not at all misappropriate Rs. 600 belonging to Narayanan. The delay is due to Narayanan's not turning upto receive the amount on 9-8-83. The said Narayanan has not made any complaint.

6. No financial loss has been caused to the Bank. Hence discharge from service is unjustified and unwarranted punishment. The charges did not really warrant the award of discharge or dismissal and so the Respondent should have followed Paragraph 19.12 (e) of the Sastry Award by informing her of the minor punishment and imposing the same on the strength of petitioner's admission if any. The Respondent should have followed this course without holding a domestic enquiry.

The punishment being an extreme one the respondent should have held a full-fledged domestic enquiry without relying upon the so-called admission made to the petitioner. The petitioner made the admission only on the assurance given by the Branch Manager. In the light of several decided cases, the Respondent ought not to have imposed the punishment of discharge or dismissal upon the petitioner. The Appellate authority is not justified in awarding the punishment of discharge without applying his mind to the relevant facts and also submission made by the petitioner. In any view of the whole matter, awarding discharge or dismissal is totally unjustifiable and the Tribunal can justly modify the punishment u/s. 11.A. of the I.D. Act. The Domestic enquiry held by the Management is not fair and proper. A suitable award may be passed.

7. The Respondent states in the counter as follows :— A crossed instrument should be credited only to the payee's A/c. or the A/c. of Holder in due course and payment of cash cannot be straightaway made to the payee. Crossing on a cheque or draft is opened or cancelled at the discretion of the Bank and cash is paid to the Payee direct, if the sums are small and the persons concerned are known to the Bank. This is done as an exception, relying on the introduction given by one of the staff of the Branch and the instrument itself after cancelling the crossing is purchased

by the Bank and by such purchase, payment could be made even before reclamation of the draft or cheque. This is part of customer's service done on the strength of assurance given by the member of the staff and at the discretion of the Officer, who permits opening the crossing and purchasing the instrument. Using O.D. facility by a member of the staff is not permitted in S.B. A/c. Availing O.D. facility is viewed seriously.

8. A crossed draft for Rs. 600 Issued by Madurai Branch of the State Bank of India to Narayanan, an account holder in Pudukottai Branch and a student of Pudukottai College was presented on 9-8-83 to the petitioner at the counter. It was presented along with a credit voucher for crediting the amount into his S.B. A/c. opened on 8-8-83. The petitioner represented to Narayanan that it could take 4 to 5 days before collecting the money from Madurai Branch and then drawing it from his S.B. Account at Pudukottai. She has persuaded the Banks officials to open the crossing on the draft for transferring the amount Rs. 600 covered by the draft to Narayanan's S.B. A/c. Immediately at the instance of the petitioner crossing was cancelled and payment of cash direct (without remitting into the A/c.) to Narayanan was authorised. The petitioner herself collected the cash of Rs. 600 (on behalf of Narayanan) on 9-8-83. Narayanan's father took exception to the failure in crediting the amount into Narayanan's Account after the crossing was opened on 9-8-83. To get over the difficulty, the petitioner had without sufficient balance in her own S.B. A/c. withdrew a sum of Rs. 500 added a further sum of Rs. 100 and then prepared a credit voucher in favour of Narayanan and remitted the sum of Rs. 600 into Narayanan's account on 10-8-83. Accordingly she made a credit entry for Rs. 600 in Narayanan's pass book of the S.B. A/c. and also in the ledger. Then on the same day, in order to set right her over drawing Rs. 500 from her account she prepared a credit voucher for Rs. 600 in her favour and wanted the Cashier Vidya for cancelling the credit voucher in favour of Narayanan for Rs. 600 and give effect to her own credit voucher by crediting Rs. 600 into her own S.B. A/c. The credit voucher in favour of Narayanan which was already prepared and used was retrieved by the petitioner in a bad to discard it in a corner and keep it infructuous. Since credit entry in Narayanan's passbook and ledger were already made by the cashier Vidya she vainly searched for the voucher in favour of Narayanan which has been snatched away by the petitioner. Therefore the cashier has scored out the credit entry and the ledger entry in the pass book of Narayanan relating to Rs. 600. Thus the remittance of Rs. 600 into the account of Narayanan is linked with petitioner's over drawal of Rs. 600 from her S.B. A/c. on 10-8-83.

9. The bearer cheque for Rs. 1000 payable to Mr. Suppaya by South Indian Bank, Othapalam was presented by one Muthulagan to the petitioner on 15-7-83 for the purpose of crediting Rs. 1000 to his S.B. A/c. The bearer cheque was not signed by Muthulagan who presented it. The petitioner herself encashed the bearer into cheque and paid the money her own S.B. A/c. after crossing on the cheque was cancelled by the bank, with an endorsement by the petitioner herself on the reverse of the cheque. Then it was sent for collection at Othapalam, the cheque was returned unpaid on 22-6-83. This compelled the petitioner to pay the money, with interest and collection charges to the Bank by debiting her S.B. A/c. suitably. The dishonoured cheque was returned to the petitioner. These fraudulent transactions were brought to the knowledge of the Regional Manager. The Administration Officer conducted a departmental investigation on 17th and 18th August, '83 and his report dt. 13-9-83 was submitted on whose basis the charge sheet dt. 31-10-83 was given to the petitioner. The second charge sheet dt. 27-2-84 is a mere amendment of the charges by way of clarification without introducing any new fact. At the domestic enquiry held on 5-11-84, the petitioner without appearing moved for adjournment and hence it was adjourned to 21-11-84. The enquiry Officer commenced enquiry on 21-11-84 in the presence of the petitioner who after hearing the charges read out, admitted them by giving a letter. The enquiry officer gave a report that the charges were proved. There upon the disciplinary authority (Regional Manager) gave petitioner personal hearing on 9-2-85. The petitioner

made her submissions at the personal hearing. The disciplinary authority after considering the representations passed the order for dismissing the petitioner from service on 14-2-85. Then she filed an appeal, which was disposed of by the Appellate Authority on 17-5-85 by modifying the punishment into discharge. The acts of misconduct committed by the petitioner have been proved by her admission of charges. The punishment has been validly imposed.

10. Later the petitioner gave a mercy appeal to the Chief General Manager. On 16-12-87 only, she has raised the I.D. before the conciliation authority. Thus there is considerable delay in raising the dispute. The petitioner's references to community, status and family are irrelevant. That she did not cause any financial loss to the Bank cannot alter or efface the misconduct. The respondent was having the necessary evidence required to prove the charges at the domestic enquiry. Petitioner's admission obviated the need of proof. Petitioner's past record of service need not be looked into, since the acts of misconduct are serious. The allegation that the Branch Manager persuaded the petitioner to admit the charges by representing that only minor punishment would be given to her is false. After having admitted the charges, the petitioner cannot retract and plead that she is not guilty of them. The submissions made by the petitioner were duly considered by the disciplinary authority. The acts committed by the petitioner are pure acts of defalcation only. The claim is liable to be dismissed.

11. Points for consideration are as follows :-

1. Whether the domestic enquiry has been conducted fairly and in accordance with the legal procedure contained in Sasuri Award and Bi-partite settlement?
2. Whether petitioner's admission of charges is genuine and not vitiated?
3. What are the acts misconduct proved by petitioner's admission?
4. Whether the punishment of discharge is just and adequate and the same is liable to be reduced?

12. The Petitioner Elavarasi examined herself as WW1. The Respondent-Bank examined the then Branch Managers of Pudukottai Branch as M. Ws 1 and 2. Exhibits W1 to W.15 and M1 to M.15 have marked. In the claim statement the petitioner has extracted the relevant parts contained in clause 19.12(c) of Bi-partite settlement. The correctness of this clause of the settlement has not been disputed. This clause contemplates that the disciplinary authority after framing the charges and if it feels that the punishment of discharge or dismissal is not needed it can inform the employee that he will be given a certain punishment (other officer at the first hearing on 5-11-84 but on the other than dismissal or discharge) for the charges if confessed and it is then open to the employee to make a voluntary admission and plead for any one of the lesser penalties. This course is intended obviously to be adopted only when the disciplinary authority decide or concludes before the discharge or dismissal will not be a deserving punishment considering the matter of misconduct and when only such conclusion in respect on the nature of the punishment the disciplinary authority is at liberty to give up an enquiry and short circuit the proceedings by straight-away offering a lesser punishment and inviting the employee to admit the without going through full-fledged domestic enquiry. In the present case, the disciplinary authority has not chose to adopt this course of obviating a domestic enquiry as contemplated in clause 19.12 (c). We cannot find fault with the disciplinary authority's conclusion at the initial stage itself that the punishment of discharge or dismissal is not warranted in the case of the petitioner and consequent failure to invoke the clause 19.12 (c). We cannot blame the authority for not invoking the said clause.

13. Therefore a full domestic enquiry has been contemplated and the Domestic enquiry officer has started the enquiry on 5-11-84. When it was adjourned to 21-12-84. The petitioner did not appear before the Domestic Enquiry Officer at the first hearing on 5-11-1984 but on the other

hand, an adjournment application prayed for one month was sent by her to the Branch Manager, who in turn placed in before the domestic enquiry Officer. He adjourned the enquiry to 21-11-84 as stated in Ex. W. 5, proceedings of the Domestic Enquiry Officer. On 21-11-84, the petitioner is said to have given a letter admitting the charges. This is marked as Ex. M.10. The act of admission is not recorded by the Domestic Enquiry Officer in the form of question and answer. In this alleged letter of admission the petitioner just says that she is sorry for the serious mistakes committed, that she would not repeat such mistake in future and she might be forgiven. The letter Ex. M.10 containing the admission is addressed not to the Domestic enquiry officer, but to the Regional Manager himself. The petitioner WW1 deposed that she was persuaded to give such admission by the then Branch Manager Krishnasamy who is M.W 2. This persuasion or advice was that if she admitted the charges she would be let-off with a minor punishment and that her admission would help the authorities in saving the officer Mr. Arugmugham who was responsible for cancelling the crossed Draft presented by Narayanan on 9-8-83, M.W.1. Krishnasamy denies having tendered any advice to the petitioner that she would benefit by admitting the charges and receiving some minor punishment. He deposed that he personally met WW1 at her residence at Pudukottai and served the suspension order. All these facts examined together support the inference that it is all probability the petitioner was persuaded to make confession of the charges and be satisfied with minor punishment. In spite of persuasion and advice given by M.W2 Krishnasamy, the confession made by WW1 in Ex. M.10 letter addressed to the Regional Manager cannot be said to be procured by coercion and undue influence. The petitioner has not given any reply to the charges and she has taken more than enough time to present the confessional letter Ex. M.10. I therefore hold that the confession is voluntary in spite of there being acts of advice and persuasion done by the superiors. The enquiry notice Ex. 4 puts to her that she is entitled to engage a defence assistant to be chosen by herself. The petitioner being the daughter of a retired officer and wife of another Officer cannot be expected to be ignorant of her rights and duties in the matter of facing the Domestic enquiry. The service code does not prevent the Domestic enquiry officer from accepting the confession as genuine taking it as proof of the charges and dispensing with the examination of management witnesses. I therefore hold that the confession was voluntarily made by the petitioner, that the Domestic enquiry has been held fairly and in accordance with the rules and that the confession made by the petitioner is a voluntary one.

14. The next question is what acts of misconduct are proved by the confession and also the evidence recorded before us. The acts committed by the petitioner in relation to the bearer cheque given to her by Subbiah for Rs. 1000 on 15-7-83 form one series which along with her acts regarding a crossed draft presented by Narayanan and her Overdraft of Rs. 500 from her S.B. A/c. on 10-8-83 are said to constitute gross misconduct falling within the definition of clause 521 (4) I of the Shastry Award. The bearer cheque presented on 15-7-83 for Rs. 1000 is marked as Ex. M.2. The evidence of WW1 Elavarasi, supported by the pleadings of both parties proves that the bearer cheque which was ultimately dishonoured by Othapalam Branch of South Indian Bank Ltd., was presented to WW1 on 15-7-83 by the bearer Subbiah whose signature is found on the reverse of the cheque. It is her case that Subbiah who is the payee, as well as the bearer, owed a debt of Rs. 1000 to a petitioner's husband and therefore he authorised the petitioner by negotiation to avail the proceeds of Ex. M.2 cheque on 15-7-83. Ex. M.1, which is copy of the S.B. A/c ledger entries of the petitioner shows that on 15-7-83 a sum of Rs. 1000 representing the value of Ex. M.2 (Cheque) was credited to her account. It is an accepted fact that this cheque was allowed to be credited in petitioner's S.B. A/c by the Officers of the Pudukottai Branch as there was nothing irregular in a member of the staff, accepting a bearer cheque from a person known to her or her spouse. The petitioner has accepted the negotiation of Ex. M.2. cheque and received payment for the same by the Bank through making a credit entry in her account on 15-7-83. The cheque ultimately

bounced compelling the petitioner to reimburse the bank by actually paying the whole amount with interest and charges. The evidence of Subbiah is not before us and therefore there is no reason for suspecting the bonafide nature of her act of receiving the cheque as a bearer herself and realising the amount by crediting the amount into her own S.B. A/c. with the consent of superiors. I am therefore of the view that the conduct of the petitioner in the matter of the bearer cheque given to her by Subbiah is not a misconduct in terms of the Respondent's service code and the Sastry Award.

15. With reference to the crossed draft in favour of Narayanan presented by him to the petitioner at the Bank's counter on 9-8-83, neither Narayanan the student nor his father who is said to have given an oral complaint has been Elavarasi. The Wrong committed by the petitioner is that opened by the officer Arumugam on a request made by Narayanan himself who is otherwise known to Mr. Arumugam. This is sound in the evidence of WW1 Elavarasi. The wrong committed by the petitioner is that after the crossing was opened by the officer Arumugam she has not remitted the amount on 9-8-83 in the S.B. A/c. of Narayanan, but has retained the amount with her till the morning of the next day 10-8-83. WW1 has after all made a show of remitting this amount of Rs. 600 into Narayanan's account with the help of Ex. M.8 a remittance voucher. The cashier Vidya on that day has posted the credit entry in the S.B. A/c. of Narayanan on 10-8-83 as shown by copy of the ledger available in the records but not marked as an exhibit. According to the counter of the Respondent the voucher Ex. M.8 was purposely thrown into an inaccessible corner by the petitioner and after suppressing Ex. M.8 she prepared a remittance voucher in her own favour which is Ex. M.9 and credited her S.B. A/c. with Rs. 600 belonging to Narayanan. In using the amount of Rs. 600 as she liked she did prepare a self serving voucher Ex. M.9 for crediting her own A/c. and further overdraw Rs. 500 on 10-8-83 itself from her S.B. A/c. when actually her account at that time had only Rs. 6.96P. The facts thus proved are that the petitioner WW1 has not discharged her duty in relation to Narayanan's S.B. A/c. and the draft in his favour, but on the other hand she has retained Narayanan's cash of Rs. 600 with her for day and at the same time got an O.D. of Rs. 500. It may be said that O.D. by itself is not a serious misconduct if at all it is a misconduct. The averment in page 2(para-2) of the counter filed by the respondent reveals that even according to the Respondent O.D. facility availed by an employee from S.B. A/c. is a matter to be viewed seriously. It is not the respondent's plea that such O.D. amounts to breach of any specific rule. At any rate the punishment for overdraft cannot be discharged or dismissal.

16. On a careful consideration of the evidence, I am of the opinion that the petitioner's retention of Rs. 600 belonging to the student Mr. Narayanan and her failure to credit the same into his account on 9-8-83 is a gross misconduct which is proved by her own admission and documentary evidence and the same is punishable under paragraph 521.4 (J) of the Sastry Award read with Desai Award. The petitioner has not been found guilty of any misconduct in her past service of more than 15 years. As a gullible woman she would have yielded to the advice of her Branch Manager and made the confession with the hope of getting minor punishment. Confession as found in Ex. M.10 is quite bald in nature and it does not reveal the full story. The earliest context that she has referred to advice given by Orders to admit the charge in her appeal (Ex. W.9) dt. 19-3-85. The next stage wherein she referred to the Branch Manager's advice is her mercy petition Ex. M.11 dt. 4-6-85 to which is attached an explanation regarding the charges. In this explanation she says, that she handed over Rs. 600 to Mr. Narayanan on 10-8-83 in an effort to mitigate her conduct. In view of her past service record which does not contain any blemish the absence of any monetary loss to the bank and the smaller magnitude of her failure to credit Rs. 600 which no doubt amounts to temporary misappropriation and the circumstances of the case I consider that the punishment of discharge with payment of one month's salary and other benefits is too serious and extreme and that the petitioner deserves to be awarded a lesser punishment in the

interest of justice. In this approach, her social or community background has not been taken into account. The smallness of the gross misconduct and her past record will justify a lesser punishment instead of the punishment of discharge. I am inclined to impose the punishment of 2 increments cut with cumulative effect and set aside punishment of discharge. Her appeal was dismissal on 17-5-85 and her mercy petition was dismissed on 5-6-85. She has approached the conciliation authority namely Asst. Labour Commissioner (Central) by belatedly filing Ex. W.11 petition on 16-2-87. It will therefore be proper for us to deny wages to the petitioner on account of the delay committed by her between 5-6-85 to 16-2-87. She shall forego backwages upto 31-1-87 and be entitled to receive backwages only from 1-2-87. She shall be given continuity of service and other attendant benefits. Point 4 is answered accordingly.

17. In the result, an award is passed setting aside the punishment of discharge and directing the respondent Bank, to reinstate the petitioner in service giving her continuity of service and attendant benefits. In the place of discharge, the petitioner shall suffer the punishment of cut of two increments with cumulative effect, the increments thus cut being those accruing in 1985-86. She shall be paid full backwages except for a period of 12 months commencing from 14-2-85. No costs.

Dated 26th day of February Nineteen Ninety three.

THIRU M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal
WITNESS EXAMINED

For Worker :
WW1—Tmt. T. Elavarasi (petitioner-worker).
For Management :
M.W.1.—Thiru M. Chidambaramathan.
M.W.2.—Thiru S. Krishnaswamy.

DOCUMENTS MARKED :

For Worker :
Ex. W.1 28-9-83—Suspension order issued by WW1—xerox copy.
Ex. W.2 31-10-83—Charge sheet -do-
Ex. W.3. 27-2-84.—do-
W.4 22-3-84.—Enquiry notice -do-
W.5 22-3-84.—Proceedings of the Enquiry Officer -do-
W.6. 22-3-84.—Findings of the Enquiry officer -do-
W.7 24-1-85.—Second show cause notice issued to WW1—xerox copy
Ex. W.8 14-2-85.—Dismissal order—xerox copy.
W.9. 19-3-85.—Appeal preferred by WW1 before the Chief Regional Manager, Regional Office SBI, Madras—copy.
W.10 17-5-85.—Order of Appellate authority—xerox copy.
W.11. 17-5-85.—2-A petition filed by WW1 before conciliation Officer—copy.
W.12. 7-4-87.—Counter filed by the Management to Ex. W.11 before the Conciliation Officer—copy.
W.13. 26-7-87.—Reply to Ex. W.12 filed before the conciliation officer—xerox
W.14. 5-11-87.—Letter from Thiru G. Paniyakodi, Authorised Representative for WW1 to the conciliation officer—copy.
W.15. 10-12-87.—Conciliation report—copy.
For Management :
Ex. M.1.—Savings Bank Ledger sheet of WW1 A/c. No. S. 93 for Feb. 83.
M.2. 15-7-83.—Cheque No. 113073 issued by the South Indian Bank Ltd., Ottapalam.
M.3. 3-8-83.—Current account pay-in slip for Rs. 1000 to the credit of Thiru R. Ruthalagu issued by SBI.
M.4. 10-8-83.—Cheque return slip for Rs. 1000 from the South Indian Bank, Ottapalam.
M.5. 3-8-83.—Draft in favour of Thiru V. Narayanan for Rs. 600 issued by State Bank of India, Madurai.

- M.6. 4-8-83.—Cheque collection return advice from SBI, Ottapalam.
- M.7. 10-8-83.—SBI with drawal slip for Rs. 500.
- M.8. 10-8-83.—S.B. Credit voucher for Rs. 600 in favour Thiru V. Narayanan.
- M.9. 10-8-83.—Cashier's receipt scroll-pudukottai.
- M.10. 21-11-84.—letter from WW1 to the Management Bank-xerox.
- M.11. 5-6-84.—Mercy petition submitted by WW1 to the Chief General Manager LHO, SBI, Madras-1. xerox copy.
- M.12. 5-6-84.—Savings bank pass book of Thiru Narayanan bearing SB A/c. No. 13542.
- M.13. 5-6-84.—Savings bank pass book of Thiru R. Muthalagan bearing S.B. A/c. 974.
- M.14. 20-7-83.—Returned unpaid cheque for Rs. 1000.
- M.15. 11-5-85.—Personal hearing given by the Appellate authority to WW1 regarding proposed punishment xerox copy.

नई दिल्ली, 3 मई, 1993

कां० 1072:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, इन्डस्ट्रियल फीनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-4-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/20/92-आई आर बी-2]
वी०के० वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd May, 1993

S.O. 1072.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Industrial Finance Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on 27-4-1993.

[No. L-12011/20/92-IRB II]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA; PRESIDING OFFICE; CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL; NEW DELHI
I.D. No. 68/92

In the matter of dispute between :

Maha Sachiv,
All India Industrial Finance Corporation Employees Association,
12th Floor,
Bank of Baroda Bhawan,
16, Sansad Marg,
New Delhi-110001.

Versus

General Manager (Administrative and Personnel),
Industrial Finance Corporation of India,
Bank of Baroda Bhawan,
16, Sansad Marg,
New Delhi-110001.

APPEARANCES :

B. K. Joseph for the Union,
Shri S. C. Pandey for the Management.

AWARD

Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. 12011/20/92-I.R.B.-2 dated 30-7-92 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the claim of All-India Industrial Finance Corp. Employees Association that the Management of I.F.C.I. has not adopted all welfare schemes prevalent in I.D.B.I. for implementation in I.F.C.I. in accordance with the agreement dtd. 5-9-90, is correct? If not, which are the schemes remaining to be so adopted and what directions are called for in the matter "

2. The case was fixed today for filing of the written statement when the representative for the union made statement that the matter regarding remodelling of welfare scheme was under negotiation with the management and the chairman of the management had assured to settle the issue amicably. No dispute, therefore, exists at present between the parties and No dispute award may be given in this case. In view of this statement no dispute exists between the parties. The statement was duly signed by the Vice President of the Union as well as Shri S. C. Pandey on behalf of the Management. No dispute exists between the parties and No dispute award is, therefore, given in this case leaving the parties to bear their own costs.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

कां० 1073:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, युनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/290/90-आई आर बी-2]

वी०के० वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1073.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 3-5-1993.

[No. L-12012/290/90-IR.B-II]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARIAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR
Industrial Dispute No. 1 of 1991

In the matter of dispute between :

The General Secretary,
Union Bank Employees Union
625/1201-33, Murari Nagar,
Faizabad Road, Lucknow.

AND

Dy. Zonal Manager,
Union Bank of India,
Zonal Office, Hotel Clark Awadh,
Lucknow

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/290/90-IR.B-2 dated 26-12-90 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the action of the management of the Union Bank of India in stopping one increment of Sri Ramesh Chandra, Peon with permanent effect vide

order dated 28-7-81 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?

2. In the instant case parties to the dispute filed a settlement on 12-4-93, with the request to pass the award in the light of the settlement. Settlement was read over and explained to the parties. The terms of the settlement is as under—

1. That the punishment of stoppage of one increment imposed vide order dated 28-7-81 is set aside.
2. That the workman will be paid arrears on account of increment which was stopped by the management at the rate of 50 per cent of what he would have earned had the punishment been not imposed on him.
3. Besides the above, Sri Ramesh Chand will not be entitled to any benefits monetarily or otherwise of any nature whatsoever.
4. The workman will not give any cause for complaint in future.
5. That it has been actually agreed by the both the parties that this settlement fully and finally resolves the entire matter of dispute under reference between the Union and the management of the bank.
3. Thus from the above it is abundantly clear that there remains no dispute between the parties for adjudication.
4. Reference is answered in the light of the above terms of settlement.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

का०ग्रा० 1074 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, युनियन बैंक ग्राफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिकी विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/652/87-डी-2(ए)]

वी०के० वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1074.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 3-5-93.

[No. L-12012/652/87-D2-A]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 69 of 1988

In the matter of dispute between:

Sri Harishanker Thakur,
C/o Sri V. N. Sekhari,
26/104, Birhana Road,
Kanpur.

AND

The Regional Manager,
Union Bank of India,
Regional Office,
Pandu Nagar, Kanpur.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification number L-12012/652/87-D.II(A) dated 27-5-88

has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the action of the management of Union Bank of India in terminating the services of Sri Hari Shanker Thakur from service and not considering him for further employment while recruiting fresh hands under section 25H of the I.D. Act is justified? if not, to what relief the concerned workman is entitled?

2. The workman's case in short is that with a view to avoid appointment of permanent hands the bank adopted a practice of appointing temporary/daily rated employees for doing the work of permanent nature. The bank terminated the services of such temporary employees and appointed fresh hands without giving any chance of re-employment to those temporary employees whose services had been terminated. The said practice on the part of the bank amounts to unfair labour practice. In accordance with the said policy, the bank appointed the workman as a peon-cum-waterman on 1-6-81. The workman worked till 5-9-81, as peon-cum-waterman against a regular vacancy after which he was retrenched w.e.f. 6-9-81 without any reason. The workman thus worked for 97 days. He was paid wages at the rate of Rs. 5 a day which was less than the minimum wage of a peon.

3. The workman alleges that at the time of his retrenchment he was not the junior most workman. Even after termination of his services new hands were appointed without giving him an opportunity of reemployment. The management thus violated the provisions of sections 25G and 25H of the I.D. Act, read with Rules 77 and 78 of I.D. (Central) Rules, 1957. Not only this, the bank also did not follow the provisions of paras 493, 495, 507, 516, 522 and 524 of modified Sastri Award. The bank also violated the various provisions of U.P. Shops and Commercial Establishment Act. Being so, the order of his termination is illegal. The workman has, therefore, prayed for his reinstatement with full back wages and all consequential benefits.

4. The case is contested by the management of the bank. The bank's case is that there being no provision for drinking water in the bank's branch, Sri Harishanker Thakur, was given a contract for supplying water to the bank employees for which he was accordingly paid. Thus there had been no relationship of Master and Servant between the parties. Sri Harishanker Thakur was never given any appointment by the bank. As such the question of violation of any provisions of I.D. Act, Shops and Commercial Establishments Act and various paras of modified Sastri Award does not arise.

5. In support of his case the workman examined himself and in support of their case, the management examined Sri S. N. Mehra, Dy. Manager Personnel of the bank.

6. It is clear from the claim statement that the workman's claims to have worked only for 97 days. As such as has been held by me in my award given in I.D. No. 94 of 86 Sri Mani Ram versus Central Bank of India, the question of violation of any provisions of the I.D. Act, and of any of the paras of the modified Sastri Award mentioned in the claim statement does not arise. This position is so even if it is assumed that Sri Harishanker had worked as a peon-cum-water boy. In this case written arguments have been filed by the workman under his signatures. Some rulings have been referred in the written arguments. Most of these rulings were considered by me in I.D. No. 94 of 86. I may state here that in the written arguments, the workman has given the reference with extracts from these rulings without filing the complete ruling. However with his written arguments he has filed the photocopy of the ruling in the case of Kamlesh Singh Versus P.O. 1987 SCC (Lab) 75. This ruling was also considered by me in I.D. No. 94/86. Therefore, the action of the management in terminating his services cannot be said as unjustified or illegal.

7. Even from the evidence, it does not look probable that he was ever appointed as temporary peon-cum-waterman. In para 7 of his claim statement it has been alleged by him that he was paid wages at the rate of Rs. 5 a day which was much less than the minimum wage of a peon. Had he been appointed as a peon-cum-waterman, there would have surely been some appointment letter and even in the absence of appointment letter he would not have been paid such a

less wage. In his cross-examination he has admitted that he was kept as a peon by one Sri Bajpai, of General Ganj Branch, Kanpur through another peon without any interview and without his making any application for the same. He admits that he never marked his attendance in the attendance register. The manager used to keep his account separately. He never got holidays as regular staff was getting. Even from his wages no amount towards P.F. was ever deducted. He used to be paid wages through voucher. He was never given any Uniform. There were five peons in the branch all of whom were permanent. He was also not paid medical allowance. After termination of his services he never made any written complaint to any bank officer. Another fact stated by him in his cross examination is that some time he was sent to post office but payment regarding it used to be made to him through voucher prepared in the name of some other person. All these facts and circumstances are sufficient for me to infer that he was never appointed as a peon cum waterman by the bank.

8. From the side of the bank Sri S. N. Mehra, has corroborated the bank's case. I see no reason to disbelieve him.

9. Hence it is held that the action of the bank in terminating the services of Sri Harishanker Thakur and in not considering him for further employment cannot be held as unjustified and illegal. Consequently he is held entitled to no relief.

10. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

कां०अ० 1075 : औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/435/89-डी-2(ए)]

वी०के० वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May 1993

S.O. 1075.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 3-5-93.

[No. L-12012/435/89-D-2A]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM LABOUR COURT PANDU NAGAR KANPUR

Industrial Dispute No. 68 of 1990

In the matter of dispute between:

State Vice President,
P. N. B. Staff Association,
E-1720 Rajaji Puram,
Talkatora Avas Vikas Colony
Lucknow.

AND

Regional Manager,
Punjab National Bank,
Chowk Faizabad

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification number L-12012/435/82-D.2(A), dated 22-2-90, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.—

"Whether the action of the management of Punjab National Bank in withdrawing the additional two increments from the salary of Sri K. N. Tripathi, Cashier cum Godown Keeper granted to him in acquiring Graduation Degree was justified? If, not to what relief the workman was entitled?"

2. The case of the Union in short is that the workman passed Shastri Examination of Sampurna Nand Sanskrit Vishwavidyalaya Varanasi in 1985. Shastri Degree with or without English of the said Vishwavidyalaya has been recognised as equivalent to Graduation (B.A.) by all the Universities, different states and even by Government of India for all purposes including further studies and appearance in competitive examinations held by the various universities, state and Government of India. The workman was initially an employee of erstwhile Hindustan Commercial Bank. In terms of various awards and settlements etc., on his obtaining the Shastri Degree the management of the bank released two increments in his favour w.e.f. 20-11-85 and allowed him two priority marks for the said qualification w.e.f. 1-1-89. However, subsequently the bank withdrew two annual increments so released in favour of the workman on the ground that the workman had not passed the Shastri Examination with English. The bank now intends to recover arrears on account of the said decision from the workman vide its letter dated 24-11-88. The Union alleges that the action of the bank is unjustified arbitrary mala-fide and illegal. The bank's action is anti Hindi. It is against the various awards and settlements as applicable to the banking industry. No opportunity was given by the bank to the workman while withdrawing the aforesaid two graded increments which amounts to punishment. Even no notice u/s. 9-A of the I.D. Act was given to the workman before effecting change in his service conditions. The Union has, therefore, prayed that the action of the management be declared as unjustified and illegal. It has further prayed that the management of the bank be directed to release the said two increments including the back arrears with all consequential benefits in favour of the workman.

3. The case is contested by the management of the bank. The management plead that the workman who is presently working as Cashier cum Godown Keeper at bank's Gonda Branch was an employee of erstwhile Hindustan Commercial Bank Limited. After the merger of the said bank with the PNB the workman became the employee of the Punjab National Bank and as such his services be governed by Rules & Regulations as are applicable to the employees of Punjab National Bank. After passing Shastri Examination without English from Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya Varanasi in 1985, the workman represented to the competent authority for sanctioning of two graded increment as provided in the bipartite settlement. On 16-4-88, the competent authority erroneously sanctioned two graded increments in favour of the workman without considering the fact that English was not one of the subject, the Shastri examination. Since the Central Government is the Appropriate Government in respect of banking industry, Rules applicable to the Central Government relating to educational qualifications are applicable to the bank employees. Further from the notification filed by the Union with the claim statement it is clear that Shastri Degree without English of Varanasi Sanskrit Vishwavidyalaya was recognised as equivalent to B.A. Degree for recruitment in service under the State Government and for admission in educational institutions run by the State Government. After detection of the mistake, the two graded increments earlier released were withdrawn. The management deny that the action taken by the management is arbitrary mala-fide or illegal or against the provisions of bipartite settlement. As per office memorandum dated 29-11-69 of Government of India, Ministry of Education & Home Affairs, Shastri with English is only equivalent to be a degree.

4. In support of their respective cases both sides have led oral as well as documentary evidence. Whereas the Union

examined the workman, the management examined Sri Arun Gupta an officer of the bank.

5. From para 5.2 of the first bipartite settlement it is evident that graduates employees are entitled to two increments.

6. The only point which needs consideration in this case is whether Shastri Degree (without English) will entail the benefits as are provided in para 5.2 of the First Bipartite Settlement or not. Whereas the Union has relied on the notification of the State Government dated 12-1-73, the management have relied upon the office memorandum dated 29-11-69 of the Ministry of Education & Home Affairs, Government of India.

7. From the notification dated 12-1-73, of Government of Uttar Pradesh, it appears that previously degree with English was considered as equivalent to B.A. Degree of a recognised university. But later on in consultation with the U.P. Public Service Commission, Shastri Degree without English was considered for appointment in the service of State, Technical Training Institutes, etc., The notification issued by the State Government as such cannot be applied to the employees of the Central Government or Industries owned and run by the Central Government or in respect of which the Central Government is the Appropriate Authority under section 2(a) of the I.D. Act. There cannot be any matter of dispute on the point that in respect of the banking industry the appropriate government is the Central Government. Therefore, to my mind if such a notification had been issued by the Central Government, the case of the Union in respect of the workman would have surely stood on much better footing.

8. The management witness by means of his affidavit has referred to the documents filed with the application dated 23-1-92, by the management. Document No. 2 is the copy of office memorandum dated 29-11-69 from the Ministry of Home Affairs, New Delhi, on the subject of recognition of examination conducted by Varanasi Sanskrit University Varanasi as equivalent to various educational qualifications in the general set up of education for the purpose of employment in the Central Government. As No. III is referred Shastri with English or Old Shastri or Shastri Examination with special examination in additional subjects with English as one of the two subjects, i.e. Varishta Shastri. It has been described as equivalent to B.A. Degree.

9. Document no. 3 is another letter dt. 3-8-89, from the Ministry of Home Affairs, Department of Education, New Delhi. From it, it appears that the name of Sanskrit Vishwavidyalaya Varanasi was changed to Sampurna Nand Sanskrit Vishwavidyalaya. It was again reiterated in this letter that only Shastri Degree with English of the said University would be equivalent to B.A.

10. No doubt in para 5.2 of the First Bipartite Settlement, it is no where specifically stated that graduation should be with English by an employee, but to my mind the word graduation would be seen in the light of the office memorandum dated 29-11-63 and letter dated 3-8-89 referred to above.

11. I am therefore of the view that the workman would have been entitled to release of two annual increments if he had done Shastri (with English) from the said University and not otherwise. The action of the management, therefore, cannot be said as mala fide or arbitrary. If previously by mistake two annual increments were released in favour of the workman, the management had full authority to rectify the said mistake. The question of giving of any notice or the question of change in Services condition does not arise at all. The question of affording any opportunity to the workman before the rectification of the mistake would not have improved the matter for the workman and now when the question is before the Tribunal, the question of notice to the workman before withdrawing of the two increments becomes meaning less.

12. Hence the action of the management of Punjab National Bank in withdrawing the additional two increments of the workman granted to him earlier under mistaken view General held as unjustified. Accordingly the Union/workman is entitled to no relief.

13. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

का०आ० 1076 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, युनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/630/89-डी-2(ए)]

वी०के० वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1076.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 3-5-1993.

[No. L-12012/630/89-DII (A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 121 of 1990

In the matter of dispute :

BETWEEN

Sri O. P. Misra, Assistant General Secretary,
Union Bank Employees Union
120/459 Lajpat Nagar,
Kanpur.

AND

The Chief Manager (Personnel)
Zonal Office Union Bank of India
Hotel Awadh Clark
8 Mahatma Gandhi Marg
Lucknow.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/630/89-D.II (A) dated 24-4-90, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Kya Deputy General Manager Union Bank of India Lucknow द्वारा Bhutpurva Part Time Pass Book Writer Sri M. P. Chaubey को दिनांक 26-4-87 से निशकासित करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो सम्बन्धित कर्मकार किस अनुतोष के हाकदार है ?

2. The case of the Union is that the workman was appointed as Part time Pass Book Writer on 16-12-77, and was posted in the General Ganj Branch of the bank at Kanpur. He was paid 1/3rd of scale wages with annual increments payable to part time permanent employees. However, vide retrenchment order dated 25-4-87, he was retrenched on 27-4-87 all of a sudden. During the conciliation proceedings before the ALC (C) Kanpur, the management of the bank admitted that there were in all 7 part time Pass Book Writers in the service of the bank, one in U.P. and six in Gujarat and all the 7 of them were retrenched from Bank's service. The Union challenges the order of retrenchment on the ground that it is illegal being in violation of the provisions of para 522(6) of the Sastri Award and section 25-N of the I. D. Act, 1947. The Union has, therefore, prayed for revocation of the said order of retrenchment and for reinstatement of the workman with full back wages and all consequential benefits.

3. The management plead that in 1987, the management of the bank decided to abolish the post of parttime Pass Book Writers and assign the said work of pass book writing to permanent full time staff. In pursuance of the said decision, the workman was retrenched after complying with the provisions of Section 25-F of the I. D. Act. The management deny violation of Section 25-N of the Act and any

provision of para 522(6) of the Sastri Award. It may be stated that in the entire written statement it is nowhere stated whether the workman joined service as part time Pass Book Writers on 16-12-77 or not.

3. In support of its case, the Union has examined, the workman and in support of their case, the management examined Sri R. K. Jain Manager, Lucknow Branch of the bank. He was the manager General Ganj Branch at Kanpur from 6-6-83 to 12-7-87.

4. As stated by me above it is the case of the Union that the workman was appointed as Part time Pass Book Writer on 16-12-77. This fact has neither been admitted nor denied in the written statement specifically. However, this fact is admitted from the document annexure 1 to the affidavit of the management. It is the copy of order of retrenchment dated 25-4-87. In the first paragraph of this order it is written that the workman had been working as a parttime pass Book Writer since December 16, 1977.

5. During the course of arguments, Sri O. P. Misra, the authorised representative for the Union has challenged the order of retrenchment only on two grounds. One is that it is in violation of Section 25-N of the Act and the second is that it is in violation of para 522(6) of the Sastri Award. During the course of arguments Sri Misra has admitted that the management fully complied the provisions of Section 25-F of the Act at the time of retrenchment of the workman.

6. In para 5 of this affidavit the management witness has deposed that on 27-4-87, the order of retrenchment dated 25-4-87 was given to the workman in the presence of Sri S. N. Mehra, the Personnel Officer, Zonal Officer Lucknow and Sri M. N. Modi, the then Accountant working in the General Ganj Branch of the Bank at Kanpur alongwith cash by way of one month's salary in lieu of notice and retrenchment compensation. But the workman refused to accept the same. Sri Misra did not cross examine the witness on this point. Rather to make the facts more clear a question was put to the management witness in reply to which the witness stated that it was he who had tried to serve the retrenchment order on the workman and pay compensation alongwith wages in lieu of notice to him on 27-4-87.

7. So far as the facts of this case is concerned Section 25-N of the Act is not applicable. Section 25-N falls in Chapter VB of the Act. Section 25-K lays down that the provisions of this chapter shall apply to an Industrial Establishment in which not less than 100 workmen were employed on an average per working day for the preceding 12 months. It shall however not apply to an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittantly. The expression Industrial Establishment is defined in Section 25-L of the Act. From the definition of Industrial Establishment it is evident that the Banking Industry does not fall within the definition of Industrial Establishments. Hence the order of retrenchment cannot be challenged on this score.

8. Para 522(6) of the Sastri Award lays down that in cases of contemplated closing down or of retrenchment of more than (5) employees, the employees shall be given two months notice with a statement of reasons for the proposed action and in the event of any representation from any such employee the management shall pass an order.

9. Annexure I to the affidavit of the management witness is the order of retrenchment dated 25-4-87. From the order of retrenchment it appears that the workman was paid one month's notice in lieu of statutory notice and retrenchment compensation in accordance with the provisions of law. The reasons for abolition of the post of part time Pass Book Writer is also found given in it. It is stated that the management had taken a decision to abolish the post of part time Pass Book Writers and to get the work done by them from permanent full time staff. It, therefore, follows that two month's notice as contemplated by para 522(6) of the Sastri Award was not given to the workman.

10. In para (4) of the claim statement it is specifically alleged by the Union that during Conciliation proceedings before ALC (C) Kanpur, the management of the bank admitted that there were 7 part time Pass Book Writers in the service of the bank one in U.P. and six in Gujarat. In reply to this para the management simply write that the contents of this para of the claim statement are not denied to the extent that retrenchment of part time Pass Book Writer and the rest of he part is denied. It is further stated

in reply to this para by the management that three part time Pass Book Writers in Gujarat contested their case before C.G.I.T. Ahmedabad, but their claims were not upheld by the Tribunal. The copy of the Award, although stated to have been filed with the written statement was not filed with the written statement. The same has been filed by the management witness with his affidavit. Thus there is no specific denial of the fact whether or not such a statement was made from the side of the management before ALC (C) Kanpur. Whether such a statement was made or not the management should have atleast come out with the facts as to how many part time Pass Book Writers, in pursuance of the decision taken were retrenched. So decision taken as accepted even by the management that in all 7 pass book writers were retrenched.

11. During the course of his arguments Sri Misra conceded that in the whole of U.P. in the service of the Union Bank, there was only one part time Pass Book Writer and he was the workman in question. The question is, whether in such a state of affairs provisions of para 522(6) of the Sastri Award would apply or not. To my mind it would not apply as the Union for retrenchment is a District. It would have been quite different if more than 5 part time Pass Book Writers have been retrenched from Kanpur Region of the Bank. It being so even para 522(6) of the Sastri Award would not apply in the present case.

12. On no other ground the order of retrenchment has been challenged before me by Sri O. P. Misra. Hence it is held that the action of the management in terminating the services of the workman w.e.f. 26-4-87 cannot be held as unjustified.

13. Reference is answered accordingly.

ARIAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

कां० प्रा० 1077 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/394/88-डी-2(ए)]

वी०के० वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1077.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Allahabad Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 3rd May, 1993.

[No. L-12012/394/88-D.2A]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARIAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 157 of 88

In the matter of dispute between :

Sri P. K. Roy,
N. 15/62, G. Vinayaka
Barigaibi,
Varanasi.

AND

Assistant General Manager,
Allahabad Bank,
Nadesar,
Varanasi.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification number L-12012/394/88-D.2(A) dated 18th November, 1988, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the action of the management of Allahabad Bank in relating to their Nadeshar Branch in dismissing Sri Prabhat Kumar Roy, Clerk-cum-Cashier from service vide orders dated 23rd June, 1986 by the Regional Manager and disciplinary authority is legal and justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?

2. The workman Sri Prabhat Kumar Roy and Sri P. N. Jaitly Assistant General Manager on behalf of the Allahabad Bank filed a settlement in this case. It was duly verified before me by the workman and Sri P. N. Jaitly on behalf of the management. It is lawful. Accordingly the reference made by the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi, to this Tribunal is decided in terms of the settlement.

3. The settlement filed in this case will form part of this award.

ARJAN DEV, Presiding Officer

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

In the I.D. Case No. 157/88

Prabhat Kumar Roy

Vs.

Allahabad Bank, Varanasi

Sir,

It is most humbly submitted that consequent upon commission of gross misconduct the workman concerned was charge-sheeted under Clause 19.5(C) of the 1st Bipartite Settlement, dated 19th October, 1966 vide charge-sheet No. RO/VARA/S/02102 dated 12th September, 1984 wherein departmental enquiry was held and charges contained therein, were found proved, and the workman concerned was dismissed from the service of the Respondent Bank vide order No. RO/VARA/S/05489 dated 23rd June, 1986 against which the present reference is pending. However, the workman concerned at last repented and finally approached the management for an amicable settlement. Keeping in view the repenting posture of the workman concerned as also his assurance to ensure non-reoccurrence of the misconduct proved against him, the matter of dispute involved in the matter of reference, has been amicably settled between the workman concerned and the Management on the following term and conditions :

TERMS AND CONDITIONS OF THE SETTLEMENT

1. That the workman concerned repents/regrets and tenders unqualified apology for the charges contained in the charge-sheet aforesaid.

2. That the workman concerned further assures that he will sincerely ensure non-reoccurrence of such incident of gross misconduct as proved against him, and that he will discharge his duties faithfully, sincerely and obediently and will not give any chance of complain to his superiors.

3. That keeping in view the repenting posture of the workman concerned and his unqualified apology and assurance aforesaid, as also with a view to give him a last chance, the Management now agree to reinstate him as clerk-cum-cashier, the designation which he was having before his dismissal in the service of the respondent bank on terms and conditions mentioned below :

(A) that Shri Prabhat Kumar Roy, the workman concerned, will not be paid any back wages and allowances nor he will be entitled to any annual increment and any other benefit/privilege for the intervening period from the date of his dismissal from service till he is reinstated and he reports at the place of his posting after reinstatement. However, the said intervening period will be counted in the length of service only for his superannuationary benefits other than Provident Fund. It is also certified that any benefit/privilege available to him or which

was at his credit at the time of his dismissal from service, will, however, be available to him after his reinstatement.

(B) that the punishment of his dismissal from service, awarded to him earlier, is modified and in place thereof punishment of stoppage of one annual increment for a period of one year, to be counted from the date of his joining duty hereafter, is to be imposed under clause 19.6(d) of the 1st Bipartite Settlement, and, accordingly his one annual increment is hereby stopped for one year under the said clause.

(C) that after his reinstatement hereafter, the said Shri Prabhat Kumar Roy will be posted in any branch or Office out of Uttar Pradesh to which he has no objection.

(D) that the workman concerned will be reinstated within a period of one month from the date of this settlement. His basic pay shall be refixed at the same stage of scale of pay in terms of Vth Bipartite Settlement at which stage he was last drawing his basic pay at the time of his dismissal from service.

(E) His chance for selection to higher functional special allowance posts and/or promotion during the intervening period, i.e., from the date of his dismissal till his reinstatement, shall be deemed to have been forfeited/lapsed.

4. That thus this fully and finally resolves the entire matter of dispute under the present reference between the parties.

5. That one L.C.A. Case No. 2/89 is also pending before this Hon'ble Tribunal between the same parties as are in the present case. Consequent upon the above settlement the workman concerned ceases to have any claim there-in and as such the workman concerned does not press the L.C.A. case No. 2/89 pending before this Hon'ble Tribunal.

PRAYER

It is, therefore, prayed that the award in terms of the above settlement may kindly be given in the interest of justice in the present case.

for the workman concerned.

(Prabhat Kumar Roy)

the workman concerned.

for the management :

1. (P. N. Jaitly)

Asstt. General Manager.

2. (M. K. Verma)

Bank's L.L.R. &

Authorised Representative.

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

Kanpur,

Dated : 20-4-1994.

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

का०आ० 1078 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अन्वंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट से प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/650/87-डी-2(ए)]

बी०के० वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1078.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in industrial dispute between the employers in relation to

the management of Allahabad Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 3-5-1993.

[No. L-12012/650/87-D.2(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR
Industrial Dispute No. 135 of 1988

In the matter of dispute :

BETWEEN

Sri Jai Prakash C/o Sri Harmangal Prasad 36/1 Kailash
Mandir Kanpur.

Sri R. K. Tripathi C/o Sri V. N. Sekhari 26/104 Bir-
hana Road, Kanpur.

AND

The A.G.M. Allahabad Bank Swarup Nagar, Kanpur.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/650/87-D.II (A) dated 21st October, 1989, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the action of the management of Allahabad Bank in terminating the services of S/Sri Jai Prakash and Rajendra while recruiting fresh hands under Section 25-H of the Act is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?

2. On 5-3-93, when the case was taken up for hearing none appeared from the side of the workmen despite issue of notice on 5-11-92. 5-3-93 was the date for the cross examination of the workmen. I may mention that even the workman Sri Rajendra Kumar has not filed his affidavit evidence in the case. Sri M. K. Verma appeared for the management on 5-3-93. Thus it appears that the workmen are not interested in prosecuting their case.

3. In the facts and circumstances of the case a no claim award is given against the workmen.

4. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

कां०ग्रा० 1079 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/217/86-डी-2(ए)]

वी०के० वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1079.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Allahabad Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 3-5-1993.

[No. L-12012/217/86-D.2(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR
Industrial Dispute No. 180 of 1947

In the matter of dispute :

1052 GI/93—11.

BETWEEN

Sri Shyam Sunder Saini
C/o Sri V. N. Sekhari
26/104 Birhana Road
Kanpur.

AND

The Assistant General Manager,
Allahabad Bank Zonal Office
113/58 Swarup Nagar, Kanpur.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/217/86-D.II (A) dated 1-12-87, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

Whether the action of the management of Allahabad Bank in terminating the services of Sri Shyam Kumar Saini w.e.f. 20-5-82 and not considering him for further employment under Section 25-H of the Act is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?

2. In this case an order to pass a no claim award was passed by the Tribunal on 18-12-92. Subsequently the said order was recalled by the Tribunal on 21-12-92 and it was ordered that a notice be issued to the workman fixing 12-2-92 for his cross examination. On 12-2-92 neither the workman nor his authorised representative appeared in the case. Sri M. K. Verma appeared for the management. The case was adjourned to 15-4-93, for cross examination of the workman on the oral prayer of the authorised representative for the management. Again on 15-4-94, the workman did not appear.

3. Thus from the above conduct of the workman it is quite evident that the workman is not interested in the case for otherwise he must have appeared in the case, but despite issue of notice he did not appear. Therefore, a no claim award is given against him.

4. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

का.ग्रा. 1080 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में लेबर कोर्ट कोची के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/178/90-आई आरबी-2]

वी०के० वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1080.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Labour Court Kochi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employer in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 4-5-1993.

[No. L-12012/178/90-IR (B-II)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR COURT,
ERNAKULAM

(Labour Court, Ernakulam)

(Monday, the 19th day of April, 1993)

PRESENT :

Shri M. V. Viswanathan, B.Sc., LL.B., Presiding Officer.
Industrial Dispute No. 14 of 1990 (C)

BETWEEN

The Regional Manager, Bank of Baroda, Regional Office,
Kisan Jyothi Buildings, Trivandrum-1.

AWARD

8. But the main grievance of the workman is that the management did not produce the documents called for by the workman. The Ext. M-1 enquiry file would reveal the fact that the workman requested the enquiry officer for the production of four documents (i) Report of the CBI Officials, enquired into the same cases which is the subject matter of the enquiry against the workman. (ii) Report of the domestic Enquiry Officer, enquired into the same case where the charge sheeted employee was Mr. A. Bhaskaran who is one of the Bank's witnesses in the enquiry. (iii) Report of Enquiry Officer and the final order of the Disciplinary Authority against Mr. A. Bhaskaran about some financial dealings where he was punished. (iv) Details of cheques drawn by Mr. A. Bhaskaran on our branches at Puzhathi, Mathilakam and Coch'n which were returned for want of funds. But the above four documents were not produced. The said request was rejected by the Enquiry Officer. The documents 2 to 4 are in respect of one Bhaskaran who was the accountant of the bank at the relevant time. But it is to be noted that the second document i.e. the report of the domestic enquiry officer regarding the enquiry about Mr. Bhaskaran has not some importance as that enquiry was in respect of the same case. The first document i.e. the report of the CBI Officials was in respect of the case against the workman herein. So the documents 1 and 2 in the list can be treated as documents relevant for the enquiry. That documents might have been relevant for the workman to establish his innocence in the case. So the non-production of those documents can be treated as prejudicial to the workman. So this circumstance would give an indication that the workman was not given sufficient opportunity to defend his case.

9. The Enquiry Officer rejected the request of the workman to get the documents on the ground that Mr. A. Bhaskaran is not a witness in this enquiry. But the available documents would show that Mr. A. Bhaskaran was cited as a witness in the witness list submitted by the management. It can be seen that on the date of the order passed by the Enquiry Officer rejecting the request for the production of the document, Mr. A. Bhaskaran was shown as a witness on the side of the management. So this action of the Enquiry Officer would give an indication that he was not impartial. It is true that subsequently the Presenting Officer deleted the name of Mr. Bhaskaran from the witness list.

10. The other aspect for consideration at this juncture is the validity of the findings in the domestic enquiry. The charge sheet dated 17-5-1986 would show that there was an allegation against the workman regarding destruction of relevant vouchers and pages of relevant ledgers to obviate detection of the fraudulent transaction. But the evidence adduced in the enquiry would show that these documents were not in the custody of the workman. It is an admitted fact that the workman was only a Head Cashier of the Management Bank and he was not in charge of those documents. So the finding of the Enquiry Officer that the workman is also guilty of destruction of document cannot be just or proper. That finding is without any basis.

11. The charge against the workman would show that he has committed fraud. But the findings made by the Appellate Authority would show that the workman has not committed any fraud. But there were only some lapses on his part. This findings made by the Appellate Authority would make the findings of the Enquiry Officer unacceptable. The union has categorically stated about those findings made by the Appellate Authority. But that statements made by the union are not disputed by the management.

12. The union has also set up a case that the Appellate Authority imposed the punishment of stoppage of three increments with cumulative effect on the ground that there were lapses on the part of the workman in discharging his duties. But according to the union the said findings of the Appellate Authority regarding the lapses on the part of the workman are unsustainable as the workman was not given an opportunity to explain his case. It is true that there was no such charges of lapses framed against the workman. So the workman did not get an opportunity to explain his stand about the alleged lapses on the part of the workman. Thus in all respects the domestic enquiry and findings thereon are liable to be set aside. Hence, I do so.

13. In the result, the domestic enquiries and findings thereon are set aside. The management will be at liberty to adduce fresh evidence to substantiate the charges levelled against the workman."

IV. The management has not adduced any fresh evidence before this court to substantiate the charges levelled against the workman. The domestic enquiry and the findings thereon are set aside by this Court by virtue of the Preliminary Order dated 16-12-1992. Thus in effect, there is no evidence available on record to substantiate this charges levelled against the workman. The burden is upon the management to establish the guilt of the workman. But the management has not adduced any evidence to substantiate the charges levelled against the workman. Thus, the management has failed to substantiate the charges of misconduct alleged against the workman Sri T. Mukunda Prasad. If that be so, the action of the management in imposing the punishment of stoppage of three increments with cumulative effect is liable to be set aside. Hence I do so. I hold that the punishment of stoppage of three increments with cumulative effect imposed on the workman Sri T. Mukunda Prasad is unjustifiable. The workman is entitled the increments which were withheld by the management.

V. In the result, the action of the management of Bank of Baroda in stoppage of three increments with cumulative effect of Sri T. Mukunda Prasad is held unjustified. The said punishment imposed on the workman is set aside. The workman is entitled to get the increments which were withheld by the management. An award is passed accordingly. Ernakulam,

Dated : 19-4-1993.

M. V. VISWANATHAN, Presiding Officer

Appendix

Exhibit marked on the side of Management :

Ext. M-1—File containing proceedings, findings and other connected papers of the enquiry held against the workman.

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

का.आ.1081—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्रवर्तन के संरक्षित नियंत्रकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोल्लम के पंचपद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-4-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/50/91-आई आर बी-2]

वी.के. वेणुगोपाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1081.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Kollam as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Overseas Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 29-4-1993

[No. L-12011/50/91-IRB II]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,
KOLLAM

(Dated, this the 22nd day of March, 1993)

PRESENT :

SRI. C. N. SASIDHARAN
INDUSTRIAL TRIBUNAL
IN

Industrial Dispute No. 3/91

BETWEEN

The Zonal Manager, Indian Overseas Bank, Zonal, M.G. Road, Trivandrum 695001.

(Sri. G. Krishnan Nair, Advocate, Trivandrum)

AND

The Assistant General Secretary, All India Overseas Bank, Employees Union, C/o Indian Overseas Bank, Currency Chest, Sreekanthaswaram, Trivandrum 695023.

(By Sri. K. B. Pandarathil, Advocate, Trivandrum)

AWARD

This industrial dispute has been referred for adjudication to this Tribunal by the Government of India as per Order No. L-12011/50/91-IRB(II) dated 29-1-1991.

The issue for adjudication is the following :

"Whether the action of the management of Indian Overseas Bank in denying permanency to the temporary employees watchmen S/s. B. Krishnan Cutty, G. Muralidharan Nair, V. Vijayakumaran Nair, G. Bhaskaran Nair, G. Rajagopalan, S. P. Aboobacker and K. K. Rajendran is justified? If not to what relief is/are the workmen entitled?"

2. In pursuance to notices issued from this Tribunal both sides entered appearance and filed statements advancing their respective contentions. Thereafter, when the case was pending for evidence, the learned counsel for the union submitted on 7-4-1992 that there was a chance of settlement. Accordingly the case stood posted on several dates for reporting settlement at the instance of the parties. While so on 3-11-1992 when the case was called the union and its course remained absent. No adjournment was also sought on behalf of the union. Hence the union was set ex-parte and the case was accordingly closed for award. On 7-11-1992 the union filed a petition for settling aside the ex-parte order. While that petition was pending the management on 16-5-1993 filed an application stating that the matter has been settled between the parties and praying for passing a consent award as per Clause 5 of that settlement. A copy of the settlement was also filed which I am marking as Ext. M1 for convenience of discussion. The learned counsel for the workmen also made an endorsement in the application filed by the management agreeing to the fact of settlement. Since there was no objection from the management side the order declaring the union ex-parte was also set aside.

3. As requested by the parties Ext. M1 settlement is accepted and I pass a consent award on the terms of the settlement.

C. N. SASIDHARAN, Industrial Tribunal

APPENDIX

Document marked on the side of the management

Ext. M1. Memorandum of settlement dated 10-2-1993 between the management of Indian Overseas Bank and All India Overseas Bank Employees Union.

Memorandum of Settlement dated 10th February 1993 between the Management of Indian Overseas Bank and All India Overseas Bank Employees Union in the matter of regularisation of the services of Temporary Watchmen working at Trivandrum Region [Under Section 2(P) and 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947] :

PARTIES PRESENT

Representing the Employer

- Sd/-
1. Shri. K. V. Bhatt
Asst. General Manager
 2. Shri. R. M. Muthalagappan
Chief Officer
Industrial Relations Dept.
 3. Shri. B. Jagadish
Officer
Industrial Relations Dept.
 4. Shri. P. L. Veerappan
Officer
Personnel Admn. Dept.

Representing the Workmen

- Sd/-
1. Shri. L. Balasubramanian
President
 2. Shri. K. Nagappan
Vice President
 3. Shri S. Srinivasan
Secretary

SHORT RECITAL OF THE CASE

Whereas the All India Overseas Bank Employees Union affiliated to the National Confederation of Bank Employees, had raised an Industrial Dispute before the Regional Labour Commissioner (Central) Trivandrum with regard to regularisation of temporary watchmen working in Trivandrum Region of the Bank. The demand of the Union is that 7 temporary watchmen, who were being utilised by the Bank for more than 3-1/2 years on a temporary basis, should be regularised immediately as they were deprived of the benefits attributable to the permanent employees.

Whereas the conciliation proceedings in respect of the above dispute had ended in a failure on 16-7-1990 and a failure report was signed accordingly.

Whereas the Ministry of Labour had decided to refer the dispute to the Central Government Industrial Tribunal for adjudication, the dispute is still pending before the Tribunal.

Whereas the services of the 7 temporary watchmen mentioned in the dispute, were being utilised by branches and Zonal Office, Trivandrum without identifying any vacancies and sanction from Central Office. The Bank has now agreed to identify two vacancies of watchmen at Zonal Office, Trivandrum and the remaining temporary watchmen will be posted as messengers.

Whereas the parties have since discussed the said demands/issues on several occasions and have come to a settlement on some of the demands/issues, which settlement is recorded hereunder.

The parties agree that the matters agreed to under this settlement shall be binding on them in terms of Section 18(1) of the Industrial Disputes Act 1947 and that this settlement shall be filed with the appropriate authorities as required vide Rule 58 of the Industrial Disputes (Central) Rules.

TERMS OF SETTLEMENT

1. The Bank will undertake to regularise all the 7 temporary watchmen working at Trivandrum Region as on the date of the dispute. (Details given in Annexure).
2. Regularisation of the services of the 7 temporary watchmen will take effect from 1st December, 1990. The two senior most watchmen among the 7 temporary watchmen would be posted to Zonal Office, Trivandrum as watchmen. The remaining would be posted as messengers in vacancies identified by the bank. If at a later date whenever watchmen vacancies arises in Trivandrum Region the remaining five members may opt for the post of watchmen at such places and preference will be given to them.
3. The process of regularisation of the services of the temporary watchmen cited above would be subject to such temporary employees being in conformity with the usual norms of recruitment of the bank and the various Governments guidelines laid down for such purposes.
4. Notional seniority would be considered only from the date of regularisation of services. No arrears would be payable from the period till date of settlement. However, they would be eligible for medical aid expenses-Term I, leave etc.
5. This agreement will be submitted to the Central Government Industrial Tribunal Trivandrum with a request for "Consent Award" on the above terms.

FOR THE MANAGEMENT :

- Sd/-
1. Shri K. V. Bhatt,
Asst. General Manager.
Sd/-
 2. Shri R. M. Muthalagappan,
Chief Officer,
Industrial Relations Deptt.
Sd/-
 3. Shri B. Jagadish,
Officer,
Industrial Relations Deptt.
Sd/-
 4. Shri R. L. Veerappan,
Officer,
Personnel Admn. Deptt.

Witnesses :

- Sd/-
1. Shri P. Muthukumar,
Officer, I.R. Deptt.
Sd/-
 2. Shri T. K. A. Khan Mohammed,
Deputy General Secretary.

FOR THE UNION :

Sd/-

1. Shri L. Balasubramanian,
President.
Sd/-
2. Shri K. Nagappan,
Vice-President.
Sd/-
3. Shri S. Srinivasan,
General Secretary (Ag).

ANNEXURE TO THE MEMORANDUM OF SETTLEMENT DATED 10.2.93

DETAILS OF TEMPORARY WATCHMEN
TRIVANDRUM REGION

Sl. No.	Name	Age	Date of regularisation
1.	Shri B. Krishnakutty	48 years	1-12-1990
2.	Shri G. Muralidharan	44 years	1-12-1990
3.	Shri N. Vijayakumar Nair	39 years	1-12-1990
4.	Shri Bhaskaran Nair	51 years	1-12-1990
5.	Shri G. Rajagopalan	44 years	1-12-1990
6.	Shri S. P. Aboubaker	43 years	1-12-1990
7.	Shri K. K. Rajendran	45 years	1-12-1990

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

का.आ.1082.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ोदा के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोटा के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3 मई, 1993 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/86/89-डी-2(ए)]

वो.के. वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1082.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Kota as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 3-5-1993.

[No. L-12011/86/89-D-2A]
V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

अनुबंध

न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण, कोटा

निर्देश प्रकरण क्रमांक : औ.न्या. (केन्द्रीय)-15/1990

दिनांक स्थापित : 25-7-90

प्रसंग : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का
आदेश क्रमांक एल-12011/86/89-डी-2(ए)

दिनांक 23-7-90

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मध्य

क्षेत्रीय सचिव, वी बैंक आफ बड़ोदा कर्मचारी यूनियन,
द्वारा बैंक आफ बड़ोदा गुमानपुरा, कोटा।

एवं

—प्रार्थी यूनियन

क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ोदा भालावाड़ रोड, कोटा

—प्रतिपक्षी नियोजक

उपस्थित

श्री जगदीश नारायण शर्मा, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी यूनियन की ओर से प्रतिनिधि :— श्री एन.के. जैन
प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से प्रतिनिधि :—

श्री एस.डी. मोहता

अधिनिर्णय दिनांक : 12 अप्रैल, 1993

अधिनिर्णय

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निम्न निर्देश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1)(घ) एवं उपधारा (2-क) के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया है :—

“Whether the action of the Bank of Baroda in considering the candidature of Shri Bhupendra Singh for the post of Special Assistant against a vacancy which arose on 1-3-1989 even though he applied for the post only on 23-3-89 is justified in terms of Provisions of para 7(2) of the Bipartite Settlements of 1984? If not, to what relief Shri R. C. Goyal, another candidate for post is entitled and from what date?”

2. निर्देश न्यायाधिकरण में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व पक्षकारों को सूचना भिजवाई गयी। तदुपरान्त दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये।

3. इस प्रकरण में आज श्रमिक यूनियन की ओर से क्षेत्रीय सचिव श्री एन.के. जैन व प्रतिपक्षी नियोजक की ओर से श्री एम.टी. मोहता प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। श्रमिक प्रतिनिधि श्री जैन ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चूंकि प्रतिपक्षी प्रबन्धक से उनका समझौता हो गया है इसलिए अब वे इस विवाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रतिपक्षी नियोजक प्रतिनिधि ने भी श्रमिक प्रतिनिधि के उक्त कथन पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। चूंकि दोनों पक्षों के मध्य समझौता सम्पन्न हो जाने से अब उनके मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद देख रहना नहीं पाया जाता है, अतः उक्त प्रकरण में इन परिस्थिति में “विवादरहित अधिनिर्णय” पारित किया जाता है।

इस अधिनिर्णय को भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भिजवाया जावे।

जगदीश नारायण शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

का.आ.1083.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4 मई, 1993 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/31/एफ/90-आईआर (सी-II)]

राजा लाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1083.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on 4-5-1993.

[No. L-22012/317/90-IR(C.II)]
RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
CUM LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 15 of 1993

In the matter of dispute between :

Additional General Secretary, Bhartiya Khadya Nigam
Karamchari Sangh, (North Zone) 14/79 Bhartiya
Khadya Nigam, Civil Lines, Kanpur.

AND

Senior Regional Manager, Bhartiya Khadya Nigam, 5-6
Habibullah Estate, Hazaratganj, Lucknow.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-22012/317/F/90. I.R. (C.II) dt. 4-2-1993, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.

"Whether the action of the Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Lucknow. In denying correct fixation of the wages w.e.f. 26-7-1976 is justified? If not, to what relief the workman is entitled and with what effect?"

2. In the case on 2-4-93, Additional General Secretary of the Unions which has raised the dispute moved an application alleged that there is now left no dispute between the parties as the management have fixed the pay of the workman. Sri Shamshad Ahmad, District Office, Kanpur. With the application the Additional General Secretary, enclosed the photostat copy of the office order dated 20-2-93 showing the fixation of pay w.e.f. 1-1-77.

3. In view of it the reference order has become infructuous.

4. The reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

का.आ.1084—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नक्रकोन्डा कोलियरी आफ ई.सी.एल. के प्रबन्धतन्त्र के संघर्ष नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-4-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/(394)/90-आईआर(सी-II)]

राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1084.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure, in the

Industrial dispute between the employers in relation to the management of Nakrakonda Colliery of E.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 27-4-1993.

[No. L-22012/(394)/90-IR(C.II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL.

Reference No. 11/91

PRESENT :

Shri N. K. Saha, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Nakrakonda Colliery of M/s. E.C. Ltd.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employers—Sri P. K. Das, Advocate.

For the Workman—Sri Bijoy Kumar, Advocate.

INDUSTRY : Coal.

STATE : West Bengal.

Dated, the 19th April, 1993.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012/(394), 90-IR(C.II) dated the 25th March, 1991.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Nakrakonda Colliery of M/s. E.C. Ltd., P.O. Laudona, Dist. Burdwan, in denying to refer Shri Ananda Mahanty, Underground Loader to the Age Determination Committee for assessment of his age due to glaring difference in appearance is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The case of the union in brief is that Shri Ananda Mahanty the concerned workman was appointed as underground loader under M/s. Eastern Coalfields Ltd., in August, 1972. He was issued identity card showing his date of birth as 15-1-39. Similarly his date of birth was recorded as 15-1-39 in Form B Register. In fact his year of birth is 1936 and not 1939 which will be apparent from the physical condition and appearance of the workman. The recording of age in the records of the management was not proper and valid. The workman raised dispute through union to refer his case to the Apex Medical Board for determination of his age due to glaring difference in appearance. But the management did not pay any heed to the request of the union.

The union raised a dispute. But the attempts of conciliation failed. The matter was sent to the Ministry of Labour, Govt. of India and ultimately the Ministry of Labour has sent the dispute to this Tribunal for adjudication.

3. In this case the management could not file any written statement. But Sri P. K. Das the learned Advocate for the management has urged that the date of birth of the concerned workman was correctly recorded in the records of the management. He was served with service excerpts but he did not raise any dispute. So the question of sending this workman to the Apex Medical Board for determination of his age does not arise.

4. In this case the claim of the union is that the year of birth of the concerned workman is 1936. In Form B Register and in the identity card the date of birth of the workman has been recorded as 15-1-39. The learned Lawyer for the union has urged before me that there is a glaring difference of 17 years. So this workman must be sent to the Apex Medical Board for determination of his age. The workman did not appear to pledge his oath. There is no iota of evidence to support the claim of the workman that his year of

birth is 1956. The Form B register of the management is a statutory register. This workman was appointed in service in 1975 long after nationalisation of the collieries. His date of birth was recorded as 15-1-39 in that register and also in the identity card issued to the workman. The onus is upon the union to show that there was wrong entry in the records of the management. But there is no such evidence. Admittedly the workman was served with service excerpts showing his date of birth as 15-1-1939. But he did not raise any objection at that time.

So considering all the facts and circumstances of the present case I find that the management was justified in denying to refer the concerned workman to Age Determination Committee for assessment of his age. So the workman is not entitled to any relief in this case.

This is my award.

N. K. SAHA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

का.आ.1085-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार केरला मिनरल एंड मेटल लि. चेवड़ा के प्रबन्धतन्त्र के के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण कोल्लम के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29/4/93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29011/15/91-आई.आर. (विबिघ)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1085.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Kollam as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Kerala Minerals and Metals Ltd. Chavara and their workmen, which was received by the Central Government on the 29-4-93.

[No. L-29011/15/91-IR(Misc)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, KOLLAM

(Dated, this the 19th day of April, 1993)

Present :

Sri C. N. Sasidharan, Industrial Tribunal.

IN

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 44/91
BETWEEN

The Managing Director, Kerala Minerals and Metals
Ltd. Chavara P.O., Dist. Quilon.
(By M/s. Menon & Menon, Advocate, Kochi)

AND

Sri U. Ullattil Unnian, Thazhathethil House, Tri-
kaderi P.O., (via) Ottappalam, Dist. Palghat.
(By Sri P. K. S. Rajeev, Advocate, Kollam)

AWARD

This industrial dispute has been referred for adjudication by the Government of India as per Order No. L-29011/15/91 IR(Misc.) dated 26-9-1991, for adjudicating the following issue.

"Whether the action on the part of the management M/s. Kerala Minerals and Metals Ltd., Chavara in

dismissing the services of Sri U. Unnian, Leading Fireman w.e.f. 4-5-1990 is legal and justifiable? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. The workman Sri Unnian has filed a detailed claim statement and his contentions are briefly as under : The workman was an Ex-serviceman and he was appointed as a leading fireman in the management company as per order dated 3-2-1986. He was confirmed in service only after two years, though as per the standing order he was to be confirmed after one year of his probation. On 12-6-1987 the workman placed a suggestion before the manager safety for the removal of grass and bushes which was disliked by the manager safety. The manager safety accordingly abused the workman, his wife and children with uncouth language. The workman complained against the manager safety and for that the manager safety and his associates were trying to trap the workman by any means. The associates of the manager safety addressed the wife of the workman to create problems in his family and the workman placed a complaint again to the Deputy General Manager. But there was no action. The workman was served with a letter dated 19-8-1988 by the Deputy General Manager alleging certain misconducts committed by the workman. These allegations were absolutely false and concocted. The workman submitted an explanation denying the allegations. The management again served a charge sheet on the workman dated 5-11-1988 containing false allegations. The workman submitted his explanations. The management ordered domestic enquiries regarding the allegations in the two charge sheets and one Sri Purushothaman Nair was appointed as the enquiry officer. The workman informed the enquiry officer that he was not co-operating with the enquiry proceedings as the rightful claim and request of the workman to include his grievances has been totally ignored by the management. Later the workman participated in the enquiry but he was not allowed to cross examine the witness or lead his evidence. The workman was denied reasonable opportunity which resulted denying natural justice to the workman. He was served with another chargesheet dated 10-2-1989 containing some other false allegations to which he has submitted his explanation. Sri Harceendran, the then Joint Manager of the management company, was appointed as the enquiry officer. In this enquiry also the workman was not allowed to cross examine witness of management or to give evidence. He was denied reasonable opportunity and request and submissions of the workman were rejected by the enquiry officer. In the meanwhile the workman was affected with rheumatic complaint and on medical advice he had taken leave on various occasions. On 14-4-1990 when he went to the company for duty his punching card was absent. However he was permitted to join duty later. But on 17-4-90 he was not permitted to do his duty without assigning any reason. The worker accordingly approached the High Court of Kerala and the High Court directed the management to allow him for joining his duties. But the management ignored the court order and dismissed him as per letter dated 4-5-1990 on the basis of three enquiry reports. The management has avoided the examination of fire officer who is just superior to the workman to victimise the worker on the basis of false and concocted allegations. The further statement is that he belongs to a poor family which consists of his wife and children and he was the only earning member of the family. The claim is for reinstatement in service with full backwages and all other benefits.

3. The contentions of management as per the written statement are briefly as under : The workman was working as a leading fireman. The post of manager safety is above the post of leading fireman and the leading fireman has to work under the control of manager safety. The management as per memo of charge dated 19-8-1988 raised charges such as throwing fire on the face of safety manager, using immoral and insulting language and threatening the safety manager, obstructing him from working, absconding himself without permission of the superior officer, submitting leave applications without mentioning the purpose contrary to the orders issued by the company, making false malicious statement against the manager safety etc. Since the explanation of the workman was not satisfactory the management ordered a domestic enquiry and appointed Sri Purushothaman Nair as the enquiry officer. The enquiry officer conducted a fair and proper enquiry and submitted his report dated 27-11-1988

holding that the charges levelled against the workman are proved. The management issued another charge memo of charges dated 5-11-1988 to the workman levelling the charges of entering safety manager's office and having noisy altercation with him, abusing the manager safety using the most obscene and derogative language in the presence of other employees, displaying his private parts towards the manager safety and engaging himself in vulgar, revolting and reprehensible actions with the connivance of the fire officer etc. Since the explanation of the workman was not satisfactory, the management ordered a domestic enquiry and Sri Purushothaman Nair was appointed as the enquiry officer. The enquiry officer conducted a fair and proper enquiry and submitted his report dated 27-11-88 finding the workman guilty of the charges. The management again issued a memo of charges dated 10-2-1989 to the workman levelling the charges of entering the office room of manager safety and beating him with chair, absenting from the work place during his working hours, and the workman spat at the face of manager safety. The explanation submitted by the workman was not satisfactory to the management and the management ordered a domestic enquiry and appointed Sri G. Hareendran as the enquiry officer. The enquiry officer submitted his report dated 17-2-1989 after conducting a fair and proper enquiry and holding that the charges levelled against the workman are proved. The management accepted the findings of the enquiry officers. Since the misconducts committed by the workman are very serious, the management has dismissed him from service. The probation of the workman was extended since his performance was unsatisfactory during the initial period of probation. The management denies all other allegations made against it by the workman. The reasons stated by the workman for non participation in the domestic enquiry are without any basis and contrary to facts. The workman was afforded reasonable opportunity in the domestic enquiries to establish his case. There was no direction from the High Court to allow the workman for joining his duties. According to the management the three enquiries were conducted fully in compliance with principles of natural justice and the findings of the enquiry officers are proper and valid. The further case of management is that the workman is not entitled to any relief.

4. Since the validity of the domestic enquiry was in serious dispute, that point was considered as a preliminary issue. On 29-1-1993 when one of the enquiry officers was present for examination the workman and his counsel remained absent without any reason whatsoever. No adjournment was also sought for on behalf of the workman. Therefore the workman was set ex-parte and the enquiry officer was examined as MW1. MW1 has proved the enquiry report submitted by him as Ext. M1. The other two enquiry reports submitted by Sri Purushothaman Nair were also proved through MW1 since Sri Purushothaman Nair expired. After the examination of the enquiry officer on 29-1-1993 there were two postings of this case before this Tribunal. On these days also the workman and his counsel failed to appear. Accordingly the counsel for the management was heard.

5. Ext. M1 is the enquiry file containing enquiry proceedings statement of witness, documents and the findings of the enquiry officer. MW1 has conducted the domestic enquiry regarding charges levelled against the workman as per memo of charges dated 10-2-1989. It is evident from Ext. M1 enquiry file that the workman did not participate in the enquiry though he was afforded reasonable opportunity to establish his case. Three witnesses have been examined on the side of the management and their statements regarding the charges levelled against the workman remained unchallenged. The enquiry officer has considered the statement of these three witnesses and came to his conclusion finding the workman guilty of the charges. The findings of the enquiry officer are fully supported by legal evidence. There are no reasons to hold that the enquiry was not conducted in compliance with principles of natural justice. I therefore hold that MW1 has conducted the domestic enquiry fully in compliance with principles of natural justice and his findings are proper and valid.

6. Exts. M2 and M3 are enquiry files regarding two domestic enquiries conducted by late Sri Purushothaman Nair. Ext. M2 the enquiry file regarding the charge memo dated 19-8-1988 issued to the workman and Ext. M3 is the

enquiry file regarding the charges as per memo issued to the workman dated 5-11-1988. It is evident from Ext. M2 and M3 files that the workman did not participate in the enquiries though he was afforded reasonable opportunities. Ext. M2 enquiry file shows that three witnesses were examined on the side of the management and these witnesses had given detailed statement of the charges levelled against the workman. The statement of these witnesses remained unchallenged. The impolite, obscene and derogatory language used by the workman towards the manager safety are stated in pages 7, 8, 18 and 19 of the Ext. M1. The enquiry officer considered the evidence of the three witnesses and the documents in detail and found the workman guilty of the charges as per charge memo dated 19-8-1988. On a perusal of Ext. M2 enquiry file it is clear that the enquiry was conducted in consonance of the principles of natural justice and the findings of the enquiry officer are supported by uncontroverted evidence of management.

7. Ext. M3 enquiry file is regarding the enquiry conducted by Sri Purushothaman Nair on the memo of charges dated 5-11-1988. It is evident from Ext. M3 file that the workman did not participate in the enquiry without any satisfactory reason though he was afforded reasonable opportunity to participate in the enquiry. Three witnesses were examined in the enquiry on the side of the management as recorded in pages 36, 37 and 38 of Ext. M3 file. The management witness, MW1 has stated the impolite, abusive and obscene words uttered by the workman towards the manager safety in the presence of others. MW2 and MW3 in the enquiry had also given detailed statement of the charges committed by the workman. The enquiry officer analysed the evidence of these three witnesses and came to the conclusion that the workman is guilty of the charges as per charge memo dated 5-11-1988. There are no reasons to hold that the enquiry was conducted not in compliance with principles of natural justice or the findings of the enquiry officer are not supported by evidence. The findings of the enquiry officer are not supported by evidence. The findings of the enquiry officer as per Ext. M3 file are proper, valid and supported by legal evidence.

8. The charges now proved against the workman are very serious and grave. The workman abused his superior officer in most filthy, obscene and vulgar language, entered the room of manager safety on several occasions and beat him with chair. He has displayed his private parts to the manager safety. The workman repeated certain misconducts which shows that there is no chance of any improvement in his bad habit. The punishment of dismissal imposed by the management is only proper and commensurate with the gravity of the misconducts committed by the workman. No management can give a lesser punishment to such a workman for the grave and serious misconduct committed by him. There are also no exenuating circumstances to interfere with the punishment of dismissal and to award a lesser punishment. The continuance of such a workman in the management company is not at all advisable.

9. In view of the above conclusion on award is passed holding that the dismissal of Sri Union from the service of management company is legal and justified.

C. N. SASIDHARAN, Industrial Tribunal

APPENDIX

Witness examined on the side of the Management

MW1 Sri G. Hareendran

Documents marked on the side of the Management

Ext. M1. File containing, enquiry proceedings, statement of witness, documents and findings of the enquiry officer regarding memo of charges dated 10-2-1989.

Ext. M2. File containing, enquiry proceedings, statement of witness, documents and findings of the enquiry officer regarding memo of charges dated 19-8-1988.

Ext. M3. File containing, enquiry proceedings, statement of witness, documents and findings of the enquiry officer regarding memo of charges dated 5-11-1988.

नई दिल्ली, 5 मई, 1993

का.आ. 1086.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धनत्व के संघर्ष नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या : एल-33012/1/89-आई.आर. (विविध)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, 5th May, 1993

S.O. 1086.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal MADRAS as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Madras Port Trust Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 3-5-1993.

[No. L. 33012/1/89-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,
TAMILNADU, MADRAS

Tuesday, the 29th day of December, 1992

PRESENT

Thiru M. GOPALASWAMY, B. Sc., B.L.,
INDUSTRIAL TRIBUNAL

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 55 OF 1989

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1) (d) of the Industrial disputes Act, 1947 between the workman and the management of Madras Port Trust, Madras-1]

Between

Thiru S. Vasudevan, Nadukuppam,
No. 23, 3rd Street, Llyods Road, Madras-600005.

AND

The Chairman,

Madras Port Trust, Rajaji Road, Madras-600001.

REFERENCE : Order No. L. 33012/1/89-IR
(Misc.), dated 12-6-89, Ministry of Labour, Govt.
of India, New Delhi.

This dispute coming for final hearing on Friday, the 4th day December, 1992, upon perusing the reference, claim and counter statements and all material papers on record and upon hearing arguments of Thiruvalargal R. Ganesan and R. Gow the mans, Advocates for workman and of Tyl. A. L. Somayaji and R. Arumugam, Advocates, appearing for the management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :

AWARD

This dispute between the workman and the management of Madras Port Trust, Madras-1 arises
1052 GI/92-12

out of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its order No. L. 33012/1/89-IR. (Misc.) dated 12-1-1989 of the Ministry of Labour, for adjudication of the following issue :

Whether the management of Madras Port Trust, Madras is justified in discharging Shri S. Vasudevan, Mazdoor No. 1677 from service vide order dated 11-6-1986. If not, what relief the concerned workman is entitled to?

The petitioner Vasudevan states as follows. —

When he was working as Mazdoor in the Madras Port Trust, Respondent herein, he was charged with the possession of foreign Nylon cloth of 46 Mtrs. hidden on his person on 28-1-84 when he was on medical leave. Under the 1st charge memo issued dt. 27-12-84 he was alleged to have committed misconduct under clause 42(C)(I) of the standing orders. The charge was then varied under 2nd notice dt. 29-3-85 as one falling under Cl. 42-A (IX) For the 3rd time under another memo dt. 18-5-85 the Respondent altered the charge as one under earlier clause 42(C)(I) and informed that a domestic enquiry would be conducted. The Petitioner has given a suitable reply stating that he purchased the cloth only from Burma Bazaar, that he did not get it from some one from the Ship 'Chidambaram' and he was not caught by CIPF Jawan near the ship. At the domestic enquiry a report was given that the charge has been proved. Then after the 2nd show cause notice was issued to the petitioner, the respondent has passed an order for discharging the petitioner from service. The petitioner has put in 25 years of clean service. The punishment of discharge is very harsh and excessive and the same is liable to be set aside. A suitable award may be passed.

The Respondent in his counter states as follows:-

The domestic enquiry has been held fairly and in accordance with the principles of natural justice. The evidence given by the witnesses has overwhelmingly proved the charge under Cl. 42 (C) (1). The petitioner has committed irregularities in the past and has been punished on 3 occasions. Punishment of discharge from service is quite adequate and proper. The petitioner has admitted his possession of foreign cloth before the officials of CISF and latter he also confessed the same before the customs collector who imposed a penalty of Rs. 400/-. The order passed by the customs Officer has become final. The claim is liable to be dismissed.

The points arising for determination are as follows:-

1. Whether the domestic enquiry officer's finding is correct?

2. Whether the punishment for discharge from service is harsh disproportionate and excessive?

Point 1 & 2 : The worker Vasudevan examined Suplt. S. Harimath as M.W1. Exhibits M.1 to M.13 have been marked. This Tribunal held earlier that the Domestic enquiry conducted by the Respondent has been done fairly and in accordance with the rules after giving opportunities to the petitioner

Now we have to consider the evidence before us including the evidence tendered before the domestic enquiry officer.

There is nothing wrong in the framing of charge under clause 42(C)(1), later altering it into a minor charge coming under 42-A (IX) and finally bringing it under Cl. 42(C) (1) for unlawful possession of foreign goods. At the domestic enquiry 1st witness (see page 15 of the typed set) Tapas Chakraborty who is a constable of CISF has deposed that he caught the petitioner Vasudevan near the gangway of a Ship M. V. Chidambaram in the place called North Quay, where the said ship was berthed on 28-11-84, that he found Vasudevan to be in possession of foreign cloth and hence he brought him to the Crime Branch and produced the delinquent before the Sub Inspector M. W1 who received the Special report at the station and recorded the F.I.R. M.W.2. Mr. B. P. Pande is the Head Constable who searched the person of the Delinquent Vasudevan, found the cloth kept concealed by the workman and directed him to be taken to M.W. 3 Sub Inspector of the Crime Branch. The latter has spoken to the registration of F.I.R. at the crime station on 28-11-84. The Crime Branch Officer later handed over Vasudevan on 28-11-84 itself to the Customs Department functioning in the harbour complex. M.W.4. Ganesan who is the preventive Officer of the customs and M.W.5. Cumban another preventive Officer have deposed to the action taken by the customs Department, confession statement given by the Delinquent Vasudevan and the order passed by the Customs Officer under which a fine of Rs. 400/- was levied from the delinquent Vasudevan. The evidence therefore is very convincing and cogent and enough to sustain the finding recorded by the domestic enquiry officer that the charge is proved.

The only other question is the quantum of punishment. The petitioner Vasudevan has served under the Respondent for nearly 22 years. His past record shows that he was once found guilty of irregular attendance for which one increment was postponed and on two other occasions he was absent from the work-spot without authorisation. There is no other act of serious misconduct in his past service. Coming into possession of foreign cloth within the harbour areas is a crime or misconduct, which cannot be said to be uncommon in that area. Cloth is an ordinary consumer item. The petitioner was in possession, near the ship M.V. Chidambaram is of dress material meant for women costing Rs. 1200/- The petitioner delinquent has confessed to his misconduct and paid a fine of Rs. 400/- to the customs authority. I believe that the punishment of discharge from service is a very serious one, ending the career of Vasudevan with disastrous consequences to his family. I therefore consider that the punishment of discharge under Ex. M 13 order is disproportionate and is liable to be set aside. Taking all the facts and circumstances, I think that the petitioner cannot be allowed to enjoy full back wages and that he must be content with 3/4th of back wages by losing 1/4th as a kind of punishment.

In the result an award is passed, directing the Respondent to reinstate the petitioner in service, pay him only 3/4th of back wages with continuity of service

and grant him all other attendant benefits. No costs.
Dated this day of Twenty-ninth December, 1992.

THIRU M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal.

WITNESSES EXAMINED

For Workman
MW1-Thiru S. Vasudevan.
For Management
MW1 - Thiru S. Harinath

DOCUMENTS MARKED

For workman-Nil.
For Management :
Ex. M1. 12-12-84—Complaint by the Management to the Inspector of Police Madras-1, against the petitioner-worker Thiru S. Vasudevan (MW1-) Xerox copy.
Ex. M2. 13-12-84—Letter from Asst. Collector of Customs, Madras-1 to the Management (Xerox copy)
M.3. 27-12-84—Charge memo issued to W.W.1. (Xerox copy)
Ex. M.4 16-1-85—Explanation by W.W1 to Ex. M.3 (Xerox copy)
Ex. M.5. 29-3-85—Charge memo issued to W.W.1. (Xerox copy)
Ex. M.6. 7-5-85—Reply by W.W.1. to Ex. M.5 (Xerox copy)
Ex. M.7 18-5-85—Show cause notice issued to W.W.1 (Xerox copy).
Ex. M.8. 20-8-85—Enquiry notice (Xerox copy)
Ex. M.9. — Proceedings of the Enquiry Officer-Xerox copy
M. 10. — Findings of the Enquiry Officer —do—
M.11. — Service sheet of W.W. 1. (Xerox copy)
M.12. 29-3-86. Second show cause notice —do—
M.13. 11-6-86. Order of discharge —do—

नई दिल्ली 5 मई, 1993

का. आ. 1087.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, ग्रहमदाबाव के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5/5/93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल—30012/42/91—आई आर विविध]

बी एम डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1993

S.O. 1087.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Ahmedabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Oil & Natural Gas Commission and their workmen, which was received by the Central Government on the 5-5-93).

[No. L-30012/42/91-IR (MISC)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI H. R. KAMODIA, INDUSTRIAL
TRIBUNAL, A'BAD.

Ref. (ITC) No. 12 of 1992

ADJUDICATION

BETWEEN

O.N.G.C., Project, Ahmedabad.

AND

The workmen employed under it.

In the matter of promotion of Shri I. R. Kumar, Sampler for the post of Gauger as per R&P Regulations 1974 with all consequential benefits.

Appearances :

Shri K. V. Gadhia, Advocate, for the first party.

Shri Surendra Walter, representative for the second party.

AWARD

An industrial dispute between the above-named parties has been referred for adjudication u/s 10(1) of the I. D. Act, 1947 by the Desk Officer, Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi vide his Order No. L-30012-42-91-IR (Misc.) dated 30-6-92 to the Industrial Tribunal at Ahmedabad. By a subsequent order it has been transferred to this Tribunal for adjudication.

2. The exact terms of reference are as under :

"Whether the action of the ONGC Management through Regional Director, Baroda and others in non-promoting Shri I. R. Kumar (S/C) Sampler for the post of 'Gauger' after completion of 3 yrs. functional experience as per provisions of ONGC, R & P Regulations, 1974, was legal, proper or justified? If not to what relief Shri I. R. Kumar is entitled to and from what date and what directions are necessary in the matter."

3. Today the concerned workman has appeared before this Court. He has submitted an application Ex. 5 praying that he withdraws this application. He is identified by Shri K. V. Gadhia, learned advocate for the first party. There is no objection against the grant of this prayer and so as desired by him I pass the following order.

1652 GI/93—13

ORDER

As per the desire of the concerned workman expressed in Ex. 15 he is permitted to withdraw this reference, with the result that it will stand dismissed with no order as to cost.

H. R. KAMODIA, Industrial Tribunal

SECRETARY,
Ahmedabad, 4th March, '93.

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

का.ग्रा. 1088.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल टसर रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 42012/19/92-आई आर
(डी यू) पार्ट]
बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1088.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Taser Research & Training Institute and their workmen which was received by the Central Government on 4-5-93.

[No. L-42012/19/92-IR (DU) (PI)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDI-
GARH

Case No. J.D. 13/93

Raj Kumar Vs. Central Taser Research &
Training Instt.

For the workman: Workman in person

For the management : Shri R. K. Goel.

AWARD

Central Govt. vide gazette notification No. L-42012/19/92-IR (UD) dated 18th January 1993 issued U/r 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of Assistant Director
Central Taser Research & Training Instt.,

Research Extension Centre, Central Silk Board, in terminating the service of Shri Raj Kumar son of Panu Ram w.e.f. 31-8-1991 is justified? If not, what relief he is entitled to?"

2. The petitioner workman has made statement that he has been given regular appointment by the respdt. and he does not want to pursue with the present reference and no dispute award be returned to the Ministry. Ex. W1 is the application.

In view of the statement made by Raj Kumar that he has been given regular appointment and has made application to this effect which is Ex. W1 and that he does not want to pursue with the present reference. Thus no dispute award is returned to the Ministry.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

Candigarh.
Camp at Palampur
12-4-1993

सेवा में,

श्रीमान सचिव, केन्द्रीय सरकार (उद्योग),
ट्री ब्यूनल—कम लेबर कोर्ट चण्डीगढ़

केस संख्या—वर्कमैन—राज कुमार बनाम सैल सिल्क बोर्ड
विषय:—केस सम्बन्धी समझौता होनेके सम्बन्ध में
महोदय,

उपरोक्त संवर्ग एवं विषय के अन्तर्गत महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि मेरा मैनेजमेंट सेंट्रल टसर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट के साथ समझौता हो गया है तथा मैं विभाग में कार्यरत हूं अतः उक्त केस को वापस लेना चाहता हूं ताकि आगे की कार्यवाही समाप्त हो जायें।

निवेदक

राजकुमार

केन्द्रीय रेशम दांड

शाखा द्रमण शाहपुर पो—द्रमण
कांगड़ा (हि. प्रा.)

नई दिल्ली, 7 मई, 93

का. आ. 1089.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सेंट्रल टसर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट के प्रबन्धतंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल—42012/21/92—आई आर (डी यू)/(पाटी)]

बी० एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1089.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Tasar Research of Trg. Instt. and their workmen, which was received by the Central Government on 4-5-93.

[No. L-42012/21/92-IR(DU)(PL.)]

B. M. DEVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. 1. D. 15/93

Harish Chand: Vs. Central Tasar Research & Training Instt

For the workman: Workman in person.

For the management: Shri R. K. Goel.

AWARD

Central Govt. vide gazette notification No. L-42912/21/92-I.R.(UD) dated 18th January, 1993 issued U/S 10(1)(d) of the I. D. Act 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of Asstt| Director, Central Tasar Research & Training Instt, Research Extension Centre, Central Silk Board in terminating the services of Shri Harish Chand son of Shri Roop Chand w.e.f. 31-8-1991 is justified? If not, what relief he is entitled to?"

2. The petitioner workman has made statement that he has been given regular appointment by the respdt. and he does not want to pursue with the present reference and no dispute award be returned to the Ministry. Ex. W1 is the application.

In view of the statement made by Shri Harish Chand that he has been given regular appointment and has made application to to this effect which is Ex. W1 and that he does not what to pursue with the present reference. Thus no dispute award is returned to the Ministry.

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

Chandigarh.

Camp at Palampur

12- 4-1993

सेवा में, श्री मात सचिव,
केन्द्रीय सरकार (उद्योग)
ट्रिब्यूनल-कम-लेबर कोर्ट,
चंडीगढ़

संदर्भ संख्या 42012/21--92 आई आर (डी.यू.)

केस संख्या--15/93 वर्कमैन-हरीश चन्द्र बनाम
सेंट्रल टसर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट
विषयः--केस सम्बन्धी समझौता होने के
सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ एवं विषय के अन्तर्गत महोदय को सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा मैनेजमेंट सेंट्रल टसर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के साथ समझौता हो गया है तथा मैं विभाग में कार्य-रत हूँ। अतः उक्त केस संख्या 15/93 को वापस लेना चाहता हूँ ताकि आगे की कार्यवाही समाप्त हो जाए।

निवेदक

हरीश चन्द्र

सुपुत्र श्री रूपचन्द्र

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

शाखा दमण

शाहपुर पो. दमण

(कांगड़ा हि. प्र.)

176223

नई दिल्ली 7 मई, 1993

वा. आ. 1090.— औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल टसर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-5-93 को प्राप्त हुआ था

[संख्या एल-42012/18/92-आई आर
डी.यू. (पार्टे)]

बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1090.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Tasar Research & Trg. Instt. and their workmen, which was received by the Central Government on 4-5-93.

[No. L-42012/18/92-IR(DU) (Ptd.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR, PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDI-
GARH

Case No. I. D. 20/93

Jagdish Chand: Vs. Central Tasar Research &
training Institute.

For the workman: Workman in person.

For the management: Shri R. K. Goel.

AWARD

Central Govt. vide gazette notification No. L-42012/18/92 I. R. (DU) dated 18th of January 1993 issue U/S 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of Assistant Director, Central Tasar Research & Training Instt. Research Extension Centre Central Silk Board in terminating the services of Shri Jagdish Chand w.e.f. 31-8-1991 is justified? If not, what relief he is entitled to?"

2. Mr. R. K. Goel Asstt. Director appearing on behalf of the management states that present case has been settled amicably. The management had agreed to reinstate the petitioner w.e.f. 31-8-1991. The petitioner shall be given regular appointment in the year 1994 on completion of his five years service. However, the petitioner shall not be paid any back wages otherwise the previous period shall be considered for all purposes minus back wages. The petitioner can report on duty on 13-4-1993 at 8-30 AM at Palampur.

Jagdish Chand workman has also made statement that the above said statement is acceptable to him.

In view of the statement made by the respective parties, the workman is directed to report for duty at Palampur on 13-4-1993 at 8-30 AM. The management is also directed to comply the settlement in its letter and spirit. No dispute Award is returned to the Ministry.

Chandigarh
Camp at Palampur
12-4-1993

ARVIND KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मई, 93

का. आ. 1091. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस. डी. ओ. (टेलीग्राफ) मुल्तानपुर के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल- 40012/192/92-आई आर (डी यू) (पी)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1091.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S. D. O. (Telegraph) Sultanpur and their workman, which was received by the Central Government on 4-5-93.

[No. L-42012/192/91-IR(DU)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM - LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR.

Industrial Dispute No. 121 of 1992

In the matter of dispute between

Sri Swami Nath Mishra Putra Sri Aditya Shankar Mishra, Nivasi Gram Sarai P.O. Saifabad, Distt. Pratagarh.

AND

The Divisional Engineer
(Telegraph)
Sultanpur.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-40012/192/91-I.R. (DU) dated 30-9-92, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Kya S.D.O. (Telegraph) Sultanpur dwara Sri Swaminath Mishra putra Sri Sri Aditya Mishra ko dinank 1-5-89 se naukari se alag karna urchit avam vaidh hai. Yadi nahi to karamchhari kis rahat ko pane ka haqdar hai?

2. In this case dates 17-11-92, 17-12-92, 16-2-93 were allowed to the workman for filing of the claim statement. Finally when the case was taken up on 20-4-93, neither the workman appeared nor he filed his statement of claim. It therore, appears that the workman is not interested in prosecuting his case.

In the circumstances of the case a no claim award is given against the Union.

4. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मई, 93

का. आ. 1092.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार चीफ जनरल मैनेजर, टेलीकाम लखनऊ के प्रबन्धतांत से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचपट

को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-40011/25/89-आई आर (सी यू)/(पीटी)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1092.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chief General Manager, Telecom, Lucknow and their workman, which was received by the Central Government on 4-5-93.

[No. L-40011/25/89-IR(DU)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM - LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR.

AWARD

Industrial Dispute No. 113 of 1992

In the matter of dispute between :

The Circle Secretary
All India P&T Industrial Workers Union
2/3 P&T Colony Alambagh
Lucknow.

AND

The Chief General Manager
Telecommunication
U. P. Circle Lucknow.

AWARD

1. The Central Government Ministry of Labour vide its notification No. L-40011/25/89, I.R.D.U. dt. 9-9-92 has referred the following dispute for adjudication of this Tribunal.

“Whether the Chief General Manager Telecom U. P. Circle Lucknow was justified in not regularising Sri Subir Kumar Dass and 18 others as per the list enclosed in terms of clause 10 of the Certified Standing Orders? If not, what relief the workmen concerned are entitled to?

2. In this case reference order from the Ministry of Labour New Delhi was received in the office of the Tribunal on 14-9-92, whereupon notices to the parties were issued on 25-9-92 for filing the statement of claim in the case by 2-11-92. After 2-11-92, dates 28-12-92 and 16-2-93 were allowed for filing the claim statement to the workman. Finally when the case was taken on 11-3-93 for hearing even by then no statement of claim was filed on behalf of Union. Thus from the above facts and circumstances of the case it appears to the that neither the

Union nor its workmen are interested in prosecuting the case.

3. Therefore, for the reasons given above a no claim award is given against the Union.

4. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

का. ग्रा. 1093.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस. डी. ओ. (टेलीग्राफ), सुल्तानपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/146/90 डी 2(बी) (पीटी)]
बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1093.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S. D. O. (Telegraph) Sultanpur and their workmen, which was received by the Central Government on 4-5-93.

[No. L-40012/146/90-D.II(B) (Pt.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 53 of the 1992
In the matter of dispute between :

Sri Girja Shanker Singh
s/o Sri Jagdish Singh
c/o Sri S. D. Srivastava
16 M G Marg Allahabad

AND

The Divisional Engineer
Telegraph
Sultanpur.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/146/90-D. 2(B)

dated 6-3-92, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Kya SDO (Telegraph) Sultanpur द्वारा श्री Girja Shanker Singh putra श्री Jagdish Singh को दिनांक 26-3-89, से नौकरी से अलग करना उचित अवाम वैद है? यदि-नहीं तो कर्मचारी किस राहत को पाने का हकदार है ?

2. In this case despite issue of notice neither the workman appeared nor filed his claim statement. The case is pending for want of statement of claim on behalf of the workman from 19-5-92.

3. Finally when the case was taken up for hearing on 20-4-93, on that date too neither the workman appeared nor he filed his claim statement. Sri N. N. Duvdi appeared for the management. It therefore, appears to me that the workman is not interested in prosecuting his case.

4. Therefore, in view of the facts and circumstances of the case, a no claim award is given against the workman.

5. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

का.ग्रा. 1094.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस डी ओ (टेलीग्राफ) सुल्तानपुर के प्रबन्ध तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-40012/152/91-डी II-बी (पीटी)]
बी एम डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1094.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S. D. O. (Telegraph), Sultanpur and their workmen, which was received by the Central Government on 4-5-93.

[No. L-40012/152/91-D.II(B) (Pt.)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI-
BUNAI.-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR,
KANPUR

Industrial Dispute No. 56 of 1992

In the matter of dispute between :

Sri Om Prakash
s/o Sri Gurudin
C/o Sri S. D. Srivastava
16, M.G. Marg, Allahabad.

AND

The Divisional Engineer (Telegraph)
Sultanpur.

AWARD :

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-40012/152/91-D. 2(B) dated 6-3-92 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Kya S. D. O. (Telegraph) Sultanpur dwara Sri Om Prakash son of Sri Gurudin ko dinank 1-4-89 se naukari se alag karna uchit avam vaid hai ? Yadi nahi to karam-chari kis rahat ko pane ka haqdar hai ?

2. In this case despite issue of repeated notices to the workman neither the workman appeared nor he filed statement of claim in support of his case. First date for filing of the statement of claim was 19-5-1992 and then the case is pending for one ground or the other. Finally when the case was taken up for hearing on 19-4-93 on that date too none appeared for the workman and the claim statement too was not filed.

3. It therefore appears that the workman is not interested in prosecuting the case any more. Therefore, in the circumstances of the case, a no claim award is given against the workman.

4. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मई, 1993

का. आ. 1095—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार दक्षिण रेलवे के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-5-93 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-41012/141/89—आई आर (डी यू.) (पीटी)]

बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1993

S.O. 1095.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Southern Railway and their workmen, which was received by the Central Government on 3-5-93.

[No. L-41012/141/89-IR (DU) (Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL
TAMILNADU, MADRAS

Tuesday, the 29th day of December, 1992

Present :—

THIRU M. GOPALASWAMY, B.Sc., B.L.,
INDUSTRIAL TRIBUNAL.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 76 OF 1990

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10 (i) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Southern Railway, Madras-3).

Between

Thiru C. V. Devarajan,
No. 3, Elumalai Street, Ayanavaram,
Madras-600 023.

AND

The Dy. Chief Mechanical Engineer, Carriage Works,
Southern Railway, Perambur, Madras-600 023.

REFERENCE : Order No. L. 41012/141/89-IR (DU), dated 18-9-1990, Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Tuesday, the 25th day of August, 1992, upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru G. Justin, Advocate appearing for the workman and of Thiru R. Venugopalan, Advocate for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following

AWARD

This dispute between the workman and the management of Southern Railway, Madras-23 arises out of a reference under section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its order No. L. 41012/141/89 IR (DU) dated 18-9-90 of the Ministry of Labour, for adjudication of the following issue ;

Whether the action of the management of Southern Railway is justified in terminating the services of Shri C. V. Devarajan, fitter, CR-240, If not, what relief the concerned workman is entitled to ?

Petitioner states as follows :—

When he was working as a Mechanical Fitter under the 2nd Respondent, he was issued a charge memo alleging that he committed theft of 1.450 Gms. of Brass value at Rs. 20/- at 11.20 A.M. on 14-6-75 and that he was caught red handed when coming out of the workshop. He has given a suitable reply denying the charge. A domestic enquiry was held in which principles of natural justice were not followed and due opportunities were not given. The enquiry officer himself acted as Prosecutor and put roving questions to petitioner. The domestic Enquiry Officer failed to examine defence witnesses. The management refused to permit the assistance of a lawyer to the petitioner in conducting the enquiry. He was not

furnished with copies of enquiry proceedings before the time of issuing penalty advice. The production Manager who has passed the dismissal order has no authority to do so. The nature of the offence does not call for the extreme punishment which is highly disproportionate. The past record of service of petitioner has not been considered. Award may be passed setting aside the punishment and granting reliefs, including reinstatement.

The Respondents 1 and 2 in their counter state as follows :—The petitioner was caught red handed when he was passing through guard room gate with a parcel of brass pieces hidden in his body. He himself gave a confession statement voluntarily in his own handwriting to the Inspector of Railway Protection force. A recovery memo was duly prepared and signed by the petitioner. Illegal possession of Railway property is a serious offence. At the domestic enquiry, several adjournments were given to suit the petitioner's convenience. Opportunities were given to him and all the rules were followed. He had in fact received copy of the proceedings on 11-8-76 long before the despatch of penalty advice. To the 2nd show cause notice, the petitioner has given a reply on 17-11-76, pleading for mercy. Deputy Chief Mechanical Engineer, who dismissed the petitioner from service is a competent authority to order such punishment. The order of removal or dismissal was not passed by the Production Engineer. The petitioner has unsuccessfully raised the dispute over the removal from service in the City Civil Court, Madras, in the High Court, Madras and in the Central Administrative Tribunal, Madras. Everywhere he has failed. There is no merit in the claim petition and the same is liable to be dismissed.

Points for consideration :

1. Whether the domestic enquiry has been conducted fairly and in accordance with the rules and principles of natural justice ?

2. Whether the findings are correct ?

3. Whether the punishment is adequate ?

The petitioner-workman Devarajan examined himself as W.W1. The respondent did not give any oral evidence. Ex. W. 1 to W.7 and Ex. M1 to M. 19 have been marked.

Points 1 to 3 :

The charge levelled against the petitioner when he was working as a Mechanical fitter under the 11th Respondent (Perambur Railway Carriage works) is that he stealthily carried a parcel of brass pieces valued at Rs. 25 by concealing it in his waist on 14-6-75. Rakshak S. S. Karuppuswamy, a member of the Protection force, caught him red handed and made over him to Abdul Majeed, Head time-keeper. A recovery mahazar relating to seizure of the stolen property from the petitioner was prepared in the form of Ex. M. 1 by Mohanam. The superior Officer i.e. Inspector Narayanan has prepared a complaint about the incident and forwarded it to his superior. It is marked as Ex. M.2. The charge memo Ex. W.1, was duly served upon the petitioner. In the reply Ex. W.2 the petitioner flatly denied the charge alleging that he had only argued with the chargeman who was behaving indecently towards him, that he was

hauled up by the chargeman to the Sub-Inspector's room and that a false complaint of theft was framed against him. The Deputy Chief Mechanical Engineer has ordered a domestic enquiry as evidenced by Ex. M.4. The petitioner was given defence assistance of co-worker Mr. Velu. At first the domestic enquiry was conducted by one Sethuraman and later Mr. Rathinaswamy was appointed as domestic enquiry Officer out of necessity. The enquiry report given by Rathnaswamy is Ex. M. 13. A reading of this report shows to us that the petitioner has taken several adjournments and that the Enquiry Officer was forced to take the evidence of 5 Management witnesses on 29-1-76 in the absence of the accused. Finally at the adjourned date the petitioner wanted to cross examine M.W. 2 Mohanram and he was accordingly allowed to do so. The findings given by the Domestic enquiry officer which are based upon the voluntary confession given by petitioner Delinquent and the evidence of MW1. Karuppuswamy Kakshak MW2, Mohanaram and other MWs is quite correct and convincing. All opportunities have been given to the Delinquent for conducting his defence. From the perusal of the records and on a scrutiny of the evidence of the M.W.'s given before this Tribunal I have no doubt that the enquiry has been conducted fairly and that the findings are sustainable. In the evidence of WW1 he has stated that he has given confession statement only out of fear. This interested explanation is most hollow.

On the question of punishment, the charge being one of theft of public property, there is no ground and reason for showing any mercy and considering any modification of punishment. I therefore hold that the petitioner is not entitled any relief. All the points are answered accordingly. In the result an award is passed dismissing the claim. No cost.

Dated this day of 29th December, 1992.

THIRU M. GOPALASWAMY, Presiding Officer

WITNESSES EXAMINED

For workman
WW1—Thiru C. V. Devarajan
For Management: None

DOCUMENTS MARKED

For workman
Ex. W.1, 30-7-75- Charge sheet issued to the Petitioner workman Thiru C. V. Devarajan (xerox copy)
W.2.-16/18-8-75- Explanation by the petitioner-workmen to Ex. W.1, xerox copy.
W. 3. 12-11-76—Show cause notice issued to the petitioner workman—Xerox copy.
W. 4. 17-11-76—Explanation by the petitioner-workman to Ex. W. 3-xerox copy.
W. 5. 1-12-76—penalty advice issued to the petitioner workman xerox copy
W. 6. 28-12-76—Appeal preferred by WW1, xerox copy.
W. 7. 14-6-75—confessional statement of WW1—do—

For Management

- Ex. M. 1. 14-6-75—Recovery Memo by Thiru O. P. Mohanan (xerox copy)
- Ex. M. 2. 14-6-75—Letter from Inspector, Railway protection force to Dy. CME|CW|PER (xerox copy)
- M. 3. 1-9-75.—Order of Dy. Chief Mechanical Engineer-relating to appointment of Enquiry Officer-xerox copy.
- M. 4. 5-9-75.—Letter from the Enquiry Officer to WW1 to Submit the name of defence helper-xerox copy.
- M. 5. 12-11-75 —Nomination of defence helper by WW1 and consent letter of defence helper-xerox copy.
- M. 6. 12-11-75.—Letter from WW1 to the Enquiry Officer requesting permission for persusal of records (xerox copy)
- M. 7. 14-11-75—Letter from Enquiry Officer to WW1 permitting persusal of records.
- M. 8. 21-11-75.—Acknowledgement for having received Ex. M. 7 by WW1-xerox copy
- M. 9. 24-1-76.—Consent letter of defence helper Thiru T. A. Krishnan xerox copy
- M. 10. 28-1-76.—Report of enquiry officer-
- M. 11. 12-5-76.—Order of disciplinary authority relating to nomination of another enquiry officer Thiru B. Muthusawamy-xerox copy.
- M. 12. 11-8-76.—Acknowledgement of WW1 for having recieved the enquiry proceedings containing 1 to 32 pages-xerox copy
8. 13. 18-9-76.—Report of the enquiry Officer-xerox copy.
- M. 14. 26-4-78.—Letter from Asst. Personnel Officer (Discipline & Appeal) communicating the order of General Manager, Southern Railway disposing the representation of WW1 dt. 27-3-78-xerox copy.
- M. 15. 3-11-86.—order of Central Administrative Tribunal Madras in T. A. No. 803|86-xerox copy.
- M. 16. 27-11-86.—letter from Law Officer
- M. 17. 10-12-78 18-1-88.—order of High Court of Judicature at Madras in WP. No. 12324|87 (xerox copy).
- M. 18. 2-9-88—order of Central Administrative Tribunal, Madras in W. P. No. 12324|87-xerox copy.
- M. 19. 26-9-89|3-10-89.—Conciliation failure report-xerox copy.

Industrial Tribunal